सूर्योदय 6.09 सूर्यास्त 6:18

आज का तापमान

शिमला	16.0 न्यू	25.0 अधि
धर्मशाला	19.8 न्यू	30.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,859
निफ्टी	23,414

सोना 1,53,000 चांदी 2,35,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 6 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 148, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

कनाडा में विमान हादसे में 2 भारतीय छात्रों की मौत

एजेंसी, ओटावा। कनाडा में 18 सितंबर को एक प्लेन क्रैश में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। इसकी जानकारी भारतीय दूतावास ने सोमवार को दी। यह हादसा फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान हुआ। इससे पहले कनाडाई न्यूज चैनल सीबीसी ने शनिवार को इस घटना की रिपोर्टिंग की थी। इसमें बताया गया था कि सस्केचेवान प्रांत में एक विमान हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, जब विमान समय पर लैंड नहीं हुआ, तो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद करीब 8 घंटे बाद विमान का मलबा मिला।

दिल्ली में 10 साल की बच्ची से रेप

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के सदर बाजार में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घटना 16 सितंबर की रात हुई। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची रात करीब 11 बजे नोटबुक, पेन सहित स्टेशनरी का सामान खरीदने घर से निकली थी। आरोप है कि दुकानदार उसे बहला-फुसलाकर पास की दुकान में ले गया। वहां बच्ची का हाथ-पैर बांधकर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 56 साल के मकसूद के रूप में हुई है। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना औसतन 3 नाबालिगों का यौन शोषण होता है। हालांकि, 2025 की एनसीआरबी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

ममता की नई पार्टी का लोगो लॉन्च

एजेंसी, कोलकाता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने सोमवार को नया लोगो जारी कर दिया। इसमें अंतरिम चुनाव चिह्न के तौर पर फुटबॉल खिलाड़ी बना है। लोगो के बीच में फुटबॉल खिलाड़ी है। इसके चारों ओर नीले बैकग्राउंड पर सफेद रंग में 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' लिखा है। डिजाइन में केसरिया, सफेद और हरे रंग भी शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग ने फिलहाल पार्टी का पुराना नाम और सिंबल फ्रीज कर दिया है। आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए हैं। ममता गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और अरूप रॉय वाले विरोधी गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम, लिफाफे का सिंबल दिया गया है।

रूसी संसदीय चुनाव में पुतिन समर्थक पार्टी जीती

एजेंसी, मास्को। रूस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समर्थक यूनाइटेड रशिया पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। शुरुआती नतीजों में पार्टी ने 57.5% वोट के साथ अजेय बढ़त बना ली है। चुनाव के आधिकारिक नतीजे अभी आने बाकी हैं। यह फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहला संसदीय चुनाव है। पुतिन ने चुनाव को यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों के समर्थन से जोड़कर पेश किया था। 2021 के पिछले संसदीय चुनाव में यूनाइटेड रशिया ने स्टेट ड्यूमा की 450 में से 324 सीटें जीती थीं। स्टेट ड्यूमा रूस की संसद का निचला सदन है। इसमें कुल 450 सीटें हैं। इनमें 225 सीटें पार्टी को मिले वोट के आधार पर और 225 सीटें अलग-अलग क्षेत्रों में सीधे चुनाव से तय होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी बोली– राम मंदिर में 105 बार हुई चढ़ावा चोरी

सभी घटनाएं सीसीटीवी में रिकॉर्ड; दो दिन के भीतर एसआईटी दाखिल करेगी चार्जशीट

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावा चोरी की 70 नहीं, 105 घटनाएं कैद हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को जांच की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच कर आरोपियों की पहचान की है। चढ़ावे और कीमती सामान की रसीदें सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार होती हैं और सामान एसबीआई के लॉकर में रखा जाता है। कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। इससे पहले 23 जून को पहली एसआईटी ने अपनी प्राइमरी जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं कैद हुई थीं। फुटेज में पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते हुए दिखे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरी एसआईटी बनाई गई है, जो जांच कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि एसआईटी 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानून के मुताबिक चार्जशीट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे देने से इनकार कर दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह मामले को सेशन जज के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं करना चाहती।

गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो एक्शन गैरकानूनी कहलाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है और जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस सीधे उसे नहीं पकड़ सकती। इसके लिए पहले मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। दोबारा गिरफ्तारी की स्थिति में मामले की आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी।

एशियन गेम्स में भारत को अब तक 6 मेडल: 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज

एजेंसी, नगोया। भारत ने जापान के नगोया में चल रहे एशियन गेम्स के दूसरे दिन 4 मेडल जीते। इनमें से 3 मेडल शूटर्स ने दिलाए। जबकि, एक मिक्स्ड मार्शल आर्टस में आया।

सोमवार को मेंस 10 मीटर राइफल के इंडिविजुअल्स इवेंट में हिमांशु ढिल्लों (252.4 अंक) को सिल्वर और रुद्रांश पाटिल (230.9 अंक) को ब्रॉन्ज मिला। चीन के शेंग लिहाओ (254.2 अंक) ने गोल्ड जीता। टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर जीता। पार्थ माने, रुद्रांक्ष पाटिल और हिमांशु ढिल्लों वाली टीम 1890.1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन (1899.9 अंक) पहले और कोरिया (1884.2 अंक) तीसरे स्थान पर रहे। इस बीच सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्टस के विवादित मुकाबले में ब्रॉन्ज हासिल किया। यह इस खेल में एशियाड का पहला मेडल भी है। इंडिया को महिला हॉकी और कबड्डी में भी जीत मिली। लेकिन, टेबल टेनिस में भारत की दोनों टीमों ने पाकिस्तान को हराया। खास बात यह रही कि पाकिस्तानी खिलाड़ी एक भी गेम नहीं जीत सके।

भारत 12वें स्थान पर पहुंचा, चीन नंबर-1

भारत एशियन गेम्स की मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। उसके खाते में अब 4 सिल्वर समेत 6 मेडल हैं। चीन 23 गोल्ड समेत 38 मेडल लेकर पहले स्थान पर है। जापान 8 गोल्ड समेत 32 मेडल के साथ दूसरे और साउथ कोरिया 5 गोल्ड समेत 23 मेडल के सहारे तीसरे स्थान पर है।

सोनिया के वोटर विवाद में कोर्ट ने फैसला पलटा नए सिरे से होगी सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर्स केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक साल पुराना फैसला पलट दिया। दरअसल 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट ने सोनिया के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के चलते एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिका एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दाखिल की थी।

आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। शिकायत में कहा गया कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। आरोप था कि यह दोबारा दर्ज किया जाना भी 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल करने से पहले हुआ था।

टैंकों के लिए 586 करोड़ की डील: टी-72 और टी-90 में लगेंगे स्वदेशी एपीयू

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 586 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है।

इस करार के तहत इन दोनों टैंकों के लिए स्वदेशी ऑक्जिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू खरीदे जाएंगे। एपीयू टैंक की कई अहम प्रणालियों को बिजली उपलब्ध कराने का काम करता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, स्वदेशी एपीयू को शामिल करने से सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की तैयारियों, विश्वसनीयता और लंबे समय तक संचालन की क्षमता को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह अनुबंध किया। करार पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। इसके तहत टी-72 और टी-90 टैंकों में स्वदेशी रूप से विकसित एपीयू लगाए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार, यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्म से जुड़े महत्वपूर्ण सिस्टम के स्वदेशीकरण की दिशा में एक अहम कदम है। इसके साथ ही यह मेक-II के तहत उद्योग के नेतृत्व में किए गए शोध और विकास को उत्पादन और सेना में शामिल करने की प्रक्रिया की सफलता को भी दिखाता है। एपीयू टैंक में बिजली पैदा करने का एक वैकल्पिक स्रोत है। इसका इस्तेमाल फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट और गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए किया जाता है।

सीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

शिकायतें कागजों तक सीमित न रहे: धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पेंशन, रोजगार और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले मुख्यमंत्री के सामने रखे।

सीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिला या विभागीय स्तर पर हो सकता है, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को अपने स्तर पर जनसमस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सरकारी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन-1905, जनसुनवाई और 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा रहा है। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' के तहत शासन-प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने के साथ पात्र लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ रहा है।

17 अक्तूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

धामी ने बताया कि 17 सितंबर से शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान 17 अक्तूबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 'सेवा सेतु अभियान' के तहत जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविरों के साथ स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

नशे की सप्लाई पर प्रहार से उपचार तक पांच मोर्चों पर काम कर रही मान सरकार

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए मान सरकार द्वारा 5 बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें सरकार का दावा है कि उनके द्वारा नशे की सप्लाई से लेकर इससे पीड़ित लोगों को इलाज तक पहुंचाया जा रहा है।

वहीं, सरकार का दावा है कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में चलाया जा रहा युद्ध नशेआं विरुद्ध अभियान अब केवल पारंपरिक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के खिलाफ पांच सूत्रीय व्यापक रणनीति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत पुलिस, शिक्षक, सामुदायिक स्वयंसेवक, युवा और स्वास्थ्यकर्मी मिलकर नशे की आपूर्ति के नेटवर्क पर प्रहार करने, नशे की रोकथाम करने, सूचना तंत्र को मजबूत करने और नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि संदेश स्पष्ट है कि पंजाब नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस थानों से नहीं लड़ेगा। यह लड़ाई अब गांवों, स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच रही है,

जहां पुलिस नशे की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करने और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं सामुदायिक प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत कर रहे हैं। शिक्षक नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही जोखिम की पहचान करने में मदद कर रहे हैं, जबकि युवा किशोरों और युवाओं के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता, मानसिक दृढ़ता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को उपचार की राह उपलब्ध करवा रहे हैं।

◆ गांव, स्कूल व कॉलेजों तक पहुंचेगा नशा विरोधी अभियान

नशे के खिलाफ लड़ाई नशा पीड़ितों से नहीं सौदागरों से हो: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को सीतो, फाजिल्का में आयोजित नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गुरुओं की धरती से शुरू होने वाली यह यात्रा पंजाब को बचाने की जन यात्रा है।

सैनी ने कहा कि पंजाब की पहचान प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 'कीरत करो, नाम जपो, वंड छको' के संदेश से है। उन्होंने पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चार साल बाद भी नशा गांव-गांव तक कैसे पहुंच रहा है। सैनी ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को सिर्फ नारे नहीं, बल्कि नशे से मुक्ति, इलाज, रोजगार और सम्मान की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे की तस्करी और ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में देशभर में ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की दर्ज 305 घटनाओं में से 298 पंजाब सीमा से संबंधित थीं। वहीं, एनसीआरबी के वर्ष 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग ओवरडोज से 106 मौतें दर्ज हुईं।

◆ कहा- पंजाब के युवाओं को नारे नहीं, नशे से मुक्ति और रोजगार चाहिए

सीएम सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई नशा पीड़ितों से नहीं, बल्कि नशे के सौदागरों से है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर नशा पीड़ितों को इलाज, परिवारों को सहयोग और तस्करों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैनी ने कहा कि हरियाणा में हर महीने नशे के खिलाफ अभियान आयोजित किए जाते हैं और 'नशा मुक्त हरियाणा' अभियान को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाया गया है।

राज ठाकरे के खिलाफ रील बनाने वाले को कालिख पोती

एजेंसी, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में राज ठाकरे पर टिप्पणी वाली रील के मामले में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर महेश मोटे से माफी मंगवाई। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने उनका चेहरा काली स्याही से पोता और

राज ठाकरे की तस्वीर के सामने दंडवत करवाया। उनके सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक भी कराई गईं। घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें वे हाथ जोड़कर राज ठाकरे, एमएनएस और पार्टी पदाधिकारियों से बिना शर्त माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वे रोते हुए आगे ऐसी गलती नहीं करने और उन्हें परेशान नहीं करने की अपील करते हैं।

जनता दर्शन: 'छोटी घटनाएं बड़ी न बनें', लोगों की समस्याएं सुन योगी बोले- डीएम-एसपी नजर रखें

एजेंसी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में लोगों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान विभिन्न जिलों से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करके सीएम ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग मामूली घटनाओं को बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे में जिलों में हर छोटी से छोटी घटना पर डीएम-एसपी नजर रखें। घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सुनवाई करें। दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। चेतावनी दी कि छोटी-छोटी घटनाओं में भी उदासीनता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 'जनता दर्शन' में सीएम योगी हर पीड़ित से मिले। उनकी समस्याओं

व शिकायतों को सुना। प्रशासन, पुलिस, राजस्व, बिजली आदि से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने कहा कि अधिकारी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाएं। मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराएं। भूमाफिया/दबंगों पर कठोरतम कार्रवाई करें। सीएम के समक्ष पुलिस व राजस्व से जुड़ीं शिकायतें अधिक रहीं। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी नियमित रूप से जनसमस्याओं का निराकरण कराएं। यदि किसी मातहत द्वारा लापरवाही की शिकायत मिले तो उस पर भी कार्रवाई करें। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए दिल्ली में पंजीकरण शुरू

◆ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 'डबल इंजन' सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'यह बहुत खुशी का पल है और इसे दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, जिसका सीधा लाभ दिल्लीवासियों को मिलेगा। जहां पिछली सरकारें मुफ्त की राजनीति करती रहीं, वहीं वर्तमान सरकार विकास की राजनीति करती है। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दिल्ली में हरित ऊर्जा पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।' उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल लगाने की पूरी लागत वहन करेगी। उपभोक्ता को एक रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चलेगी।

आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सुसाइड केस में प्रोफेसर सस्पेंड

एजेंसी, मुंबई। आईआईटी बॉम्बे ने बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की मौत मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला को डीन पद से सस्पेंड कर दिया है। वहीं, संस्थान ने साहिल की मौत को लेकर पहले कही गईं अपनी बातों के लिए माफी भी मांगी है। कहा कि साहिल की मौत से पहले क्या हुआ था, इसकी जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना सही नहीं था। साहिल आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। 18 सितंबर की रात वे पवई कैंपस स्थित हॉस्टल के कमरे में मृत मिले थे। आईआईटी बॉम्बे ने अपने बयान में कहा था कि घटना वाले दिन साहिल को मिड-सेमेस्टर एग्जाम में फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। संस्थान ने दावा किया था साहिल ने चैटजीपीटी पर क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की कोशिश की। फिर हॉस्टल जाकर सुसाइड कर लिया।

घोषणा — मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

क्लास-3 पेंशनर्स को 30, क्लास-1 व 2 को 15 % पेंशन एरियर मिलेगा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-3 पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत, जबकि क्लास-1 और क्लास-2 पेंशनरों को उनके पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत एरियर इस वर्ष अक्तूबर माह में प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है तथा इनके समाधान के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है और आने वाले समय में महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनर्स के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों का एरियर सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। सुक्खू ने कहा कि पेंशनर्स ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने 77 वर्षों से मिल रहे इस अधिकार को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरडीजी केवल प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि एक लाख रुपए की वार्षिक आय में से 40,000 रुपए काट लिए जाएं, तो क्या स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश आज इसी स्थिति का सामना कर रहा है। प्रदेश को हर वर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी तथा 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा होता, तो प्रदेश का कर्ज लगभग 30,000 करोड़ रुपए कम किया जा सकता था और कर्मचारियों से संबंधित देनदारियां भी चुकाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से भवनों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कई भवन वर्तमान में खाली पड़े हैं जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछले तीन वर्षों में 17,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में प्राप्त हुए हैं और सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है।

किशाऊ बांध परियोजना पर राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा

युवाओं को नशे से बचाने के साथ उपचार सुविधाएं बढ़ाने की बनाई गई योजना

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर परियोजना के वित्तीय प्रावधानों और हिमाचल के जल अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को परियोजना से जुड़े वित्तीय, जल और बिजली संबंधी प्रावधानों को सार्वजनिक करना चाहिए तथा प्रदेश के दीर्घकालिक हितों पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए।

किशाऊ परियोजना की अनुमानित लागत 15,624 करोड़ रुपये है। 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश समेत छह राज्यों ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार के अनुसार जल घटक की करीब 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष वित्तीय भार संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। परियोजना से 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। बिंदल ने कहा कि परियोजना में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है और समझौते को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार का योगदान रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार परियोजना की उपलब्धियों का श्रेय ले रही है, जबकि हिमाचल के हिस्से के जल और बिजली संबंधी प्रावधानों पर जनता को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है।

हालांकि, केंद्र की ओर से जारी जानकारी के अनुसार हिमाचल के हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान के लिए आवंटित करने पर सहमति बनी है और इसके बदले हिमाचल के बिजली घटक की लागत साझा करने की व्यवस्था की गई है। बिंदल ने हिमाचल के संभावित जल अधिकारों को लेकर सवाल उठाते हुए

◆किशाऊ बांध समझौते पर सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग करते डॉ. राजीव बिंदल

कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि समझौते के बाद प्रदेश को कितना पानी मिलेगा और भविष्य में राज्य की सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए क्या व्यवस्था होगी। उपलब्ध परियोजना दस्तावेज में हिमाचल के लिए करीब 42 मिलियन घन मीटर जल लाभ का उल्लेख है, जबकि अंतिम वितरण 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते और नए समझौते के प्रावधानों के अधीन रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें परियोजना से हिमाचल को लगभग 1,200 करोड़ रुपये सालाना आय होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार हिमाचल को परियोजना से 211 मेगावाट बिजली बिना उत्पादन लागत वहन किए मिलने की व्यवस्था हुई है।

बिंदल ने कहा कि सरकार को बिजली की मात्रा, बिक्री दर, उत्पादन लागत और वास्तविक शुद्ध आय का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। बिंदल ने सिरमौर के किसानों की सिंचाई, स्थानीय युवाओं के रोजगार और परियोजना से जुड़े कारोबार के अवसरों पर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के हितों और स्थानीय भागीदारी को लेकर स्पष्ट नीति सामने आनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि किशाऊ परियोजना के समझौते की वित्तीय शर्तें, जल अधिकार, बिजली हिस्सेदारी, अनुमानित आय, सिंचाई लाभ और रोजगार संबंधी प्रावधानों का विस्तृत विवरण जनता के सामने रखा जाए।

हिमाचल सचिवालय में फाइलों की थमी रफ्तार 80 प्रतिशत मामले पहुंच रहे बिना सिफारिश

फाइलों पर 'फॉर कंसीडरेशन' लिखकर भेजने से सचिवालय में बढ़ा काम का इंतजार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में फाइलों को लेकर 'फॉर कंसीडरेशन' और 'फॉर रिकमेंडेशन' के बीच नया शब्दयुद्ध शुरू हो गया है। सरकारी विभागों और निदेशालयों से सचिवालय पहुंचने वाली बड़ी संख्या में फाइलों पर 'फॉर कंसीडरेशन' यानी विचारार्थ लिखा जा रहा है। सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य तौर पर 100 में से करीब 80 फाइलें बिना स्पष्ट सिफारिश के पहुंच रही हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और कई मामलों में 15 दिन में पूरा होने वाला काम तीन महीने तक खिंच रहा है।

सचिवालय स्तर पर अधिकारियों का तर्क है कि जिन मामलों में विभाग और निदेशालय नियमों के अनुसार जांच और औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं, उनमें स्पष्ट सिफारिश के साथ फाइल भेजी जानी चाहिए। इसके बजाय यदि फाइल पर केवल 'फॉर कंसीडरेशन' लिखकर भेजा जाता है तो सचिवालय स्तर पर दोबारा पूरे मामले की समीक्षा करनी पड़ती है। अधिकारियों का कहना है कि विभागों को अपने स्तर पर परीक्षण के बाद यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी है या नहीं। हाल ही में उद्योग विभाग के खनन विंग से जुड़ी एक फाइल सचिवालय पहुंची। फाइल में संबंधित दस्तावेज और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी थीं। इसके बावजूद नोटिंग के अंत में 'फॉर कंसीडरेशन' लिखा गया था। इस पर सचिवालय स्तर पर सवाल उठाया गया कि जब मामला नियमों के अनुरूप है और दस्तावेज पूरे हैं तो विभाग की ओर से स्वीकृति की स्पष्ट सिफारिश क्यों नहीं की गई।

अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की फाइलों में सचिवालय को निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण या दोबारा सिफारिश मंगवानी पड़ती है। इससे फाइल एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के बजाय वापस लौटती है और प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसका सीधा असर विभागीय कामकाज और लंबित मामलों के निपटारे पर पड़ रहा है। सचिवालय में चर्चा यह भी है कि कुछ मामलों में अधिकारी सीधे सिफारिश करने के बजाय 'विचारार्थ' लिखकर जिम्मेदारी आगे बढ़ा रहे हैं। सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है तो उसकी स्थिति और अनुशंसा स्पष्ट होनी चाहिए। केवल विचार के लिए फाइल भेजने से निर्णय की जिम्मेदारी सचिवालय पर आ जाती है।

फाइलों के इस आदान-प्रदान के बीच अब 'फॉर कंसीडरेशन' बनाम 'फॉर रिकमेंडेशन' का मुद्दा प्रशासनिक कामकाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यदि फाइलों में विभागीय स्तर पर स्पष्ट सिफारिश दी जाए तो अनावश्यक पत्राचार और देरी को कम किया जा सकता है। जिससे सचिवालय में फाइलों के निपटारे की गति बढ़ेगी और विभागों के बीच अनावश्यक पत्राचार भी कम होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट सिफारिश पर जोर दिया।

हिमाचल में एमआइएस सेब खरीद पर सवाल, 20 करोड़ रुपए के घपले की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। चंबा और मंडी समेत कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बागवानों से वास्तव में जितना सेब खरीदा गया, रिकॉर्ड में उससे कहीं अधिक मात्रा दर्ज कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी खरीद के लिए बनाए गए दस्तावेजों में वास्तविक आपूर्ति और दर्ज मात्रा के बीच बड़ा अंतर है। इससे एमआइएस के तहत होने वाली खरीद प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

मामले में संबंधित क्षेत्रों के उपमंडल अधिकारियों से जांच करवाई गई। जांच के दौरान कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आने की बात कही गई है, जिनमें बागवानों की वास्तविक आपूर्ति से अधिक सेब की मात्रा दर्ज है। सैकड़ों मामलों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड, खरीद से संबंधित दस्तावेजों और बागवानों से मिली जानकारी के आधार पर मामलों की जांच की है। एमआइएस के तहत सरकारी एजेंसियों की ओर से बागवानों से सेब की खरीद की जाती है।

इसका उद्देश्य बाजार में उचित मूल्य न मिलने की स्थिति में बागवानों को राहत देना है। आरोप है कि इसी व्यवस्था में कुछ एजेंटों ने रिकॉर्ड में वास्तविक खरीद से अधिक मात्रा दर्ज कर दी। यदि जांच में यह अंतर सही पाया जाता है तो इससे सरकारी धन के भुगतान और खरीद प्रक्रिया दोनों पर असर पड़ सकता है। जांच में सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है।

करीब 20 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतिम नुकसान और जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। शिमला के अलावा चंबा, मंडी और अन्य जिलों में भी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में वास्तविक खरीद और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर मिला है, उनमें संबंधित एजेंटों और प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल जरूरी है।

11 से 20 अक्तूबर तक आयोजित होगा ज्वालामुखी आश्विन नवरात्र मेला

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, ज्वालामुखी। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 11 से 20 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर न्यास के स्वागत कक्ष में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त (मंदिर) एवं एसडीएम ज्वालामुखी ने की। स्थानीय विधायक संजय रत्न ने विशेष रूप से भाग लेकर विभिन्न विभागों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। विधायक ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। स्वच्छता व्यवस्था के लिए 60 सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने तथा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 75 होमगार्ड जवानों की मांग करने का निर्णय लिया गया। मंदिर परिसर में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित एंबुलेंस उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए।

मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने और लंगर में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया। श्रद्धालुओं को बेहतर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मेन्यू में आवश्यकतानुसार बदलाव करने पर भी जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत उपयुक्त स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और करीब 85 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंदिर परिसर में प्रतिबंधित एवं अनावश्यक वस्तुओं के प्रवेश पर रोक तथा प्रभावी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी कर मेले को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने का भरोसा दिलाया।

108 देवी देवताओं की उपस्थिति में साई बाबा के प्रति सामूहिक कृतज्ञता का अर्पण

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव पर सत्य साई सेवा संगठन हिमाचल प्रदेश मंडी के पडडल मैदान में हिमाचल के 108 देवी देवताओं की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक देव समागम का आयोजन करने जा रहा है। 26 और 27 सितंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समूचे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब 20,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। प्रेम प्रवाहिनी के रूप में एक रथ यात्रा पिछले वर्ष 24 अप्रैल 2025 को साई धाम पुट्टापर्थी से समूचे भारत के लिए निकली थी। पूरे भारत में सबसे अधिक 152 दिन इस रथ यात्रा का हिमाचल में प्रवास होने के चलते सत्य साई सेवा संगठन हिमाचल प्रदेश हिमाचल के 108 देवी देवताओं की उपस्थिति में साई बाबा का आभार प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 100 साई सेवा समितियां के हजारों लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। सत्य साई सेवा संगठन हिमाचल प्रदेश की मानें तो इतना बड़ा विशाल सम्मेलन हिमाचल में पहली बार होने जा रहा है जिसमें सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाने वाले तथा मानवता के प्रति साई बाबा के निस्वार्थ कार्यों के चलते हिमाचल के हजारों हाथों के कृतज्ञता स्वरुप उठने की उम्मीद है। नगाड़ों, वेद मंत्रों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच होने वाला यह आयोजन हिमाचल की देव संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अनूठा संगम होगा।

हिमाचल में इलाज महंगा, सिरिंज से दवाओं तक मनमाने दाम वसूलने के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सरकार की बीमा योजना के तहत बड़े इलाज की सुविधा बंद होने से सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पतालों में कई जरूरी दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध न होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को इन्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। इससे उपचार का कुल खर्च बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति अधिक परेशानी वाली साबित हो रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों की ओर से लिखी गई दवाओं और जरूरी चिकित्सा सामग्री बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है। निजी दवा दुकानों पर कई बार इनकी कीमतें काफी अधिक बताई जाती हैं। अस्पताल के आसपास स्थित दुकानों पर मरीजों की निर्भरता अधिक होने के कारण उन्हें मजबूरी में सामान खरीदना पड़ता है। शिमला के अलावा ठियोग, रामपुर, रोहड़ू, सुन्नी और कुमारसैन जैसे क्षेत्रों से भी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं।

सीएम कार्यालय खर्च पर सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल

सुधीर शर्मा ने कहा, कार्यालय के लिए 50 करोड़, कैंपस निर्माण के लिए 20 करोड़ की कमी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नए कार्यालय को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने नए कार्यालय के निर्माण और उस पर होने वाले खर्च को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से खर्च की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सचिवालय के नए अलर्जली फेज-2 भवन में कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार नए भवन की लागत 20 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि विपक्ष की ओर से निर्माण और अन्य कार्यों को मिलाकर खर्च करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने तंज के अंदाज में मुख्यमंत्री को नए कार्यालय के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के कार्यालय पर इतनी बड़ी राशि खर्च किए जाने का उदाहरण नहीं रहा है।

उन्होंने सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे समय में खर्च की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। भाजपा विधायक ने सेंटर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए

करीब 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि शिक्षा और विकास से जुड़े संस्थानों के लिए धन की कमी क्यों बताई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण और सुविधाओं पर इतनी बड़ी राशि

◆सुधीर शर्मा ने नए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण पर सरकार से मांगा जवाब

खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। सुधीर शर्मा ने नए कार्यालय में लगाए गए फर्नीचर को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि कार्यालय में लगाए गए कुछ सोफों की कीमत छह से सात लाख रुपये प्रति सोफा बताई जा रही है और इनके बाकायदा बिल भी बनाए गए हैं। इन दावों पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग भी उन्होंने की। नए कार्यालय को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि यह केवल मुख्यमंत्री का निजी कार्यालय नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा है।

कुक हेल्पर और स्टीवर्ड के पदों के लिए 24 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 24 सितंबर को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन प्रात: 11 बजे त्रिमूर्ति पाइन वैली होटल, नालदेहरा, शिमला में किया जाएगा। इस दौरान कुक हेल्पर और स्टीवर्ड के एक-एक पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि कुक हेल्पर और स्टीवर्ड दोनों पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोनों पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि कुक हेल्पर पद पर चयनित उम्मीदवार को 13 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके साथ उम्मीदवार को भोजन और आवास की

◆रोजगार कार्यालय शिमला की पहल से होटल क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा रोजगार

सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

वहीं, स्टीवर्ड पद के लिए चयनित उम्मीदवार को 12 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोजगार कार्यालय ने योग्य युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिन युवाओं का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, वे रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ बायोडाटा लेकर निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर पहुंचना होगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब कसेगा शिकंजा, 25 हजार तक जुर्माना

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरा वस्तुओं के खिलाफ अब कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकृत पर्यावरण अधिकारियों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक से जुड़े मामलों में निरीक्षण और कार्रवाई के अधिकार दे दिए हैं। इससे अब विभाग के अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग और बिक्री की जांच कर सकेंगे।

अब तक प्लास्टिक से जुड़े मामलों में कार्रवाई का अधिकार मुख्य रूप से राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के पास था। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए अन्य विभागों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए आदेश के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

सरकार के आदेश के अनुसार अधिकृत पर्यावरण अधिकारी प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल, भंडारण या बिक्री की जांच के लिए संबंधित स्थान पर प्रवेश कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिनियम और निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

आयुषदिवस आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम में होंगे विभिन्न आयोजन

शिमला में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय आयुष दिवस कार्यक्रम – यादविंदर गोमा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। आयुर्वेद को बढ़ावा देने और लोगों को आयुष पद्धति से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आयुष दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हिमाचल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर यादविंद्र गोमा को आयुष मंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आयुष मंत्री ने बताया कि आयुष दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न सेवाओं, उपचार पद्धतियों और विभागीय योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना है। राज्यभर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में भी

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाने और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयुष विभाग की ओर से 'हिम औषधम' की शुरुआत भी की जाएगी। इसके तहत आयुर्वेदिक औषधियों को बाजार में उपलब्ध करवाने की योजना है। विभाग का मानना है कि इससे लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही, इससे आयुष विभाग के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत तैयार करने में भी मदद मिलेगी। विभाग प्रदेश में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के साथ-साथ वेलनेस और पंचकर्म केंद्रों को विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

गोमा ने बताया कि हिमाचल में आयुर्वेद एम्स स्थापित करने को लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एम्स की स्थापना से प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा, उपचार सुविधाओं और इससे जुड़े संस्थानों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत ढांचे के विस्तार की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।

तीन देशों के अध्ययन प्रवास पर विधानसभा अध्यक्ष पठानियां

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के समापन के बाद निर्धारित कार्यक्रम के तहत इटली, फिनलैंड और नार्वे के अध्ययन प्रवास पर हैं। अध्ययन प्रवास के पहले चरण में वह शनिवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। दो दिन के प्रवास के बाद पठानियां रेल मार्ग से वेनिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वेनिस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया।

वेनिस अपनी नहरों, गोंडोला की सवारी और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। पठानियां ने वेनिस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने समुदाय के सदस्यों और स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन स्थलों और यहां उपलब्ध पर्यटन अवसरों की जानकारी साझा की। इसके बाद पठानियां रेल मार्ग से वेनिस से मिलान के लिए रवाना हुए। वह 21 और 22 सितंबर को मिलान में प्रवास करेंगे। इसके बाद अध्ययन प्रवास के अगले चरण में फिनलैंड और नार्वे जाएंगे।

उत्तराखंड में 89 मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरु

देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग में पंजीकरण नहीं कराने वाले 89 मदरसों को बंद करने की शासन से सिफारिश की है। मदरसों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है और समयसीमा नजदीक आने के साथ प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण के अनुसार, जिन मदरसों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया है, उनके संचालन को अवैध मानते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराने वाले मदरसों की 22 प्रकार की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेश में चिन्हित 452 मदरसों में से अब तक 34 को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन संस्थानों को प्रमाण पत्र दिए हैं। इसके अलावा 200 मदरसों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। दूसरी ओर, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में संचालित 21 अवैध मदरसों को शासन पहले ही सील कर चुका है।

सतपाल महाराज का 75वां जन्मदिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया

हरिद्वार में सतपाल महाराज का जन्मदिन, राज्यपाल और सीएम भी हुए शामिल

अनिल थपलियाल

हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का 75वां जन्मदिन श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के अन्य मंत्री और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने पहुंचकर सतपाल महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भारतेंदु शिखर संस्थान के राज्य प्रमुख अनिल थपलियाल ने भी पुष्प भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की।

जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही सतपाल महाराज के आवास पर शुभचिंतकों और समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर को प्रदेशभर में सेवा दिवस के रूप में भी मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित करने के साथ ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम भी किए गए।

आयोजनों में लोगों ने सतपाल महाराज के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को याद किया। उनके समर्थकों ने कहा कि सेवा और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों के माध्यम से उन्होंने लोगों को लगातार प्रेरित किया है। मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का संदेश देश-विदेश तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

◆ **75वें जन्मदिन पर सतपाल महाराज के आवास पर लगा शुभचिंतकों का तांता**

वहीं, प्रदेश सरकार में पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े कार्यों के माध्यम से विकास को गति देने में उनके योगदान को भी कार्यक्रम में रेखांकित किया गया। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धा और सेवा भावना का विशेष रूप से प्रदर्शन देखने को मिला। समर्थकों ने सतपाल महाराज के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके सामाजिक, आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन में निरंतर सक्रिय रहने की शुभकामनाएं दीं।

250 किमी पैदल सफर के बाद सुतोल पहुंची नंदा देवी की बड़ी जात यात्रा

अनिल थपलियाल

थराली। श्री नंदादेवी लोकजात यात्रा 2026 हिमपर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित पंचगंगा के होमकुंड में बड़ी पूजा संपन्न करने के बाद वापसी के दूसरे पड़ाव सुतोल गांव पहुंच गई है। सोमवार को दशोली, बंड और ज्वालपा की नंदा देवी की डोलियों और छंतोलियों के साथ यात्रा 18वें आबादी वाले पड़ाव सुतोल पहुंची। यहां देव डोलियों और यात्रियों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। रात्रि प्रवास के दौरान पूरी रात देवी जागरण का आयोजन होगा।

होमकुंड में बड़ी पूजा और खाडुओं की कैलाश विदाई के बाद रविवार को बड़ीजात यात्रा 17वें और चौथे निर्जन पड़ाव जामुन डाली पहुंची थी। सोमवार सुबह यहां पूजा-अर्चना के बाद नंदा देवी के जयकारों के बीच यात्रा सुतोल के लिए रवाना हुई। घने जंगलों से होकर यात्रा तातड़ पहुंची, जहां ध्योंसिंह देवता की पूजा-अर्चना की गई। कुछ देर विश्राम के बाद यात्रा आगे बढ़ी और शाम को सुतोल पहुंची। करीब 250 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। होमकुंड में पूजा संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में यात्री अपने घरों को लौटने लगे हैं।

मंगलवार को बड़ीजात यात्रा 19वें पड़ाव के तहत विभिन्न गांवों से होते हुए फरखेत पहुंचेगी, जहां देव डोलियों और यात्रियों का रात्रि प्रवास होगा। उधर, बधाण की श्री नंदादेवी राजराजेश्वरी की उत्सव डोली भी देवराड़ा स्थित नंदा सिद्धपीठ लौटने के क्रम में चौथे पड़ाव बेराधार पहुंच गई है। तीसरे पड़ाव उलंग्रा से रवाना होकर डोली हाट कल्याणी, इच्छोली और अठ्ठू गांवों से होते हुए बेराधार पहुंची। रास्ते में ग्रामीणों ने देव डोली का भव्य स्वागत किया। मंगलवार को डोली सिरमथल होते हुए थराली ब्लॉक के टुंड्री और फिर गोठिंड़ा गांव पहुंचेगी।

बागेश्वर के खजान सिंह टंगड़िया का उत्तराखंड हॉकी टीम में चयन

भारतेंदु संवाददाता, बागेश्वर

बागेश्वर जिले के खजान सिंह टंगड़िया ने अपनी मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर हाकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन 16वीं हाकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की सीनियर टीम में हुआ है। हल्द्वानी में आयोजित प्रदेश स्तरीय चयन ट्रायल में खजान ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी जगह बनाई। उनके चयन की जानकारी मिलते ही परिवार, खेल साथियों और क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।

खजान के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि सीनियर टीम के चयन ट्रायल में वह इससे पहले दो बार असफल हो चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार अभ्यास करते रहे। तीसरे प्रयास में उन्होंने अपने खेल में सुधार करते हुए चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और उत्तराखंड की टीम में स्थान हासिल किया।

खजान की इस उपलब्धि को उनके परिवार और प्रशिक्षकों की मेहनत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शुरुआती दौर में खेल को लेकर रुचि रखने वाले खजान ने नियमित प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत के जरिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाया। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उन्हें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

देहरादून में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति फरार

विकास बलोनी

देहरादून। देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। सुबह करीब छह बजे कंट्रोल रूम को धीरज पंवार नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन लगातार बंद मिला। तत्पश्चात टीम बनाकर उक्त कॉलर के कॉल करने के स्थान की जानकारी कर वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो एक प्लॉट के अंदर बने कमरे में खोलने पर एक महिला काजल पत्नी धीरज पवार उम्र 26 वर्ष निवासी ईदगाह रोड, सुभाष नगर, सत्य साइ मंदिर के पास, थाना क्लेमेंट टाउन मूल निवासी ग्राम मेघा सकरपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर मृत पाई गई। मौके पर गोली लगने से उक्त महिला की मृत्यु होना प्रकाश में आया।

क्षेत्राधिकारी सदर, देहरादून

मृतका उक्त स्थान पर अपने पति धीरज पवार पुत्र सुशील पवार निवासी ग्राम मेघा शकरपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के साथ रह रही थी। उपरोक्त मकान के बगल में मृतका का भाई अभिषेक पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम चांचक थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर भी निवास कर रहा था। मृतका के भाई द्वारा मौके पर बताया गया की कई दिनों से उसकी बहन और जीजा का विवाद चल रहा था। मौके पर पुलिस तथा फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

घटना के संबंध में मृतका के भाई द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना क्लेमेनटाउन पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतका के पति की तलाश में हेतु अलग-अलग टीमों का गठन का गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

मजबूत गांवों से समृद्ध बनेगा उत्तराखंडः धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत एम-पैक्स से गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है और मजबूत गांवों से समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण होगा। उन्होंने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रभावी माध्यम बताते हुए किसानों, युवाओं और मातृशक्ति को सहकारिता से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और गांवों से पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।

मसूरी झड़ीपानी में रेलवे भूमि विवाद को लेकर 31 मकानों पर नोटिस चस्पा

◆ **संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश के बाद उत्तर रेलवे की टीम पहुंची, भारी पुलिस बल रहा तैनात**

सुनील सोनकर

मसूरी। झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर उत्तर रेलवे ने सोमवार को कार्रवाई तेज कर दी। संपदा अधिकारी की अदालत से बेदखली आदेश जारी होने के बाद उत्तर रेलवे के अधिकारी रेलवे पुलिस और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने रेलवे की भूमि पर बने 31 मकानों पर नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई के दौरान मसूरी कोतवाल नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तैनात रही और विरोध की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

रेलवे के अनुसार झड़ीपानी स्थित ओक ग्रोव स्कूल के समीप करीब 100 वर्ग मीटर भूमि पर जगमोहन उर्फ सांझ कैफे पुत्र दर्शन लाल द्वारा अनधिकृत कब्जे का मामला सामने आया था। इस पर लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। संपदा अधिकारी की अदालत ने रेलवे की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और पक्ष को देखने के बाद कब्जे को अनधिकृत माना। आदेश में प्रतिवादी को 15 दिन के भीतर भूमि खाली कर रेलवे को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर रेलवे को नियमानुसार बलपूर्वक बेदखली और कार्रवाई का खर्च वसूलने का अधिकार दिया गया है।

रेलवे ने अपने दावे के समर्थन में 21 अप्रैल 1886, 28 दिसंबर 1895 तथा वर्ष 1920-21 के पुराने विक्रय अभिलेखों का हवाला दिया है। वहीं प्रतिवादी पक्ष ने वर्ष 1940 के सीमांकन, राजस्व विभाग की रिपोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं का उल्लेख किया। रेलवे का कहना है कि हाई कोर्ट ने पूर्व में नोटिस संबंधी कार्रवाई प्रक्रिया के आधार पर निरस्त की थी, लेकिन कानून के अनुसार नई कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी।

स्थानीय लोगों ने रेलवे की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं और भूमि खरीदकर मकान बनाए हैं। उनका दावा है कि नगर पालिका में दाखिल-खारिज भी दर्ज है। उन्होंने रेलवे से संपत्ति संबंधी दस्तावेज दिखाने की मांग की है और कहा कि वे सक्षम न्यायालय में मामला उठाएंगे। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर आशु शर्मा ने बताया कि नोटिस संपदा अधिकारी के आदेश के अनुपालन में लगाए गए हैं और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी।

डीएम नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार में सुनीं 70 से अधिक शिकायतें

अनिल थपलियाल

नई टिहरी। सोमवार को जिला सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें जनपदवासियों की पेयजल, ग्राम पंचायत, विद्युत, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 से अधिक शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए समाधान हो चुके मामलों को तत्काल पोर्टल पर अद्यतन करने को कहा।

ग्राम पंचायत तिवाड़गांव-मरोड़ा की प्रधान पिंकी पंवार ने टिहरी झील में डूब चुकी ग्राम सभा की 16 नाली भूमि के समतुल्य भूमि आवंटित करने की मांग रखी। इस पर प्रभारी अधिकारी पुनर्वास को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। व्यापारियों ने नव निर्मित सार्वजनिक शौचालय पर ताला लगे होने की शिकायत की, जिस पर एडीबी के परियोजना प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोरदी में शिक्षकों की कमी और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज शिलारी में कला व राजनीतिक विज्ञान के प्रवक्ता के रिक्त पदों का मामला भी उठाया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया। ग्राम ओखला निवासी गंभीर सिंह रावत ने सड़क निर्माण से मकान को खतरे की शिकायत की, जिस पर लोक निर्माण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर घटनास्थल का डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

विकास बलोनी

देहरादून। मोहब्बेवाला क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारतेन्दु शिखर में प्रकाशित खबर का असर सामने आया है। 20 सितंबर को क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने 21 सितंबर को संयुक्त रूप से मोहब्बेवाला राजमार्ग और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत एवं तकनीकी जांच करने के निर्देश दिए गए। सड़क इंजीनियरिंग, ब्लैक स्पॉट, ओवरस्पीडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन समेत सभी पहलुओं का विश्लेषण कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्षेत्र में बड़े चेतावनी साइन बोर्ड लगाने तथा रंबल स्ट्रिप ब्रेकर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए तैयार कार्ययोजना को तत्काल लागू करने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्रशासन, एनएचएआई, आरटीओ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

ज्योलीकोट में दूषित पानी से मौतों पर छह अधिकारी निलंबित

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल

ज्योलीकोट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पेयजल से जलजनित रोग फैलने और एक छात्र व एक विवाहिता की मौत के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जल संस्थान और पेयजल निगम के छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें जल संस्थान के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता तथा पेयजल निगम के प्रभारी अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

◆ **हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद ज्योलीकोट जल संकट में छह अधिकारियों पर हुई बड़ी विभागीय कार्रवाई**

मामला जून में सामने आया था, जब ज्योलीकोट समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति से डायरिया, पीलिया और अन्य जलजनित रोग फैलने की शिकायतें मिली थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद यह कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को निगरानी के निर्देश दिए थे। जल संस्थान की ओर से निलंबित अधिकारियों को संबंधित कार्यालयों से संबद्ध किया गया है।

वहीं पेयजल निगम के निलंबित अधिकारियों को मुख्य अभियंता कुमाऊं और अधीक्षण अभियंता कार्यालय से संबद्ध किया गया है। शासन ने जल संस्थान लालकुआं के अधिशासी अभियंता नंदकिशोर को अग्रिम आदेश तक अधीक्षण अभियंता हल्द्वानी का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा है।

नई टिहरी आइटीआई में लगा नेशनल अप्रेंटिस मेला, 45 प्रशिक्षार्थियों का चयन

अनिल थपलियाल

नई टिहरी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ), नई टिहरी में सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान की स्मृति में नेशनल अप्रेंटिस मेला-2026 आयोजित किया गया। मेले में 25 कंपनियों और संस्थानों ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षार्थियों को अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराए। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और आइटीआइ प्रधानाचार्य आशुतोष उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षार्थियों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया।

मेले में पैनासोनिक, यूपीपीसीएल, जल संस्थान और एमबीआइओ इन्फोसिस समेत 25 कंपनियों ने विभिन्न ट्रेडों के करीब 113 प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार लिया। इनमें से 45 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया। साक्षात्कार व्यवसाय, फिटर, वेल्डर, विद्युतकार, कोपा और स्टेनोग्राफी आदि ट्रेडों के लिए हुआ।

प्रधानाचार्य आशुतोष उनियाल ने प्रशिक्षार्थियों को अप्रेंटिसशिप के महत्व और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अप्रेंटिस/प्लेसमेंट अधिकारी कुलदीप सिंह रावत, अनुदेशक शिल्पी, कार्यदेशक प्रीति और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंजुला रावत समेत संस्थान के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

अंत में प्रधानाचार्य ने अतिथियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर अनुदेशक अमित बहुगुणा, अमित सैनी, मुकेश तोमर, राजेशलाल, अनिता शाही, मनवीर सिंह, सुनील असवाल और शिवानी पंवार आदि उपस्थित रहे।

हल्द्वानी में दो महिलाओं ने पूर्व सैनिक के 50 हजार उड़ाए

हल्द्वानी। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के एटीएम परिसर में दो महिलाओं ने एक पूर्व सैनिक के थैले से 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। पूर्व सैनिक पेंशन के 50 हजार रुपये निकालने के बाद पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक परिसर में गए थे। इसी दौरान महिलाओं ने मौका पाकर उनके थैले को काट दिया और उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गईं। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व सैनिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दोनों संदिग्ध महिलाओं की गतिविधियां कैद हुई हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस अब दोनों की पहचान और तलाश में जुटी है। बताया गया कि महिलाओं ने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया और पूर्व सैनिक को इसका पता बाद में चला। पेंशन की राशि चोरी होने से पूर्व सैनिक परेशान हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

मसूरी शरदोत्सव का न्योता लेकर सीएम धामी से मिले गणेश जोशी और मीरा सकलानी

सुनील सोनकर

मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबे समय बाद होने जा रहे ऐतिहासिक शरदोत्सव 2026 को लेकर शहर में उत्साह बढ़ने लगा है। शरदोत्सव को भव्य रूप देने की तैयारियों के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें शरदोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में पहुंचने का भरोसा दिया। शरदोत्सव को मसूरी की पुरानी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़े इस आयोजन की दोबारा शुरुआत से स्थानीय कलाकारों, युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों में उत्साह है। आयोजन के माध्यम से मसूरी की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय कला और प्रतिभाओं को मंच देने की तैयारी की जा रही है।

◆ **लंबे अंतराल बाद लौट रहा मसूरी का ऐतिहासिक शरदोत्सव, मुख्यमंत्री ने आयोजन में पहुंचने का दिया भरोसा**

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मसूरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने सड़क, पेयजल, पर्यटन विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़े विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। हालांकि मुलाकात का प्रमुख केंद्र शरदोत्सव रहा और मुख्यमंत्री को आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। शरदोत्सव के आयोजन को लेकर शहर में विभिन्न समितियों के गठन और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थानीय कलाकारों और अन्य प्रतिभाओं को अवसर देने की तैयारी है। इससे मसूरी के पर्यटन सीजन में भी नई गतिविधियां जुड़ने की उम्मीद है। मुलाकात में सभासद कुशाल सिंह राणा, जसबीर कौर, प्रदेश संस्कृति प्रकोष्ठ संयोजक राजेंद्र रावत, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की 26 सितंबर से बढ़ेगी परेशानी

देहरादून। मुरादाबाद मंडल के रायसी स्टेशन पर अप और लूप लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते 26 से 29 सितंबर तक विभिन्न चरणों में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक रहेगा। इसके कारण इस अवधि में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ को निर्धारित समय में बदलाव या परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। चंदौसी से ऋषिकेश जाने वाली पैसेंजर 26 से 29 सितंबर तक और ऋषिकेश से चंदौसी जाने वाली पैसेंजर 25 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। प्रयागराज से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली एक्सप्रेस तथा योगनगरी से प्रयागराज जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस 27 सितंबर को रद्द रहेंगी। इसके अलावा 28 सितंबर को दरभंगा से अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस को रास्ते में करीब 30 मिनट रोककर चलाया जाएगा।

कनाडा में 102 करोड़ के लोन में फंसे दो गुरुद्वारे

1.5 करोड़ कनाडाई डॉलर की लोन लिमिट, ब्याज बढ़कर 88 करोड़ रुपए से ज्यादा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

कनाडा के ओंटारियो में दो गुरुद्वारे भारी-भरकम लोन विवाद में फंस गए हैं। सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो और नानकसर ठाठ ईशर दरबार की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी से जोड़कर 1.5 करोड़ कनाडाई डॉलर यानी करीब 102.6 करोड़ रुपये की लोन लिमिट बनाई गई थी। इस लोन पर समय के साथ ब्याज की राशि भी काफी बढ़ गई और अब यह 88 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है। मामले में संपत्तियों की बिक्री को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है।

मामला कनाडा के ओंटारियो प्रांत से जुड़ा है, जहां दो गुरुघरों की संपत्तियों को लोन की सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित वित्तीय विवाद में कर्ज की मूल राशि के साथ ब्याज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। यही वजह है कि अब कुल देनदारी काफी बड़ी हो गई है। सिख स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो और नानकसर ठाठ ईशर दरबार की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर जोड़कर 1.5 करोड़ कनाडाई डॉलर की लोन लिमिट तैयार की गई थी। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 102.6 करोड़ रुपये बताई गई है।

लोन से जुड़े विवाद में ब्याज की रकम भी लगातार बढ़ती रही। अब ब्याज 88 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है। इस मामले में प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हुई। ब्रैम्पटन स्थित गुरुद्वारे की संपत्ति को बेचने की कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित संपत्ति की बिक्री फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगी।

मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ब्रैम्पटन स्थित गुरुद्वारे की संपत्ति की बिक्री को लेकर सामने आया है। कोर्ट ने संपत्ति बेचने पर रोक लगाई है। इससे गुरुद्वारा प्रबंधन और लोन विवाद से जुड़े पक्षों के बीच कानूनी प्रक्रिया का महत्व बढ़ गया है। लोन विवाद में संपत्तियों को सिक्योरिटी के तौर पर जोड़े जाने के कारण मामला केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी भी इसके केंद्र में आ गई है।

अदालत की रोक के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर संपत्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। करीब 102.6 करोड़ रुपये की लोन लिमिट से जुड़े इस मामले में 88 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज की बात सामने आने के बाद विवाद की गंभीरता बढ़ गई है। मूल लोन के अलावा ब्याज की इतनी बड़ी राशि जुड़ने से कुल वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। दोनों गुरुघरों की प्रॉपर्टी को लोन सिक्योरिटी से जोड़ने के कारण इस मामले में संपत्ति और कर्ज दोनों अहम मुद्दे हैं। अदालत द्वारा ब्रैम्पटन की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाए जाने से फिलहाल उस प्रॉपर्टी को बेचकर विवाद निपटाने की प्रक्रिया रुक गई है। ओंटारियो में सामने आए इस मामले में अब आगे की सुनवाई और अदालत के आदेश महत्वपूर्ण होंगे। लोन, ब्याज और संपत्तियों से जुड़े दावों पर कानूनी प्रक्रिया के दौरान संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखेंगे।

फिलहाल ब्रैम्पटन स्थित गुरुद्वारे की संपत्ति की बिक्री पर अदालत की रोक लगी हुई है। मामले ने कनाडा में गुरुद्वारों की संपत्तियों को लेकर बड़े वित्तीय विवाद को सामने ला दिया है। 1.5 करोड़ कनाडाई डॉलर की लोन लिमिट, 88 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज और संपत्ति बिक्री पर अदालत की रोक इस पूरे विवाद के प्रमुख पहलू हैं। मामले में अब अदालत की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

केजरीवाल का भाजपा पर पलटवार, मुंद्रा पोर्ट से नशे की सप्लाई रोकने की मांग

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के 'पंजाब का भविष्य खतरे में है' वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि अगर पंजाब के युवाओं और भविष्य की चिंता है तो गुजरात से आने वाली नशे की सप्लाई को रोकना चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत पंजाब से नहीं, बल्कि मुंद्रा पोर्ट से होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजरात से पंजाब की ओर आने वाली नशीले पदार्थों की कथित सप्लाई पर कार्रवाई करने की मांग की। यह बयान ऐसे समय आया है, जब भाजपा पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और राज्य में नशे की समस्या को प्रमुख मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रधानमंत्री के हवाले से पंजाब के युवाओं और भविष्य को नशे से बचाने की बात कही गई थी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यदि पंजाब के भविष्य की चिंता है तो नशे की सप्लाई के स्रोतों और रास्तों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया।

केजरीवाल का यह बयान पंजाब में नशे को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है। भाजपा की ओर से 18 से 30 सितंबर तक प्रदेश में चार 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना और पंजाब को नशामुक्त बनाने का संदेश देना बताया गया है। यात्राएं प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों से गुजरने वाली हैं। पंजाब में नशे की सप्लाई को लेकर इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का मुद्दा उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाजपा के नशामुक्त पंजाब अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंद्रा पोर्ट का जिक्र किया था।

उन्होंने कहा था कि पंजाब को नशे के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ-साथ दूसरे राज्यों से आने वाली बड़ी खेपों पर भी कार्रवाई जरूरी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी भाजपा की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को लेकर मुंद्रा पोर्ट से हुई नशीले पदार्थों की बरामदगी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में यात्रा निकालने से पहले मुंद्रा पोर्ट से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।

24 सितंबर को कोर्ट में खुलेगा डीआईजी भुल्लर रिश्वतकांड का राज, शिकायतकर्ता देंगे गवाही

आठ लाख रुपए की रिश्वत से जुड़े मामले में गवाही की प्रक्रिया होगी शुरू

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े आठ लाख रुपये के कथित रिश्वतकांड में 24 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अहम सुनवाई होगी। इस दौरान मामले के शिकायतकर्ता और मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी आकाश बत्ता पहली बार अदालत में पेश होकर गवाही देंगे। उनकी गवाही को मामले की आगे की सुनवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले के अनुसार, सीबीआई ने पिछले वर्ष तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब शिकायतकर्ता के अदालत में बयान दर्ज होने हैं। आकाश बत्ता की गवाही के दौरान मामले से जुड़े घटनाक्रम और कथित रिश्वत लेनदेन से संबंधित जानकारी सामने आ सकती है।

सीबीआई की विशेष अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल-जवाब किए जा सकते हैं। अदालत में दर्ज होने वाला उनका बयान जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत किए गए मामले के साक्ष्यों का हिस्सा बनेगा। इसके बाद बचाव पक्ष को भी गवाही पर सवाल करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत के निर्णय के बाद ही होगी।

डीआईजी भुल्लर से जुड़े इस मामले में आठ लाख रुपये की रिश्वत का आरोप है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद से ही यह मामला चर्चा में रहा है। अब 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि शिकायतकर्ता पहली बार अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी आकाश बत्ता की गवाही के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सेक्टर-26 में वीवीआईपी वाहनों से स्कूलों के बाहर लगा जाम

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में ट्रैफिक नियम आम नागरिकों के लिए सख्ती से लागू किए जाते हैं, लेकिन सेक्टर-26 में वीवीआईपी और नेताओं के वाहनों के मामले में अलग तस्वीर नजर आई। स्ट्रॉबेरी स्कूल और सेंट कबीर स्कूल के बाहर सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने से यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई। आम तौर पर सड़क पर वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान करने के साथ वाहन को टो कर ले जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूलों के बाहर वीवीआईपी वाहनों की पार्किंग के कारण सड़क पर जगह कम हो गई, जिससे दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हुई। खबर के अनुसार, इन वाहनों के कारण स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इससे आम वाहन चालकों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। यदि आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वीवीआईपी और नेताओं के वाहनों पर भी नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्टर-26 में स्कूलों के बाहर यातायात व्यवस्था सुधारने और पार्किंग को व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि बच्चों, अभिभावकों और राहगीरों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

स्वाइन फ्लू की बढ़ी रफ्तार, पंजाब में 347 मरीज पॉजिटिव

एक जनवरी से अब तक 347 मरीजों की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) यानी स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी से अब तक प्रदेश में कैटेगरी-सी के 1,926 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें जांच के बाद 347 मरीजों की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई है। संक्रमण के कारण लुधियाना और जालंधर में एक-एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। गुरुवार को प्रदेश में 12 नए पॉजिटिव मामले सामने आए।

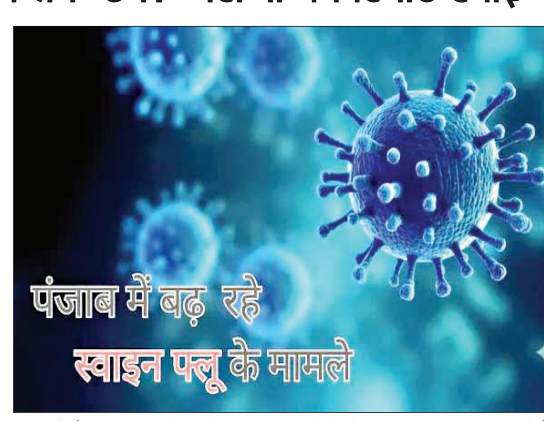

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, लुधियाना में स्वाइन फ्लू के सबसे अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मोहाली और पटियाला में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार सामने आ रहे नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने को कहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लोगों को फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। प्रदेश में सामने आए 1,926 कैटेगरी-सी के संदिग्ध मामलों की जांच के बाद 347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। विभाग इन मामलों की निगरानी कर रहा है।

गुरुवार को मिले 12 नए पॉजिटिव मामलों के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता भी बढ़ी है। लुधियाना और जालंधर में स्वाइन फ्लू से हुई दो मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दे रहा है। लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर दूसरों से दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है। स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लक्षण लंबे समय तक बने रहने या स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है।

विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में इस साल अब तक 347 स्वाइन फ्लू मरीजों की पुष्टि हुई है। लुधियाना में सबसे अधिक संदिग्ध मामले सामने आने के साथ मोहाली और पटियाला में भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विभाग की ओर से लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

तनिष्क शोरूम में सोने की चेन चोरी, महिला को एक साल जेल

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा स्थित तनिष्क शोरूम से सोने की चेन चोरी करने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने मोहाली के खरड़ निवासी डिंपल को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चोरी की गई सोने की चेन बरामद होने के बाद मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया।

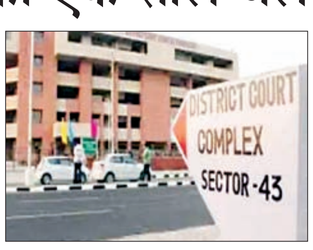

मामला 18 मार्च 2021 का है। शोरूम के सेल्समैन मिलिंद मल्होत्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दो महिलाएं सोने की चेन देखने के बहाने शोरूम में आई थीं। दोनों ने कुछ देर तक अलग-अलग आभूषण देखे। इसके बाद वे बिना कोई सामान खरीदे शोरूम से बाहर निकल गईं। बाद में शोरूम कर्मचारियों को चेन गायब होने का पता चला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान डिंपल का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन बरामद की गई। इसके बाद उसके खिलाफ अदालत में मामला चला। इस मामले में दिल्ली निवासी गीता चोपड़ा भी आरोपित थी। हालांकि, वह अदालत की कार्यवाही के दौरान लगातार पेश नहीं हुई।

हिमाचल समेत छह राज्यों के समझौते के बाद विवाद, पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की

किशाऊ परियोजना पर पंजाब का कानूनी दांव, यमुना पानी में हिस्सेदारी का दावा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। राज्य सरकार का कहना है कि यमुना बेसिन से जुड़ी इस परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले पंजाब को विश्वास में नहीं लिया गया। पंजाब यमुना नदी के पानी में अपने हिस्से का दावा कर रहा है और 1994 के जल बंटवारे समझौते में राज्य को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठा रहा है।

पंजाब जल संसाधन विभाग ने प्रस्तावित याचिका के मसौदे को मंजूरी के लिए एडवोकेट जनरल कार्यालय भेजा है। विभाग के अनुसार, मसौदे की जांच पंजाब के पूर्व एडवोकेट जनरल रह चुके एक वरिष्ठ अधिवक्ता कर चुके हैं।

अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की तैयारी है। पंजाब सरकार का तर्क है कि 12 मई 1994 को हुए यमुना जल बंटवारे के समझौते में पंजाब शामिल नहीं था। उस समय दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। पंजाब का कहना है कि उसे यमुना जल आवंटन से जुड़े मामलों में लगातार शामिल किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार 1954 के एक समझौते का भी हवाला दे रही है।

चंडीगढ़ में सर्दियों से पहले चकाचक होंगी सड़कें निगम ने तेज किया काम

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बारिश के बाद खराब हुई सड़कों की मरम्मत और री-कारपेटिंग का काम तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने सर्दियों से पहले करीब 400 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है। शहर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सेक्टर-9 में सड़क की पुरानी परतें हटाकर नीचे तक खुदाई की जा रही है, ताकि सड़क का स्तर और मजबूती बेहतर की जा सके। निगम का प्रयास है कि केवल ऊपरी सतह की मरम्मत के बजाय सड़क की खराब परतों को हटाकर टिकाऊ तरीके से काम किया जाए। बारिश थमने के बाद विभिन्न सेक्टरों में चरणबद्ध तरीके से री-कार्पेटिंग और सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

बिल्डर को 16 .36 लाख लौटाने का आदेश, 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली। फ्लैट बुक कराने के बाद एग्रीमेंट न करना और बैंक लोन के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न कराना बिल्डर को भारी पड़ गया। मोहाली जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को उपभोक्ता की 16.36 लाख रुपये की बुकिंग राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 2.25 लाख रुपये अलग से देने होंगे।

मामले के अनुसार, उपभोक्ता ने बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था और इसके लिए 16.36 लाख रुपये की राशि जमा की थी। बुकिंग के बाद उपभोक्ता को उम्मीद थी कि बिल्डर निर्धारित प्रक्रिया के तहत फ्लैट का एग्रीमेंट करेगा और बैंक से लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। हालांकि, बिल्डर ने न तो एग्रीमेंट किया और न ही बैंक लोन के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए।

दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता के लिए फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। इसके बाद उसने अपनी बुकिंग राशि वापस लेने की मांग की, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। मामला मोहाली जिला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा। फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद बिल्डर को बुकिंग राशि 16.36 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया।

पंजाब कांग्रेस में हलचल, प्रताप बाजवा ने सचिन पायलट से की अहम मुलाकात, राहुल दौरे पर चर्चा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पंजाब कांग्रेस से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।

मुलाकात में राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर भी बातचीत हुई। बाजवा ने बताया कि पायलट के साथ पंजाब को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव की तैयारियां शुरू करने को लेकर भी बातचीत हुई। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अगले चार-पांच दिनों में स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई गई है। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बदलाव को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है। सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्य के वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें शुरू की हैं। पायलट ने हाल में पंजाब का दौरा भी किया था, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक साथ नजर आए।

पायलट ने पंजाब कांग्रेस के संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया है। पार्टी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा जारी है। राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को कांग्रेस की आगामी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं के अनुसार, दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

इससे पहले भी पायलट और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बीच पंजाब की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति को लेकर चर्चा हो चुकी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस में संगठन से जुड़े लंबित फैसलों को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चाएं चल रही हैं। पायलट की बैठकों के बाद केंद्रीय नेतृत्व को राज्य संगठन से संबंधित रिपोर्ट दिए जाने की बात सामने आई थी।

हड़ताल 5500 से अधिक चालक-कंडक्टर हड़ताल में शामिल, 2700 से ज्यादा बसों का संचालन रहेगा प्रभावित

रोडवेज कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए मंगलवार से परेशानी बढ़ सकती है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (पंजाब 25/11) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। यूनियन के इस फैसले से पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बस सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है।

ऐसे में रोजाना सरकारी बसों के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। यूनियन के अनुसार, हड़ताल में पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के करीब 5500 से अधिक चालक और कंडक्टर शामिल होंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में 2700 से अधिक सरकारी बसों का संचालन प्रभावित होने की बात कही गई है। इन बसों के जरिए रोजाना बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न जिलों और शहरों के बीच सफर करते हैं।

बसों का संचालन रुकने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी बसों या अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। कर्मचारी संगठनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि हड़ताल की कोई निर्धारित समाप्ति तिथि घोषित नहीं की गई है। जब तक कर्मचारियों और सरकार के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बनती, तब तक बस सेवाओं पर इसका असर बने रहने की संभावना है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चिंता उन रूटों को लेकर हो सकती है, जहां सरकारी बसें परिवहन का प्रमुख साधन हैं। यूनियन का कहना है कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाते रहे हैं। इनमें ठेका कर्मचारियों को नियमित करना और समान काम के लिए समान वेतन सहित कई मांगें शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों पर ठोस समाधान नहीं होने के कारण उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। इसके अलावा समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग भी उठाई गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे ठेका कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।

यूनियन इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हड़ताल का असर केवल बस संचालन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे रोजाना काम, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए सरकारी बसों पर निर्भर यात्रियों की दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। खासकर लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्लानिंग विभाग की भूमिका और ढांचे की समीक्षा जारी

प्रशासनिक, वित्तीय और संगठनात्मक पहलुओं पर विचार के बाद सरकार लेगी फैसला

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सत्र में प्रदेश के प्लानिंग सिस्टम को मजबूत और प्रभावी बनाने का मुद्दा उठा। कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकार से पूछा कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से प्लानिंग फंक्शन को मजबूत, पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने की बात कहे जाने के बाद अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।

तारिगामी ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या प्लानिंग व्यवस्था में बदलाव को लेकर कोई कैबिनेट निर्णय, सरकारी आदेश या औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर प्लानिंग सेल स्थापित करने, विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था को मजबूत करने और जिला विकास परिषदों, स्थानीय निकायों तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय का मुद्दा भी उठाया। सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग विभाग की भूमिका, कार्यात्मक दायित्व और संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा चल रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और संबंधित प्लानिंग विभाग के बीच

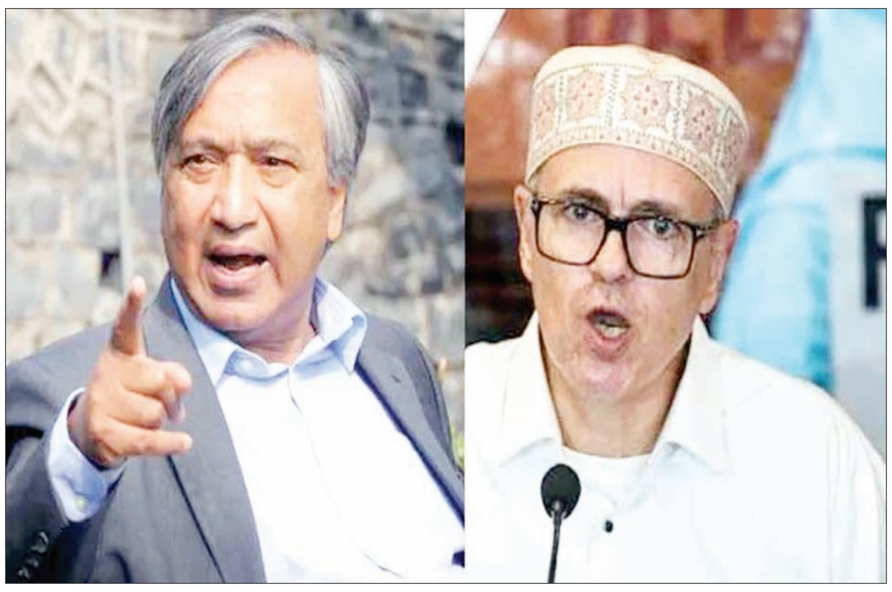

जिला और ब्लॉक स्तर की योजना व्यवस्था को लेकर समीक्षा जारी।

विचार-विमर्श जारी है। सरकार के अनुसार समीक्षा के दौरान प्रशासनिक, संगठनात्मक और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार ने संकेत दिया कि समीक्षा पूरी होने के बाद प्लानिंग सिस्टम को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। इसका उद्देश्य योजना निर्माण और विकास कार्यों की निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर योजना तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

विधायक के सवाल में जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना निर्माण को मजबूत करने का विषय भी प्रमुखता से सामने आया। स्थानीय स्तर पर जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जरूरत पर चर्चा हुई। जिला विकास परिषदों और स्थानीय निकायों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए।

सरकार के जवाब के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था और विभागीय जिम्मेदारियों का अध्ययन किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान यह देखा जा रहा है कि प्लानिंग विभाग की भूमिका को किस तरह अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्लानिंग सिस्टम में बदलाव पर सरकार की नजर

इसके साथ ही समीक्षा में योजना निर्माण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने और विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारियां स्पष्ट करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना तैयार करने की क्षमता बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने और योजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, प्लानिंग सिस्टम में बदलाव से पहले सभी संबंधित पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विभागों के बीच समन्वय बेहतर होने से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में सुधार की उम्मीद है। समीक्षा पूरी होने के बाद सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया और प्रस्तावित बदलावों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। अंतिम निर्णय के बाद नई व्यवस्था में विभागों की भूमिका, योजना निर्माण और निगरानी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

बिजली बिल बकायादारों को मिल सकती है राहत, एमनेस्टी योजना बढ़ाने पर विचार

सरकार योजना विस्तार की संभावना की मेरिट पर कर रही जांच

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में बिजली बिल बकायादारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार पावर एमनेस्टी योजना की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विधानसभा में बताया कि तय समय के भीतर बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए योजना के विस्तार की संभावना की मेरिट के आधार पर जांच की जा रही है। रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे के तारांकित सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।

सवाल में पूछा गया था कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल का बड़ा हिस्सा जमा कर दिया है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण शेष राशि की किस्तें नहीं चुका पाए, क्या उन्हें सरचार्ज या ब्याज में राहत दी जा सकती है। सरकार से यह भी पूछा गया कि ऐसे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने की कोई व्यवस्था है या नहीं। विभाग ने बताया कि एमनेस्टी योजना के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। योजना बढ़ाए जाने पर घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों को अपने पुराने बकाये

बिजली बकायादारों को राहत, योजना विस्तार पर विचार

सरकार के इस कदम से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, जो बकाया राशि चुकाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण समय पर भुगतान नहीं कर पाए। योजना के विस्तार से उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। विभाग की ओर से प्रस्ताव का आकलन करने के बाद इसे लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य बकाया राशि की वसूली के साथ उपभोक्ताओं को भुगतान में सुविधा देना है। अंतिम मंजूरी और शर्तें तय होने के बाद ही योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की स्थिति स्पष्ट होगी।

का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य बकाया राजस्व की वसूली के साथ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। हालांकि योजना की अवधि बढ़ाने और राहत की शर्तों को लेकर अंतिम फैसला सरकार की ओर से लिया जाना बाकी है। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि बकायादारों को कितनी राहत मिलेगी और भुगतान के लिए कितना अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं की बदली तारीख

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने कई पदों की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। बोर्ड ने नई तिथियों को लेकर अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के अनुसार फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (एफएमपीएचडब्ल्यू) और मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (एमएमपीएचडब्ल्यू) के पदों के लिए 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित परीक्षा अब 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय

परीक्षा तिथि जल्द

बोर्ड के अनुसार ड्रेसर और जूनियर फार्मासिस्ट की परीक्षा की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे जेकेएसएसबी की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखें। अन्य पदों की परीक्षाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।

मिलेगा। इसी तरह जूनियर थिएटर टेक्निशियन पद की परीक्षा, जो पहले 24 सितंबर को निर्धारित थी, अब 29 अक्टूबर 2026 को होगी।

हेल्थ एजुकेटर पद के लिए 27 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा की तारीख भी बदल दी गई है। अब यह परीक्षा एक नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। जेकेएसएसबी ने ड्रेसर और जूनियर फार्मासिस्ट पदों के लिए होने वाली ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है।

लद्दाख की ऐतिहासिक यात्रा, तिब्बत से भारत तक का सफर

जोरावर सिंह के अभियान से लद्दाख जम्मू-कश्मीर का बना हिस्सा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। करीब 2000 साल पुराने इतिहास में इस क्षेत्र पर अलग-अलग राजवंशों और शक्तियों का प्रभाव रहा है। तिब्बत और मध्य एशिया से इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं।

लद्दाख लंबे समय तक विभिन्न स्थानीय शासकों के अधीन रहा। 19वीं सदी में डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख में सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ जुड़ गया। इस दौरान क्षेत्र का राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप भी बदला। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जम्मू-कश्मीर का

भारत में विलय हुआ और लद्दाख भी इसी प्रशासनिक इकाई का हिस्सा रहा। समय के साथ यहां की अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चर्चाएं होती रहीं। 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान में लेह और कारगिल इसके प्रमुख जिले हैं। लद्दाख की अलग पहचान और विकास को लेकर स्थानीय स्तर पर मांगें उठती रही हैं।

◆ जोरावर सिंह के अभियान से बदली लद्दाख की राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान

स्थानीय अधिकारों और विकास पर जोर दे रहे लोग

लद्दाख की अलग पहचान और विकास को लेकर स्थानीय स्तर पर मांगें उठती रही हैं। क्षेत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा और स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार देने जैसे मुद्दे समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में इसकी स्थिति भी इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। लेह और कारगिल में अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान देखने को मिलती है। स्थानीय संगठनों और नागरिक समूहों की ओर से रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाते रहे हैं।

विधानसभा सत्र के पहले दिन श्रीनगर में लगा भारी जाम

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को श्रीनगर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

लालचौक, बटमालू, करननगर, बरजुल्ला, डलगेट, बरबरशाह और मगरमल बाग समेत कई इलाकों में घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहे। जाम की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वाहनों से उतरकर पैदल जाना पड़ा। सड़कों पर यातायात की रफ्तार बेहद धीमी रही और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, दुकानदारों तथा अन्य यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रशासन और यातायात पुलिस की ओर से कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया था। हालांकि, कई स्थानों पर वाहन चालकों द्वारा निर्धारित मार्गों और यातायात नियमों का पालन नहीं करने से व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके चलते वैकल्पिक रास्तों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया।

जम्मू-कश्मीर में 38,872 सरकारी पद खाली, स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे

कुल रिक्तियों में 3,318 गजटेड, 24,427 नॉन-गजटेड और 11,127 एमटीएस पद शामिल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का आंकड़ा सामने आने के बाद रोजगार और भर्ती का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सरकार के अनुसार, विभिन्न विभागों में कुल 38,872 पद रिक्त हैं। इनमें 3,318 गजटेड, 24,427 नॉन-गजटेड और 11,127 मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद शामिल हैं। यह जानकारी विधायक इरफान हाफिज लोन के तारांकित प्रश्न के जवाब में विधानसभा में दी गई।

विभागवार आंकड़ों में सबसे अधिक रिक्तियां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में हैं। यहां कुल 12,797 पद खाली हैं। इनमें 2,125 गजटेड, 8,064 नॉन-गजटेड और 2,608 एमटीएस पद शामिल

हैं। इसके बाद कृषि उत्पादन, पशु एवं भेड़ पालन और बागवानी क्षेत्र में 4,939 पद रिक्त हैं। लोक निर्माण विभाग में 2,190 और वित्त विभाग में 1,829 पद खाली हैं। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग में 1,619, उद्योग एवं वाणिज्य में 1,787, स्कूल शिक्षा में 1,364 और युवा सेवा एवं खेल विभाग में 1,369 पद रिक्त हैं। बिजली विकास विभाग में 1,264, आवास एवं शहरी विकास में 941 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 836 पद खाली बताए गए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में काम कर रहे कैजुअल, मौसमी, संविदा, जरूरत के आधार पर नियुक्त और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है।

19 मार्च 2025 के सरकारी आदेश संख्या 384-जेके(जीएडी) के तहत गठित समिति इस मुद्दे की समीक्षा कर रही है। समिति नियमितीकरण के मानवीय, कानूनी और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन कर रही है। प्रस्तावित नीति को मौजूदा कानून, न्यायिक स्थिति और भर्ती नियमों के अनुरूप बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार के अनुसार पिछले दो वर्षों में 2,150 पद जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को भर्ती के लिए भेजे गए।

जम्मू में महिला की संदिग्ध मौत पर मायके वालों का हंगामा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव सई सरदारी में 38 वर्षीय सुषमा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सोमवार को तनाव की स्थिति बन गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सई मौला मुख्य मार्ग पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि सुषमा की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे मायके वालों ने ससुराल पक्ष के मकान को गिराने तथा उसी स्थान पर सुषमा का अंतिम संस्कार करने की मांग रखी। परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा। घटना के बाद मौके पर तनाव बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मृतका के परिजनों के आरोपों की जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुषमा को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

जम्मू-कश्मीर में छह मुफ्त एलपीजी रिफिल योजना पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाखों गरीब परिवारों को साल में छह मुफ्त घरेलू एलपीजी रिफिल देने की घोषणा के बावजूद अभी तक इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि योजना फिलहाल विचाराधीन है और इसे लागू करने के लिए नियमों तथा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विधायक सज्जाद गनी लोन के तारांकित सवाल के जवाब में दी। विधायक ने पूछा था कि एएवाई परिवारों को बजट घोषणा के तहत छह मुफ्त एलपीजी रिफिल का लाभ कब से मिलेगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया तय की गई है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार जम्मू-कश्मीर के एएवाई परिवारों को हर साल छह घरेलू एलपीजी

सिलेंडरों की रिफिलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसके लिए लाभार्थियों को सीधे राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित है। राशि आधार-सक्षम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के मुताबिक योजना को लागू करने से पहले इसके नियम, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। इसी वजह से फिलहाल लाभार्थियों को छह मुफ्त रिफिल का इंतजार करना पड़ रहा है।

जम्मू-कश्मीर में 200 यूनिट फ्री बिजली का रास्ता साफ, पुराने बकाये पर सरकार सख्त

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना अब अमल के करीब पहुंच गई है। सरकार ने विधानसभा में बताया कि पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना अंतिम टेंडरिंग प्रक्रिया में है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार, रूफटॉप सोलर योजना के तहत बोलियां खोली जा चुकी हैं और फिलहाल उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

निर्धारित टेंडर प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत पात्र परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लागू की जा रही है। जम्मू-कश्मीर सरकार के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, 2.22 लाख अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के घरों में 2 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाने की मंजूरी मिली है। इन सिस्टम से प्रत्येक परिवार को हर महीने करीब 200 यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है।

वहीं, पुराने बिजली बकाये को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद मौजूदा बिजली बकाया माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी नई योजना का लाभ पुराने बकाये की माफी से अलग रहेगा। सरकार के मुताबिक योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सौर ऊर्जा के जरिये बिजली उपलब्ध कराने के साथ बिजली खर्च का बोझ कम करना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद पात्र उपभोक्ताओं को योजना का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

मुद्दे आरक्षण में देरी का मुद्दा उठाते हुए पीडीपी विधायक वहीद परा ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला दिन रोजगार मुद्दों पर गरमाया

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के पहले दिन ही युवाओं, आरक्षण, रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने के बाद भाजपा विधायकों ने रोजगार, बिजली दरों, आउटसोर्सिंग और कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विरोध के कारण सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई।

पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरक्षण से जुड़े मामलों में देरी और इसके प्रभाव पर तत्काल चर्चा की मांग की। पारा ने कहा कि यह मुद्दा जम्मू-कश्मीर के युवाओं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं और दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से जुड़ा है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और इससे संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की मांग रखी। वहीं, भाजपा विधायकों ने सदन में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की मांगों, दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण और सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाया। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर भी विरोध जताया गया।

विधायकों ने विभिन्न मांगों से जुड़े पोस्टर दिखाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान पैदा हुआ और बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की ओर से रोजगार और सेवा संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई। भाजपा ने दैनिक वेतनभोगी, कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों

के नियमितीकरण के साथ आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े मामलों को भी सत्र में उठाने की बात कही। इन कर्मचारियों से जुड़े रोजगार और सेवा संबंधी विषय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा भी सत्र के प्रमुख विषयों में शामिल है। पारा की ओर से पेश प्रस्ताव में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। आरक्षण को लेकर खुले वर्ग के अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी, प्रमाणपत्रों और विभिन्न श्रेणियों से जुड़े मुद्दे पहले भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उठते रहे हैं।

रोजगार और आरक्षण पर बढ़ेगी बहस

आने वाले दिनों में विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज होने की संभावना है। विपक्ष रोजगार के अवसर, अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग और आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। वहीं, बिजली दरों में बढ़ोतरी और विभिन्न कर्मचारी वर्गों की मांगों पर भी सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था में देरी को लेकर भी चर्चा आगे बढ़ सकती है। सदन की आगामी बैठकों में सरकार की नीतियों, योजनाओं और जनहित से जुड़े सवालों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का यह सत्र 21 से 30 सितंबर तक निर्धारित है। विधानसभा के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार सत्र में सात बैठकें प्रस्तावित हैं। अगले दिनों में रोजगार, आरक्षण, सार्वजनिक सेवाओं, कर्मचारियों के नियमितीकरण और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पहले दिन की कार्यवाही से स्पष्ट हुआ कि सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस जारी रह सकती है। सत्ता पक्ष की ओर से सरकार के कामकाज और नीतियों पर जवाब देने की तैयारी है, जबकि विपक्ष रोजगार, कर्मचारियों, बिजली और आरक्षण जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। सत्र आगे बढ़ने के साथ इन मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है।

नशे के खिलाफ सिर्फ कानून नहीं समाज की सामूहिक भागीदारी भी जरूरी

केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतन्त्र लेखक
गांव-कोटला,घुमारवीं।

वर्तमान समय में नशे का जाल शहरों से लेकर गाँवों तक फैल चुका है। स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थी, बेरोजगार युवा और कई बार कम उम्र के किशोर भी आज इसकी चपेट में आ रहे हैं। शराब, चरस, अफीम, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और नशीली दवाओं का अवैध कारोबार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। नशे के कारण परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं और युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनता जा रहा है। ऐसे में नशे के खिलाफ समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में दीमक की तरह समाज की जड़ों को खोखला कर रही नशे की बीमारी से समाज को सुरक्षित करने के लिए नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना निश्चित रूप से आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसे अभियान ही लोगों को नशे के दुष्परिणामों से परिचित कराते हैं। संस्कार सोसायटी ने यह समझा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल बैठकों और भाषणों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए एक व्यापक जन अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ इस जन अभियान को आगे बढ़ाते हुए संस्कार सोसायटी की ओर से घुमारवीं में 8 जून 2024 को स्कूली विद्यार्थियों की उपमंडल स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी, जिसमें बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से चिट्टे के बढ़ते प्रभाव, उसके दुष्परिणाम और नशामुक्त समाज की कल्पना को प्रभावशाली ढंग से सामने रखा।

इसके बाद अभियान को साहित्य और संस्कृति से जोड़ते हुए सोसायटी की ओर से 2 मार्च 2025 को रैन बसेरा घुमारवीं में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले के करीब 40 वरिष्ठ एवं युवा कवियों ने भाग लिया। उद्देश्य था कि नशे के खिलाफ संदेश केवल प्रशासनिक अपील न रहकर समाज की संवेदनाओं और भावनाओं से भी जुड़े। इसके बाद चुने हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और संस्था सदस्यों के लिए कार्यशाला आयोजित कर चिट्टे के कानूनी, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक प्रभावों पर विशेषज्ञों से जानकारी दिलाई गई। इस पहल के माध्यम से युवाओं और उनके परिवारों को नशे के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

साथ ही, सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए 1 से 28 फरवरी 2026 तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 49 युवाओं एवं सोशल मीडिया प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्था के अनुसार इसके माध्यम से अभियान का संदेश तीन लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ने और नशे के खिलाफ सकारात्मक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस पहल ने यह दिखाया कि आधुनिक संचार माध्यमों का सही उपयोग सामाजिक जागरूकता के लिए प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

17 मई 2026 को इन युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में चिट्टे के सामाजिक कारणों और उसके समाधान पर गंभीर चर्चा हुई। युवाओं ने अपने घर, गांव और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस तरह अभियान में युवा केवल दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव के सहभागी बने। युवाओं की भागीदारी से अभियान को नई ऊर्जा मिली और नशे के खिलाफ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। घुमारवीं से उठी यह आवाज धीरे-धीरे प्रदेश स्तर तक पहुंची। संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्माणी के प्रयासों से शिमला में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर 'संजीवनी ग्रुप' का गठन किया गया।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

जिस बेटी को देवी कहते हैं, उसके जन्म से पहले ही सवाल क्यों खड़े कर देता है समाज

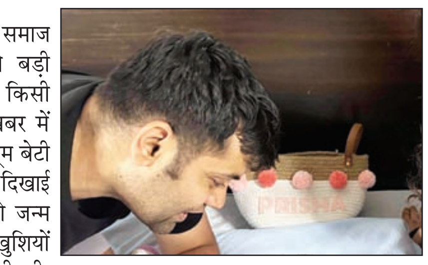

डॉ अंकिता चौधरी (सह-प्राध्यापक)अभिलाषी विश्वविद्यालय, मंडी (हि .प्र)

कभी-कभी समाज की सबसे बड़ी त्रासदी किसी अखबार की बड़ी खबर में नहीं, बल्कि एक मासूम बेटी की खामोश आंखों में दिखाई देती है। वह बेटी जो जन्म लेते ही परिवार की खुशियों का कारण बन सकती थी, लेकिन उसे आने से पहले ही इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह बेटी थी। वह बेटी जो अपने हिस्से का आसमान लेकर इस दुनिया में आना चाहती थी, लेकिन समाज की सदियों पुरानी सोच ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे में मन के भीतर से एक करुण पुकार उठती है— 'अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो।' यह पंक्ति केवल बेटी की पीड़ा नहीं है, बल्कि उस समाज के चेहरे पर एक कठोर प्रश्न है जो एक ओर नारी शक्ति की बातें करता है, बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व करता है और दूसरी ओर आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म को चिंता, खर्च और जिम्मेदारी के रूप में देखता है। आखिर ऐसी कैसी विडंबना है कि जिस बेटी को हम देवी का रूप कहते हैं, उसी के जन्म पर कई घरों में खुशी की जगह चिंता क्यों उतर आती है? बेटी जब जन्म लेती है तो वह अपने साथ कोई बोझ लेकर नहीं आती। वह केवल एक जीवन लेकर आती है—एक संभावना, एक सपना और एक पूरा भविष्य। लेकिन समाज उसके जन्म के साथ ही उसके जीवन का हिसाब लगाने लगता है। उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, शादी में कितना देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा की चिंता कौन करेगा—इन सवालों के बीच यह भूल जाता है कि बेटा भी उतनी ही जिम्मेदारी लेकर पैदा होता है। फर्क केवल हमारी सोच का है। जिस परिवार में बेटे के जन्म को वंश आगे बढ़ाने की खुशी माना जाता है, उसी परिवार में बेटी के जन्म को कई बार चिंता की नजर से देखा जाता है। यह सोच न केवल बेटी के सम्मान को चोट पहुंचाती है बल्कि पूरे समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े करती है।

बेटी के प्रति भेदभाव हमेशा किसी बड़े अपराध के रूप में सामने नहीं आता। कभी वह खाने की थाली में दिखाई देता है, कभी शिक्षा के अवसरों में, कभी उसके सपनों पर लगाए गए प्रतिबंधों में और कभी उसके निर्णय लेने के अधिकार को छीन लेने में। कई बार बेटी को बचपन से ही यह सिखा दिया जाता है कि उसे दूसरों की खुशी के लिए जीना है, जबकि बेटे को अपने सपनों के लिए उड़ने का अधिकार दिया जाता है। यही छोटी-छोटी असमानताएं आगे चलकर एक बड़ी सामाजिक असमानता का रूप लेती हैं। बेटियों को घर के काम में अधिक लगाया जाना, उनकी शिक्षा को सीमित करना, उनकी पसंद और निर्णय को महत्व न देना और उनके सपनों को परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे दबा देना भी उसी भेदभाव का हिस्सा है।

और फिर आती है वह सबसे भयावह स्थिति, जहां बेटी को जन्म लेने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। कन्या भ्रूण हत्या केवल एक अजन्मे जीवन की हत्या नहीं है। यह उस सोच की हत्या है जो समाज में संवेदना, समानता और मनुष्यता को जन्म देती है। जिस समाज में बेटी के आने से पहले ही उसके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया जाए, वहां हमें यह पूछना चाहिए कि समस्या बेटी में है या हमारी मानसिकता में? किसी अजन्मी बेटी को केवल इसलिए दुनिया देखने का अवसर न देना कि वह लड़की है, मानवता के लिए गंभीर प्रश्न है। यह केवल कानून का विषय नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और नैतिक जिम्मेदारी का भी विषय है।

बेटी को बचाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। कानून जरूरी हैं, जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है घर के भीतर सोच का बदलना। जिस दिन माता-पिता बेटी और बेटे के भविष्य को बराबर नजर से देखने लगेंगे, जिस दिन बेटी की शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि निवेश समझा जाएगा, जिस दिन उसकी सुरक्षा को केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी माना जाएगा, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। बदलाव किसी एक अभियान या नारे से नहीं आएगा।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

संपादकीय

विकास का संतुलन

जलवायु परिवर्तन आज केवल पर्यावरण से जुड़ी चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक असमानता, आर्थिक विकास और विकसित तथा विकासशील देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है। बढ़ते तापमान, बदलते मौसम, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसमी घटनाओं ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऊर्जा और आर्थिक विकास पर भी पड़ रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल उत्सर्जन कम करने की बात पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी देखना होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और इसका भार किस पर अधिक पड़ रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और जलवायु से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु संबंधी असमानता का मुद्दा उठाया। भारत का लगातार यह पक्ष रहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के लंबे दौर में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया है, जबकि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और ऐतिहासिक उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से कम रहा है। इसके बावजूद विकासशील देशों पर उत्सर्जन घटाने और तेजी से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए जलवायु न्याय का प्रश्न वैश्विक जलवायु नीति के केंद्र में होना जरूरी है।

भारत के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश एक ओर तेज आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। भारत की बड़ी आबादी की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, परिवहन, कृषि और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसे में अचानक पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह समाप्त कर देना व्यावहारिक नहीं हो सकता। जरूरत ऐसी संतुलित रणनीति की है, जिसमें आर्थिक विकास की गति भी बनी रहे और स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ती जाए।

पिछले वर्षों में भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है। सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता और अन्य स्वच्छ तकनीकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा की लागत में कमी और तकनीकी क्षमता में वृद्धि ने भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं। पवन ऊर्जा भी ऊर्जा संक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा को भी कम-कार्बन ऊर्जा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी स्रोतों को मिलाकर ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा कर सके और उत्सर्जन के दबाव को कम कर सके।

भारत की जलवायु नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पर्यावरण संरक्षण को विकास की आवश्यकताओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। देश में करोड़ों लोगों के लिए रोजगार, आवास, बिजली, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अभी भी आवश्यक है। विकासशील देशों के सामने यह वास्तविकता है कि उन्हें गरीबी कम करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्थिक विकास की जरूरत है। इसलिए जलवायु नीति ऐसी होनी चाहिए, जिसमें विकासशील देशों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऊर्जा संक्रमण का रास्ता चुनने की पर्याप्त गुंजाइश मिले।

इसी संदर्भ में विकसित देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि दुनिया को तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना है तो विकासशील देशों को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। हरित तकनीक केवल उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी लागत भी विकासशील देशों की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। तकनीक हस्तांतरण, जलवायु वित्त और क्षमता निर्माण के बिना वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की गति सीमित रह सकती है। विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता को केवल सहायता के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक जलवायु जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव उन क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है, जिनकी आर्थिक क्षमता सीमित है। कृषि पर निर्भर आबादी अनियमित बारिश, सूखा और अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होती है। छोटे किसान, तटीय क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में जलवायु नीति का उद्देश्य केवल कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समाज और अर्थव्यवस्था को तैयार करना भी होना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और मजबूत बुनियादी ढांचा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

-शिवांश धाकड़

कविता

जिंदगी

रक्षा कुमारी
खन्यारा, धर्मशाला(हि .प्र)

मुस्कुराती है जिंदगी कभी-कभी वीरानों में,
यूँ ही नहीं खिलते फूल तपते रेगिस्तानों में।
कांटों को भी कलियों का सहारा हुआ करता है,
दुख के साथ कहीं सुख भी रहा करता है।
कुछ खट्टे, कुछ मीठे हैं जायके जिंदगी के,
यूँ ही नहीं घुलती मिठास यादों की जुबानों में।
हर लम्हा कोई नया सबक दे जाता है,
हर मोड़ पर कोई नया रास्ता दिखाता है।
रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो,
उसके बाद सवेरा जरूर आता है।
हर जख्म के पीछे कोई चेहरा छिपा होता है,
जो दर्द सहकर भी मुस्कुराना सिखाता है।
मुस्कुराना जिनको आ जाए दर्द को पीकर भी,
वही तो सफल होते हैं जिंदगी के इम्तिहानों में।
गिरकर जो फिर उठते हैं और चलते जाते हैं,
वही अपनी पहचान बनाते हैं जमाने में।
जिनके पैरों ने चखे हों कांटों भरे रास्तों के मौसम,
वही फूलों की खुशबू को पहचानते हैं।
जिन्होंने आंधियों में भी दीप जलाए हों,
वही उजालों की कीमत जानते हैं।
जिंदगी हर किसी को आसान राह नहीं देती,
कभी धूप, कभी छांव का सफर देती है।
बस हौसला बनाए रखना, कदम बढ़ाते रहना,
क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है
जो कठिन रास्तों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते।

गीत की पंक्तियां याद न रखने वाले नेताओं का वंदे मातरम् पर ज्ञान देना कितना उचित

निर्मल रानी

राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' के 150 साल पूरे होने के अवसर पर 2026 के नए सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाना और सभी के लिए सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही औपचारिक अवसरों पर इसके सभी छह छंदों को गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष सहित कुछ अन्य संगठन इस अनिवार्य प्रोटोकॉल को संविधान के अनुच्छेद 25 अर्थात व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हैं। बहरहाल, इन सबके बावजूद 'वंदेमातरम' को संसद में और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लाल किले पर गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखे इस गीत के शब्द काफी कठिन हैं। छह छंदों पर आधारित यह गीत काफी लंबा भी है। चूंकि आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों को ही आधिकारिक तौर पर गाया जाता रहा है, इसलिए देश के अधिकांश राजनेताओं और आम नागरिकों को भी इसके बाद के चार छंद कंठस्थ याद नहीं होते हैं। लेकिन भाजपा के मामले में यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वह अन्य दलों पर राष्ट्रगीत के अपमान का तो आरोप लगाती है, जबकि खुद उसके अपने नेता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में चूक जाते हैं। समय-समय पर भाजपा के नेताओं की इस गीत को लेकर अज्ञानता कैमरे पर भी उजागर हुई है। एक टेलीविजन लाइव डिबेट के दौरान, जब भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह दूसरों को 'वंदे मातरम्' गाने की चुनौती दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे स्वयं इसे गाने को कह दिया। वे अपने मोबाइल फोन में देखने के बावजूद गीत की गलत पंक्तियां गाने लगे और धुन भी पूरी तरह भूल गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह औलख से जब पत्रकारों ने 'वंदे मातरम्' की कुछ पंक्तियां सुनाने को कहा, तो वे बेहद असहज हो गए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस समय पूरा याद नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में भाजपा के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंच पर राष्ट्रगीत गाते समय गलत धुन और गलत वर्जन बज गया। कांग्रेस द्वारा इस बड़ी चूक पर हमला किए जाने के बाद राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कोटा, मेरठ और ग्वालियर जैसे कई शहरों में भाजपा के स्थानीय विधायकों और सांसदों के ऐसे अनेक वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां वे वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन गण मन के बीच अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं या गीत की पंक्तियों को आपस में मिला देते हैं। हाल ही में गुजरे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब 'वंदे मातरम्' को लेकर नया कानून और राष्ट्रगीत विवाद गरमाया, तो विपक्ष ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों ने वंदे मातरम् को लेकर कड़े कानून बनाए हैं, हकीकत यह है कि उनके अपने नेताओं और मंत्रियों को भी यह गीत पूरा याद नहीं है।

उधर मुस्लिम समुदाय के भीतर इस गीत को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण और विचार हैं। हालांकि समग्र मुस्लिम समाज 'वंदे मातरम्' गायन का विरोध नहीं करता है, परन्तु समाज के कुछ लोग या कुछ धार्मिक संगठन इसके पूरे पाठ या कुछ विशिष्ट छंदों का विरोध करते हैं। जबकि अनेक अन्य मुस्लिम नागरिक, प्रतिष्ठित लोग और कलाकार इसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सहजता से गाते भी हैं।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

छोटे पर्दे से ओटीटी तक

रिद्धि डोगरा
जन्म : 22 सितंबर 1985

रिद्धि डोगरा भारतीय मनोरंजन जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने टेलीविजन से लेकर वेब सीरीज तक अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका जन्म 22 सितंबर 1985 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने नई दिल्ली के एपिजे स्कूल, शेख सराय से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की और इसके बाद कमला नेहरू कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वह श्यामक डावर डांस इंस्टीट्यूट से जुड़ी थीं और बतौर नृत्यांगना भी काम कर चुकी हैं।

रिद्धि डोगरा ने मनोरंजन उद्योग में अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन चैनल जूम में सह-निर्माता के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई टेलीविजन कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। उन्होंने जी टीवी, एनडीटीवी गुड टाइम्स और जूम जैसे मंचों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा यात्रा आधारित शो में प्रस्तोता के रूप में काम किया। टेलीविजन की दुनिया में अपनी जगह बनाने के बाद उन्होंने अभिनय को अपने करियर का प्रमुख हिस्सा बनाया।

रिद्धि को छोटे पर्दे पर कई चर्चित धारावाहिकों में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने 'सावित्री' में सावित्री, 'दीया और बाती हम' में अदिति और 'वो अपना सा' में निशा जैसे किरदार निभाए। इन भूमिकाओं के जरिए उन्होंने अलग-अलग तरह के चरित्रों को पर्दे पर उतारा और दर्शकों के बीच अपनी पहचान मजबूत की। उनकी अभिनय शैली में सहजता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को विशेष रूप से पसंद किया गया।

टेलीविजन के साथ रिद्धि डोगरा ने प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वर्ष 2013 में उन्होंने 'नच बलिए 6' में भाग लिया। इसके अलावा वह 'खतरों के खिलाड़ी 6' और 'द 50' जैसे कार्यक्रमों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इन कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को उनके अभिनय से अलग व्यक्तित्व और प्रदर्शन क्षमता से परिचित कराया।

वेब माध्यम में रिद्धि डोगरा को विशेष पहचान 'द मैरिड वुमन' से मिली। इस वेब सीरीज में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उनके अभिनय को दर्शकों तथा समीक्षकों से सराहना मिली।

सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन को महत्व देने की जरूरत

डॉ. रविंद्र कुमार
लाहड़ू चंबा

आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे मंचों ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और संवाद के क्षेत्र में इन माध्यमों ने अभूतपूर्व सुविधाएं दी हैं। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल का एक दूसरा और चिंताजनक पक्ष भी सामने आया है। खासकर युवाओं में लगातार बढ़ती आभासी दुनिया की निर्भरता उनके व्यवहार, आत्मविश्वास, सामाजिक संबंधों और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही है। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया उपयोगी है या नहीं, बल्कि यह है कि उसका उपयोग किस सीमा और किस उद्देश्य से किया जाए।

सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक जीवन और आभासी जीवन के बीच बढ़ती दूरी है। डिजिटल मंचों पर अधिकांश लोग अपने जीवन के चुनिंदा खूबसूरत और सफल क्षण ही साझा करते हैं। महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, शानदार छुट्टियां, आकर्षक तस्वीरें और उपलब्धियों से भरे संदेश देखकर दूसरे लोग अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सभी लोग उनसे अधिक खुश, सफल और संतुष्ट हैं। जबकि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर पूरी वास्तविकता नहीं होती। इस आभासी तुलना से युवाओं में हीन भावना, असुरक्षा और अपने जीवन से असंतोष बढ़ सकता है।

इसका एक बड़ा उदाहरण युवाओं में पसंद और प्रतिक्रिया की बढ़ती चिंता है। किसी तस्वीर या संदेश पर कितने पसंद, टिप्पणियां या साझा किए जाने मिले, यह कई लोगों के लिए आत्ममूल्यांकन का पैमाना बनता जा रहा है। यदि अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा और बेचैनी पैदा होने लगती है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी वास्तविक उपलब्धियों और खुशियों को भूलकर आभासी प्रतिक्रिया को सफलता का प्रमाण मानने लगता है। यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है और व्यक्ति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर बना सकती है।

सोशल मीडिया का दूसरा गंभीर प्रभाव साइबर उत्पीड़न के रूप में सामने आया है। इंटरनेट पर की गई अभद्र टिप्पणियां, उपहास, गलत आरोप और व्यक्तिगत हमले कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। वास्तविक जीवन में कही गई एक बात सीमित लोगों तक रहती है, लेकिन डिजिटल मंच पर वही बात तेजी से फैल सकती है। इससे प्रभावित व्यक्ति सामाजिक दबाव, शर्मिंदगी, तनाव और असुरक्षा महसूस कर सकता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी आवश्यक है।

लगातार स्क्रीन देखने की आदत युवाओं की दिनचर्या को भी प्रभावित कर रही है। देर रात तक मोबाइल पर वीडियो देखना, संदेश पढ़ना और अलग-अलग सामग्री देखना नींद के सामान्य चक्र को बिगाड़ सकता है। पर्याप्त नींद न मिलने से दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की समस्या पैदा हो सकती है। इसका असर पढ़ाई, नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत संबंधों पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति वास्तविक दुनिया की गतिविधियों के बजाय अधिक समय आभासी दुनिया में बिताने लगता है, तो सामाजिक मेलजोल और शारीरिक गतिविधियां भी कम हो सकती हैं।

हालांकि सोशल मीडिया को पूरी तरह नकारात्मक मानना भी उचित नहीं होगा। इसका सकारात्मक उपयोग युवाओं के लिए अनेक अवसर पैदा कर रहा है। आज विद्यार्थी घर बैठे शैक्षणिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। युवा रोजगार, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, प्रतियोगिताओं और करियर से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कलाकार, लेखक, संगीतकार और अन्य रचनात्मक प्रतिभाएं अपने काम को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा सकती हैं। छोटे व्यवसायों और नए उद्यमों के लिए भी सोशल मीडिया प्रचार और ग्राहकों तक पहुंच बनाने का प्रभावी माध्यम बन गया है।

सोशल मीडिया ने सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया है। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और अन्य सामाजिक विषयों पर अभियान चलाना अब आसान हो गया है। अनेक युवा अपनी समस्याओं और विचारों को सार्वजनिक मंच पर रखते हैं तथा समान अनुभव रखने वाले लोगों से जुड़ते हैं। इससे उन्हें जानकारी, सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं। इसलिए समस्या सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और असंतुलित इस्तेमाल में अधिक है।

आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को डिजिटल अनुशासन सिखाया जाए। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय करना एक उपयोगी कदम हो सकता है। विशेषकर सोने से पहले लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचना चाहिए। पढ़ाई, काम, परिवार और व्यक्तिगत गतिविधियों के दौरान मोबाइल से दूरी बनाना भी जरूरी है। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया उनके वास्तविक मूल्य या क्षमता का प्रमाण नहीं है। उनकी पहचान केवल पसंद और टिप्पणियों की संख्या से तय नहीं होती। माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। केवल मोबाइल छीन लेना या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना स्थायी समाधान नहीं है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

झांसी जेल से प्रयागराज लाया गया अली अहमद

प्रयागराज कोर्ट में अली अहमद की पेशी के दौरान जुटी समर्थकों की भीड़

एजेंसी, प्रयागराज

झांसी जेल में बंद अली अहमद को सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज जिला अदालत में पेश किया गया। अली अहमद को उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुनवाई के लिए झांसी से प्रयागराज लाया गया था। अदालत में पेशी के दौरान कचहरी परिसर और आसपास के इलाके में गहमागहमी का माहौल रहा। अली की पेशी की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में उसके समर्थक भी कचहरी के आसपास पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई थी। झांसी से प्रयागराज लाए जाने के दौरान भी अली के काफिले को कई स्थानों पर सुरक्षा कारणों से जांच से गुजरना पड़ा। पुलिस ने रास्ते में वाहनों की निगरानी के साथ काफिले की गतिविधियों पर भी नजर रखी।

अली को प्रयागराज लाने के दौरान कौशांबी जिले के सैनी क्षेत्र में उसके काफिले को रोका गया। बताया गया कि अली का छोटा भाई अहजम भी कार से प्रिजन वैन के पीछे चल रहा था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए अहजम की कार को रोककर उसकी तलाशी ली। इसके बाद उसे वहीं रोक दिया गया और अली के काफिले के साथ आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने काफिले की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की। इसके बाद अली को निर्धारित सुरक्षा घेरे में प्रयागराज की ओर रवाना किया गया।

प्रयागराज जिला अदालत में अली की पेशी के दौरान कचहरी परिसर के आसपास समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी। अदालत परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई। पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। कचहरी के आसपास भी पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अली को अदालत में पेश किए जाने के बाद संबंधित मुकदमे में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

अली अहमद के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में रंगदारी मांगने, अपहरण और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

पांच लाख की रंगदारी का मामला

पुलिस के अनुसार, मामले में पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने और व्यक्ति को अगवा कर उसके साथ मारपीट करने के आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में सोमवार को अली को जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले से संबंधित प्रक्रिया के बाद उसे वापस जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई। इससे पहले अली अपने छोटे भाई अबान की मौत के बाद पैरोल पर प्रयागराज आया था। उस समय भी उसके प्रिजन वैन के पीछे कई वाहन चलने की बात सामने आई थी। फतेहपुर क्षेत्र में टोल प्लाजा से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी पुलिस ने अली के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि पीछे चल रहे वाहनों ने टोल का भुगतान नहीं किया और कर्मचारियों को तेज रफ्तार वाहनों से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

ग्रीन पार्क बनेगा यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम, 55 हजार होगी दर्शक क्षमता

350 करोड़ के बजट से होगा स्टेडियम का कायाकल्प

एजेंसी, कानपुर

कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाकर 55 हजार की जाएगी। इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण और नवीनीकरण कार्य कराए जाएंगे। नई दर्शक दीर्घा को उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिह्न की धनुषाकार आकृति से प्रेरित स्वरूप दिया जाएगा। इसके साथ ही बारहसिंघा, सारस और पलाश के फूलों की आकृति भी डिजाइन में दिखाई देगी। ग्रीन पार्क देश के प्रमुख टेस्ट केंद्रों में शामिल है और इसके आधुनिकीकरण से यहां होने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मुकाबलों के दौरान दर्शकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

स्टेडियम में पूर्व खिलाड़ियों और शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली प्रमुख हस्तियों के नाम पर नई गैलरियां भी विकसित की जाएंगी। इनमें सुनील गावस्कर, गोपाल शर्मा, शशिकांत खांडेकर, राहुल सप्रू, नीतू डेविड और रीता डे जैसे पूर्व क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं। शहर में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने वाले सर पदमपत सिंहानिया के नाम पर भी गैलरी प्रस्तावित है।

स्टेडियम के आधुनिकीकरण में मैदान की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आधुनिक जल निकासी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिससे बारिश के बाद मैदान को कम समय में खेलने के लिए तैयार किया जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत करीब 15 मिनट में मैदान सुखाने की क्षमता विकसित करने की योजना है। दर्शक क्षमता, नई गैलरियों, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर मैदान व्यवस्था के साथ ग्रीन पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। इससे कानपुर की क्रिकेट पहचान को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर बनेंगी गैलरी

स्टेडियम में पूर्व खिलाड़ियों और शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली प्रमुख हस्तियों के नाम पर नई गैलरियां भी विकसित की जाएंगी। इनमें सुनील गावस्कर, गोपाल शर्मा, शशिकांत खांडेकर, राहुल सप्रू, नीतू डेविड और रीता डे जैसे पूर्व क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं।

अयोध्या में तेज हुई विकास की रफ्तार

अयोध्या में तीन माह में 30 होटल समेत 53 मानचित्रों को मिली मंजूरी

एजेंसी, अयोध्या

भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। शहर में बढ़ती निर्माण गतिविधियां और नए होटल, व्यावसायिक भवन तथा आवासीय परियोजनाएं इसकी तस्वीर को लगातार बदल रही हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण की हालिया कार्यवाही से भी विकास की इस रफ्तार का पता चलता है। पिछले तीन माह में प्राधिकरण ने 53 विभिन्न भवनों, होटलों और आवासीय भूखंडों की प्लाटिंग से जुड़े मानचित्रों को मंजूरी दी है। इनमें अकेले 30 होटल शामिल हैं। इसके अलावा एक आवासीय योजना का लेआउट भी स्वीकृत किया गया है।

मानचित्रों की स्वीकृति में होटल परियोजनाओं के साथ व्यावसायिक और आवासीय निर्माण को भी जगह मिली है। प्राधिकरण ने 16 व्यावसायिक, पांच आवासीय और एक धार्मिक स्थल के मानचित्र को भी मंजूरी दी है। इन स्वीकृतियों से अयोध्या विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ 28 लाख 74 हजार 372 रुपये की आय हुई है। प्राधिकरण के अनुसार इस स्तर पर आय होना उसके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगातार बढ़ती निर्माण गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि अयोध्या में आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं की मांग बढ़ रही है।

मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण ने समाधान दिवस की शुरुआत भी की है। चार जून से शुरू हुआ यह आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय गुरुवार को एडीए सभागार में होता है। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले समाधान दिवस में लोग अपने मानचित्रों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंच सकते हैं।

युवक ने स्कूल में घुसकर की टीचर की हत्या, फिर खुद को भी गोली से उड़ाया

एजेंसी, लखनऊ

लखीमपुर शहर के बीचोंबीच सोमवार को एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। शाहपुरा कोठी चौराहे के पास स्थित चिल्ड्रेन एकेडमी में करीब साढ़े 11 बजे 28 वर्षीय युवक ने 26 वर्षीय शिक्षिका निशात फातिमा को गोली मार दी। इसके कुछ ही क्षण बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के समय स्कूल में करीब 350 बच्चे मौजूद थे।

एक के बाद एक दो गोलियां चलने से स्कूल परिसर में चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अचानक हुई इस वारदात से बच्चे और स्कूल स्टाफ दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस युवक के स्कूल में पहुंचने, शिक्षिका को गोली मारने और इसके बाद खुद को गोली मारने के पीछे की वजहों की जांच कर रही है।

वारदात के दौरान बच्चों की मौजूदगी ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छोटे बच्चों के विद्यालय में बाहरी व्यक्ति का इस तरह प्रवेश कर जाना सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जरूरत को सामने लाता है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार युवक और शिक्षिका दोनों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्कूल और आसपास के क्षेत्र में तनाव तथा दहशत का माहौल बना हुआ है।

यूपी में बिजली संकट गहराया: सात महीने में 1912 हेल्पलाइन पर शिकायतें चार गुना बढ़ीं

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के सरकारी दावों के बीच उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों ने बिजली व्यवस्था की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पावर कॉरपोरेशन की 1912 हेल्पलाइन पर सात महीनों के भीतर बिजली से जुड़ी शिकायतों में करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सूचना का अधिकार के तहत सामने आए आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच शिकायतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। इनमें 70 प्रतिशत से अधिक शिकायतें बिजली कटौती, कम आपूर्ति और बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की हैं।

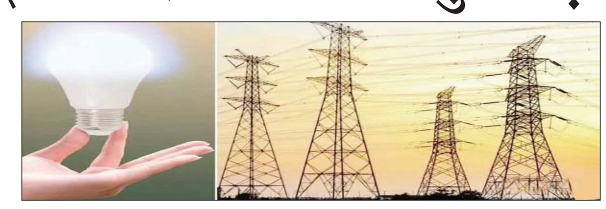

इससे संकेत मिलता है कि प्रदेश के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के दावों के बावजूद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के साथ आपूर्ति संबंधी शिकायतों में भी तेजी आई।

हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का बढ़ता आंकड़ा यह बताता है कि उपभोक्ताओं की समस्याएं केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक स्तर पर सामने आ रही हैं। बिजली कटौती के अलावा खराब आपूर्ति और तकनीकी दिक्कतों से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में दर्ज की गई हैं।

ऐसे में शिकायतों के बढ़ते आंकड़े बिजली विभाग की तैयारियों, वितरण व्यवस्था और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करते हैं। आंकड़ों के सामने आने के बाद अब यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि बिजली कटौती से जुड़ी शिकायतों के कारणों की पहचान कर उनके स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं।

यूपी की बिटिया खुशी ने ग्रैपलिंग में जीता गोल्ड मेडल

एजेंसी, लखनऊ

◆ इस्तांबुल में खुशी ने जीता भारत के लिए स्वर्ण

◆ 64 किग्रा वर्ग में खुशी ने हासिल किया स्वर्ण

शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र के छोटे से गांव अगरौली नवादा मोड़ की रहने वाली खुशी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल ग्रैपलिंग सीरीज़ में खुशी ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने ईरान की खिलाड़ी अइदा को पराजित कर शीर्ष स्थान हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली इस सफलता के बाद खुशी के परिवार और गांव में खुशी का माहौल है।

स्थानीय लोगों ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। प्रतियोगिता में खुशी का मुकाबला ईरान की अइदा से हुआ। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी ने अपनी तकनीक, संतुलन और आक्रामक खेल के दम पर मुकाबले में बढ़त बनाए रखी। लगातार दबाव बनाने के बाद खुशी ने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को ज्वाइंट लॉक में फंसा लिया।

जीत से गांव में जश्न

इसके बाद अइदा ने मैट पर टैप करते हुए मुकाबला छोड़ दिया और खुशी को विजेता घोषित किया गया। इस जीत के साथ खुशी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। गांव की बेटी की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोगों में उत्साह का माहौल है। परिजनों और परिचितों ने खुशी को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ग्रामीणों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच मेहनत और लगन से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल करना क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकी खुशी

ग्रैपलिंग में शारीरिक क्षमता के साथ तकनीक, फुर्ती, संतुलन और मानसिक एकाग्रता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करना खिलाड़ी की तैयारी और मेहनत को दर्शाता है। इस्तांबुल में मिली इस सफलता से खुशी ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, बल्कि भारतीय ग्रैपलिंग को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया।

ईरानी खिलाड़ी पर भारी पड़ी खुशी

64 किलोग्राम भार वर्ग के निर्णायक मुकाबले में खुशी ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए ईरानी खिलाड़ी पर दबाव बनाए रखा। प्रतिद्वंद्वी के संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत रखी और ज्वाइंट लॉक की तकनीक के जरिए मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। अइदा के मैट पर टैप करने के साथ ही मुकाबला समाप्त हो गया। खुशी की इस उपलब्धि के बाद क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को लेकर भी उत्साह बढ़ा है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि युवाओं को प्रशिक्षण, सुविधाएं और उचित मंच मिले तो छोटे शहरों और गांवों से भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकते हैं। खुशी की सफलता इसी संभावना का उदाहरण है। परिवार के लिए भी यह उपलब्धि विशेष है, क्योंकि उनकी बेटी ने विदेश में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। खुशी की इस सफलता से उनके गांव और शाहजहांपुर जिले में खुशी की लहर है।

ओवैसी बोले, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं

कानपुर की जनसभा में ओवैसी ने भाजपा, कांग्रेस और सपा को घेरा

एजेंसी, कानपुर

कानपुर में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। रविवार को बाबूपुरवा के बागही ईदगाह मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। करीब एक घंटे के भाषण में उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। ओवैसी ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और चुनाव के समय उनसे समर्थन लिया, लेकिन शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे सवालों पर अपेक्षित ठोस काम नहीं हुआ।

ओवैसी ने अपने संबोधन में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उनके सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े सवालों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने शिक्षा और रोजगार के अवसरों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उनके अनुसार किसी भी समुदाय की प्रगति केवल चुनाव के समय उसके वोटों की संख्या से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि उसे शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर भी मिलने चाहिए।

ओवैसी का दावा, मुद्दों पर नहीं हुआ काम

कानपुर की यह जनसभा ऐसे समय हुई है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। एआईएमआईएम भी प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। कानपुर की सभा को इसी क्रम में पार्टी की एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में देखा गया। ओवैसी ने अपने भाषण में भाजपा और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मुस्लिम समाज के सामने मौजूद मुद्दों को लेकर इन दलों की राजनीति पर सवाल उठाए और कहा कि चुनावी राजनीति में समुदाय की भागीदारी को केवल मतदाता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही संपत्ति और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे विषयों पर भी गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर पर्याप्त काम नहीं हुआ। उनके संबोधन में यह बात भी प्रमुख रही कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बिना किसी समुदाय की आवाज को सत्ता और नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से उठाना कठिन हो सकता है।

बाराबंकी में निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म के पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत

एजेंसी, बाराबंकी

बाराबंकी के कुर्सी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में तीन बालकों की डूबने से मौत हो गई। बैना गांव के बाहर निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म परिसर में मिट्टी निकालने के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा बारिश के पानी से भर गया था। शाम करीब चार बजे गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंचे और पानी में नहाने लगे। इसी दौरान गहराई में जाने से तीन बालक डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिवारों में मातम पसर गया।

मृतकों की पहचान गांव निवासी गुड्डू गौतम के 13 वर्षीय पुत्र देवा, शंकर के 10 वर्षीय पुत्र सुमित और धर्मराज के 15 वर्षीय पुत्र दिव्यांश के रूप में हुई है। बताया गया कि तीनों बालक अन्य बच्चों के साथ निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचे थे। बारिश के कारण गड्ढे में काफी पानी जमा था। बच्चे उसमें नहाने लगे, लेकिन पानी की वास्तविक गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। कुछ देर बाद तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने पानी में उतरकर देवा और सुमित को बाहर निकाला। परिवारजन दोनों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीसरे बालक दिव्यांश की भी हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिन बच्चों की आवाज कुछ समय पहले गांव में सुनाई दे रही थी, उनकी अचानक मौत से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। यह हादसा निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

खुले गड्ढे बन रहे जानलेवा

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि बारिश के मौसम में खुले गड्ढों, निर्माणाधीन भवनों और जलभराव वाले स्थानों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसियों को ऐसे स्थानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुले गड्ढे लोगों के लिए खतरा न बनें। ग्रामीणों को भी बच्चों को ऐसे स्थानों से दूर रखने के लिए जागरूक करना होगा। तीन परिवारों के लिए यह हादसा कभी न भरने वाला दुख छोड़ गया है। एक छोटी-सी लापरवाही ने तीन मासूम जिंदगियां छीन लीं। घटना केवल एक गांव की त्रासदी नहीं, बल्कि निर्माण स्थलों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी है। विकास कार्यों के साथ सुरक्षा मानकों का पालन उतना ही आवश्यक है, ताकि बारिश के पानी से भरे गड्ढे किसी परिवार के लिए हमेशा का दुख न बन जाएं।

स्वागत समारोह | नितिन नवीन के स्वागत की रही चर्चा, कहीं बुलडोजर से माला तो कहीं ढोल-नगाड़ों से अभिनंदन

मेरठ में नितिन नवीन का हुआ अनोखा स्वागत

एजेंसी, मेरठ

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मेरठ आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका अलग और खास अंदाज में स्वागत किया। काशी टोल प्लाजा पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने विशेष तैयारी की थी। यहां बुलडोजर को फूलों से सजाकर खड़ा किया गया था। जैसे ही नितिन नवीन टोल प्लाजा पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बुलडोजर से माला पहनाए जाने का यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नारेबाजी की और पार्टी के झंडे लेकर स्वागत में हिस्सा लिया।

नितिन नवीन के मेरठ पहुंचने के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर भी उनके स्वागत का सिलसिला जारी रहा। कई जगह कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। स्वागत स्थलों पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और हाथों में पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी करते नजर आए। ढोल-नगाड़ों की थाप और कार्यकर्ताओं के उत्साह से वातावरण काफी देर तक उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से नितिन नवीन का स्वागत किया और उनके आगमन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की।

मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में बुलडोजरों को खड़ा किया

काशी टोल प्लाजा पर स्वागत के लिए बुलडोजर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। नितिन नवीन के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने इसी बुलडोजर से फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद शहर में अलग-अलग स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता पहुंचे तो कहीं फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। मेरठ दौरे के दौरान नितिन नवीन का कार्यक्रम पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद से भी जुड़ा रहा। सुभारती विश्वविद्यालय में उन्होंने युवाओं के साथ सीधा संवाद किया।

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी रही और पार्टी अध्यक्ष ने उनके साथ संवाद किया। मेरठ आगमन के दौरान उनका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए अलग-अलग इंतजामों ने पूरे दौरे को खास बना दिया। शहर में कई स्थानों पर कार्यकर्ता पहले से ही उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। नितिन नवीन के काफिले के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे नजर आए। स्वागत स्थलों पर काफी देर तक उत्साह का माहौल बना रहा। काशी टोल प्लाजा पर बुलडोजर से फूलों की माला पहनाने के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ हुए स्वागत ने लोगों का ध्यान खींचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी अध्यक्ष का अभिनंदन किया और उनके मेरठ दौरे को लेकर उत्साह जताया।

यूट्यूब से सीखी ड्रैगन फ्रूट खेती, यमुनानगर में किसानों को मिल रहा 200 रुपए किलो तक भाव

एक बार पौधे लगाने के बाद करीब 20 साल तक उत्पादन, पोषक तत्वों से भरपूर फल की बढ़ी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

परंपरागत फसलों के बीच अब यमुनानगर के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। बाजार में अच्छी मांग और 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक मिल रहे भाव ने किसानों का इस विदेशी फल की खेती की तरफ रुझान बढ़ाया है। खास बात यह है कि कई किसानों ने इंटरनेट और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इसकी खेती की जानकारी हासिल कर इसे अपने खेतों में शुरू किया।

किसानों के अनुसार, ड्रैगन फ्रूट की खेती पारंपरिक फसलों से अलग है। इसकी खेती के लिए पौधों को विशेष तरीके से लगाया जाता है और उन्हें सहारा देने के लिए सीमेंट के खंभों का इस्तेमाल किया जाता है। पौधे इन खंभों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सही देखभाल और प्रबंधन के साथ पौधों से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट को पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है।

स्वास्थ्य के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में इसकी मांग भी बढ़ी है। यही वजह है कि किसानों को इसके अच्छे दाम मिलने की उम्मीद रहती है। यमुनानगर में कई किसान अब अपनी पारंपरिक फसलों के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी आजमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में इसकी कीमत 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है। हालांकि कीमत मांग, गुणवत्ता और बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। अच्छी कीमत मिलने के कारण किसानों को इस फसल से बेहतर आमदनी की संभावना दिखाई दे रही है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में सबसे पहले यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल की। खेती की तकनीक, पौधों की रोपाई, खाद-पानी और देखभाल से जुड़े वीडियो देखने के बाद किसानों ने अपने स्तर पर इसकी शुरुआत की। इसके बाद खेत में प्रयोग करते हुए खेती के तौर-तरीकों को समझा।

किसानों के लिए यह खेती इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि एक बार पौधों की रोपाई करने के बाद करीब 20 साल तक उत्पादन मिलने की बात बताई जाती है। इससे किसानों को लंबे समय तक फल उत्पादन की संभावना रहती है। हालांकि उत्पादन और आमदनी खेती की तकनीक, मौसम, पौधों की गुणवत्ता और बाजार पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र में लगातार बदलते बाजार और बढ़ती लागत के बीच किसान अब ऐसी फसलों की तलाश कर रहे हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो।

हरियाणा में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं, सरकार सख्त : जेपी दलाल

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के हर वर्ग का समर्थन है। इसमें युवा वर्ग और जेन जी भी शामिल हैं। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त है।

प्रदेश में गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा को लेकर लोगों में भरोसा कायम है और समाज के विभिन्न वर्ग पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने जेन जी का जिक्र करते हुए कहा कि युवा भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। दलाल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और मजबूत व्यवस्था चाहती है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता हासिल करने की राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुसार राहुल गांधी का ध्यान जनता के मुद्दों के बजाय सत्ता की लड़ाई पर अधिक है। हालांकि, यह जेपी दलाल का राजनीतिक आरोप है।

भिवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रति विभिन्न वर्गों के समर्थन का दावा किया। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और मजबूत कानून-व्यवस्था चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के प्रति लोगों का भरोसा कायम है और युवा वर्ग समेत समाज के विभिन्न वर्ग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं।

न्यूज ब्रीफ

रोहतक में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले के महम क्षेत्र के भराण गांव में रविवार देर रात जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव निवासी संजय (45) के रूप में हुई है। आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते उसके बड़े भाई ने संजय पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। बताया गया कि परिजनों को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। परिजन घायल संजय को उपचार के लिए पीजीआई लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रखवा दिया। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों और आरोपी की भूमिका को लेकर पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है।

रेवाड़ी अनाजमंडी गेट पर ताला लगाने पहुंचे किसान, पुलिस से हुई झड़प

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर की अनाजमंडी में सोमवार को एमएसपी पर फसल खरीद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप से जुड़े किसान अनाजमंडी के गेट पर ताला लगाने पहुंचे। मौके पर पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच करीब 15 मिनट तक झड़प हुई। इसके बाद किसान अनाजमंडी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मार्केट कमेटी की ओर से नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान धरना समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ समय बाद एसडीएम दलबीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी मांगें सुनीं और समझाने का प्रयास किया। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। प्रदर्शन के दौरान मंडी परिसर में पुलिस बल तैनात रहा।

यमुनानगर में पति-पत्नी विवाद, महिला ने संबंधों और मारपीट के लगाए आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र की एक महिला ने शादी के करीब तीन साल बाद अपने पति और ससुराल पक्ष के तीन अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से उसका पति उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता रहा है। वह उसे बार-बार तलाक देने की धमकी भी देता था। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति के उसकी बहन की भांजी से संबंध हैं। इसी बात को लेकर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। महिला का कहना है कि उसने पति के व्यवहार का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और उसे प्रताड़ित किया गया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत में उसने पति के अलावा ससुराल पक्ष के तीन अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

अकाउंटेंट से कराया 7 लाख का ट्रांसफर बैंक स्टेटमेंट से खुली साइबर ठगी

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत के अंसल सुशांत सिटी निवासी एक कपड़ा व्यापारी से सात लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि साइबर ठगों ने व्यापारी की फर्म के अकाउंटेंट के कंप्यूटर में जिप फाइल के जरिए संदिग्ध वायरस भेजा। इसके बाद ठगों ने कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर व्यापारी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फर्जी ग्रुप के जरिए अकाउंटेंट को भरोसे में लेकर अज्ञात बैंक खाते में सात लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। व्यापारी को इस लेनदेन की जानकारी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद हुई। इसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की।

गन्ने का भाव 600 रुपए करने की मांग, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर यात्रा

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले किसानों ने सोमवार को सोनीपत में ट्रैक्टर यात्रा निकाली। किसानों ने जाहरी चौक से यात्रा शुरू की, जो कामी रोड, बस स्टैंड, गीता भवन और तिरंगा चौक से होते हुए मिनी सचिवालय की ओर रवाना हुई। किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने ट्रैक्टर खड़े कर धरना देंगे।

किसान नेताओं ने बताया कि गन्ने के उचित भाव समेत अन्य मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रखा जाएगा। ट्रैक्टर यात्रा में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और

मिनी सचिवालय में धरने से पहले ट्रैक्टर यात्रा निकालते किसान

अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। यात्रा के दौरान किसान नेता वीरेंद्र पहल ने किसानों को संबोधित किया।

उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखने का आह्वान किया। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। ट्रैक्टर यात्रा के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बनी।

मंत्री की ससुराल में पंचायत का फैसला, गांव में लव मैरिज पर लगाई रोक

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा के हिसार जिले के आर्यनगर गांव में लव मैरिज को लेकर पंचायत ने फैसला लिया है। ग्रामीणों ने पंचायत कर गांव के युवक-युवतियों के आपस में प्रेम विवाह करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया। पंचायत में तय किया गया कि यदि गांव का कोई युवक या युवती आपस में लव मैरिज करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत का उद्देश्य गांव की सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं को बनाए रखना है। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और सामूहिक रूप से निर्णय लिया। पंचायत के फैसले के बाद गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्यनगर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की ससुराल का गांव बताया गया है।

हत्या केस में फंसाने की धमकी, फसल उजाड़ने से परेशान युवक ने जहर पीकर दी जान

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

सिरसा के रोड़ी थाना क्षेत्र के गांव झोरड़रोही में करीब 25 वर्षीय युवक ने खेत में स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान लवजीत सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, युवक पिछले कुछ समय से कथित तौर पर मानसिक रूप से परेशान था। मृतक के दादा बाबू सिंह ने गांव के सात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

दादा बाबू सिंह ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि संबंधित लोग लवजीत सिंह को परेशान करते थे और उसे खेत में काम नहीं करने देते थे। आरोप है कि उसकी फसल भी उजाड़ दी गई थी। इसके अलावा युवक को एक पुराने हत्या के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी। परिजनों

का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों और कथित परेशानियों के कारण लवजीत तनाव में था।

बताया गया कि लवजीत खेत में गया था। इसी दौरान उसने स्प्रे पी ली। हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक के दादा के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक को किन परिस्थितियों में यह कदम उठाना पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

एशियन गेम्स में जींद का दमदार प्रदर्शन सुमित प्री-क्वार्टर में, हिमांशु ने जीता रजत

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

आइची-नागोया एशियन गेम्स में जींद जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया है। गांव ढाकल के बॉक्सर सुमित कुंडू ने पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में अपने शुरुआती मुकाबले में थाईलैंड के बुंजोंग सिसिरी को 5-0 से हराकर राउंड ऑफ-16 यानी प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं, जींद के शूटर हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

जींद के सुमित कुंडू ने बॉक्सिंग में मारी बाजी, हिमांशु ने शूटिंग में जीता रजत पदक।

सुमित कुंडू का मुकाबला 21 सितंबर को निसियो जिम्नेजियम में हुआ। भारतीय मुक्केबाजी अभियान में उनकी जीत के बाद ढाकल गांव समेत पूरे जींद जिले में खुशी का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने सुमित की जीत पर खुशी जताई। अब सुमित की नजर अगले दौर के मुकाबले पर है। सुमित कुंडू का अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी तक पहुंचने का सफर संघर्षों से भरा रहा है। गांव ढाकल से निकलकर उन्होंने कम उम्र में ही खेलों में अपनी पहचान बनाई। सुमित ने वर्ष 2018 में नेशनल स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था।

इसके बाद 2019 के खेलो इंडिया गेम्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह मजबूत की और अब एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी ओर, शूटर हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जींद को एक और उपलब्धि दिलाई। हिमांशु के पदक जीतने से जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह है। एक ही प्रतियोगिता में जिले के दो खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से स्थानीय स्तर पर खुशी का माहौल है। एशियन गेम्स में जींद के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने जिले को खेल प्रतिभाओं को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जिले के युवाओं में भी खेलों के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। जींद के दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जिले के खेल जगत में उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले सुमित कुंडू और हिमांशु ढिल्लों ने युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। सुमित की जीत के बाद अब उनसे अगले मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं हिमांशु के रजत पदक ने जींद की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

सिरसा में मां के बाद ढाई साल की बेटी की भी मौत, दहेज हत्या का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के गांव शक्करमंदोरी में रविवार को कमरे में आग लगने से झुलसी विवाहिता कविता की मौत के बाद उसकी ढाई वर्षीय बेटी सानवी ने भी हिसार के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बच्ची आग की चपेट में आने से करीब 50 प्रतिशत झुलस गई थी। गंभीर हालत में उसे रविवार को हिसार रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए षड्यंत्र रचकर मां-बेटी को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि रविवार को कमरे में अचानक आग लगने की सूचना मिली थी। आग की चपेट में आने से कविता और उसकी बेटी सानवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं।

परिजन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। कविता की हालत गंभीर होने के कारण उसे भी उपचार दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं सानवी को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस आग लगने के कारणों के साथ-साथ घटनास्थल की परिस्थितियों और परिजनों के बयानों की भी पड़ताल कर रही है। ससुराल पक्ष पर लगाए गए दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।

उम्र को मात देकर पढ़ने निकले जयराम चंद्रो, उल्लास परीक्षा में दिखा उत्साह

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

उम्र के जिस पड़ाव पर लोग पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, वहां बीड़ गांव के 75 वर्षीय जयराम और 71 वर्षीय चंद्रो ने रविवार को परीक्षा केंद्र पहुंचकर पढ़ने-लिखने की ललक की मिसाल पेश की। दोनों ने उल्लास कार्यक्रम के पांचवें चरण के तहत आयोजित साक्षरता परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा में पढ़ने-लिखने के साथ आसान गणना से जुड़े सवाल पूछे गए।

उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाना है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर सके। परीक्षा में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। जिले में 425 निरक्षर लोगों की पहचान कर उनका पोर्टल पर पंजीकरण किया गया था। इन लोगों को साक्षर बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पढ़ाई कराई गई और इसके बाद उनकी सीखने की क्षमता जांचने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। बीड़ के जयराम और चंद्रो ने उम्र की परवाह किए

सेवा संकल्प अभियान के तहत लोगों को अंगदान के लिए किया जागरूक।

बिना परीक्षा में भाग लिया। दोनों के परीक्षा केंद्र पहुंचने से अन्य परीक्षार्थियों में भी उत्साह नजर आया। जयराम की उम्र 75 वर्ष और चंद्रो की उम्र 71 वर्ष है।

इस उम्र में पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह उन लोगों के लिए प्रेरणा बना, जो उम्र अधिक होने के कारण शिक्षा हासिल करने से पीछे हट जाते हैं। हांसी क्षेत्र में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए थे। हालांकि, दो परीक्षा केंद्रों पर ताले लगे मिले। इससे वहां पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। इसके बावजूद जिन केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, वहां परीक्षार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, साक्षरता अभियान का उद्देश्य केवल पढ़ना-लिखना सिखाना ही नहीं, बल्कि लोगों को रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए सक्षम बनाना भी है। आसान गणना की जानकारी होने से लोग दैनिक जीवन में लेन-देन और अन्य जरूरी कार्य अधिक आसानी से कर सकते हैं। जयराम और चंद्रो जैसे बुजुर्गों की भागीदारी से अभियान को प्रोत्साहन मिला है। बुजुर्गों के उत्साह से साक्षरता अभियान को मिला नया प्रोत्साहन।

तिजारा चुनाव से पहले सियासी घमासान, पंचकूला में रोके कांग्रेस पार्षद

तिजारा चुनाव से पहले पंचकूला में कांग्रेस पार्षदों को रोकने पर नेताओं ने जमकर किया हंगामा

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

तिजारा नगर परिषद के सभापति चुनाव से एक दिन पहले सियासी हलचल तेज हो गई। हिमाचल प्रदेश में बाड़ेबंदी के बाद तिजारा लौट रहे कांग्रेस पार्षदों को रविवार रात करीब नौ बजे पंचकूला टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस द्वारा पार्षदों को रोकने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। जानकारी के अनुसार, तिजारा नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्षदों को हिमाचल प्रदेश में रखा गया था। चुनाव से पहले पार्षदों की वापसी के दौरान पंचकूला टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनके वाहनों को रोक लिया।

पुलिस की कार्रवाई के बाद पार्षदों को पिंजौर पुलिस चौकी ले जाया गया। इसकी सूचना मिलने पर कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। उनका आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले पार्षदों को रोकना मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। नेताओं ने कहा कि पार्षदों को तिजारा पहुंचकर नगर परिषद सभापति के चुनाव में मतदान करना है, ऐसे में उन्हें रास्ते में रोकना

उचित नहीं है। पुलिस चौकी के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

नेताओं ने पार्षदों को तत्काल छोड़ने की मांग की। मामले को लेकर मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि पार्षदों को जानबूझकर रोका गया है ताकि वे समय पर तिजारा पहुंचकर चुनाव में हिस्सा न ले सकें। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध दर्ज कराया। हालांकि, पुलिस की ओर से पार्षदों को रोके जाने के पीछे क्या कारण था, इसे लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। तिजारा नगर परिषद के सभापति चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। चुनाव से पहले पार्षदों की बाड़ेबंदी के बाद उनकी वापसी और पंचकूला में पुलिस द्वारा रोके जाने की घटना ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्षदों को चुनाव में मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वहीं, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भी जांच और जानकारी सामने आने का इंतजार है। सभापति चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस घटनाक्रम ने तिजारा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि रोके गए कांग्रेस पार्षद कब तक तिजारा पहुंचते हैं और चुनाव की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। तिजारा नगर परिषद सभापति चुनाव से पहले कांग्रेस पार्षदों को पंचकूला में रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार रात करीब नौ बजे पंचकूला टोल प्लाजा पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से लौट रहे कांग्रेस पार्षदों के वाहनों को रोक लिया। इसके बाद पार्षदों को पिंजौर पुलिस चौकी ले जाया गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चौकी के बाहर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पार्षदों को रोककर उन्हें समय पर तिजारा पहुंचने से रोका जा रहा है। उन्होंने पार्षदों को तत्काल छोड़ने और पुलिस कार्रवाई का कारण स्पष्ट करने की मांग की। मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। चुनाव से पहले घटनाक्रम ने तिजारा की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इस घटनाक्रम के बाद तिजारा नगर परिषद सभापति चुनाव को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद और बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने पार्षदों को चुनाव में शामिल होने के लिए समय पर तिजारा पहुंचाने की मांग की है।

महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पांडु पिंडारा में कौरवों का किया पिंडदान

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

हरियाणा के जींद जिले में स्थित पांडु पिंडारा तीर्थ का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। पिंडतारक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान को पितरों के पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने भगवान श्रीकृष्ण के निर्देश पर यहां कौरवों और युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने ही परिजनों और संबंधियों की मृत्यु का दुख था। युद्ध में बड़ी संख्या में कौरव पक्ष के योद्धा और सैनिक मारे गए थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बावजूद पांडवों के मन में अपने परिजनों के प्रति शोक था।

ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें मृत योद्धाओं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक विधि से पिंडदान करने की सलाह दी। मान्यता है कि पांडवों ने इसी स्थान पर पहुंचकर कौरवों और युद्ध में मारे गए अन्य लोगों के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। इसी वजह से इस तीर्थ का संबंध महाभारत की घटनाओं से जोड़ा जाता है। स्थानीय धार्मिक परंपराओं में पांडु पिंडारा को पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। पांडु पिंडारा में वर्षभर श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक

अनुष्ठान करते हैं। विशेष रूप से अमावस्या के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। सोमवती अमावस्या को पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष महत्व वाला दिन माना जाता है। इस दिन दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग तीर्थ पर पहुंचते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पितरों का विधि-विधान से तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसी विश्वास के कारण पांडु पिंडारा लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जींद का यह तीर्थ महाभारत से जुड़ी पौराणिक कथाओं और स्थानीय धार्मिक परंपराओं के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। यहां आने वाले श्रद्धालु तीर्थ में स्नान, पूजा-अर्चना और पितरों का पिंडदान करते हैं। पांडु पिंडारा का नाम आज भी महाभारत काल से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।

नमो भारत कॉरिडोर पर दौड़ेंगी सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेनें

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर आने वाले वर्षों में ट्रेनें सौर ऊर्जा से संचालित होती दिखाई देंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक बड़े सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसे लगभग ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि प्लांट का निर्माण वर्ष 2028 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल नमो भारत कॉरिडोर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जालौन में स्थापित होने वाले सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को सीधे नमो भारत कॉरिडोर तक नहीं पहुंचाया जाएगा।

यह बिजली पहले ग्रिड में जाएगी और फिर ग्रिड के माध्यम से गाजियाबाद और दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी के रिसीविंग सब-स्टेशनों तक पहुंचाई जाएगी। इन सब-स्टेशनों से बिजली को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में वितरित किया जाएगा। इस सोलर प्लांट को एनआईआरएल एनसीआरटीसी रिन्यूएबल्स लिमिटेड विकसित करेगा। परियोजना का उद्देश्य नमो भारत कॉरिडोर की बिजली जरूरतों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। अनुमान के मुताबिक, जालौन में बनने वाले इस सोलर प्लांट से दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल बिजली आवश्यकता का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया जा सकेगा।

फिलहाल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नमो भारत कॉरिडोर के डिपो, स्टेशनों और अन्य संबंधित परिसरों में किया जाएगा। भविष्य में इस व्यवस्था का विस्तार कॉरिडोर की परिचालन जरूरतों के अनुसार किया जा सकता है। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के अनुसार, जालौन में प्रस्तावित सोलर प्लांट को वर्ष 2028 के आखिरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्लांट के तैयार होने के बाद इससे उत्पादित सौर बिजली का इस्तेमाल नमो भारत कॉरिडोर में शुरू किया जाएगा। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर देश के प्रमुख क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में शामिल है।

इस परियोजना में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल की योजना को पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा होने पर परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका बढ़ेगी। जालौन में बनने वाला सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकता है। परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद स्थित रिसीविंग सब-स्टेशनों के जरिए सौर बिजली को नमो भारत कॉरिडोर तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह आने वाले समय में दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली नमो भारत सेवाओं के संचालन में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले नितिन नवीन, संगठन मजबूती पर दिया जोर

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान सोमवार सुबह गाजियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। एनएच-9 पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।

नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को कहा। उन्होंने संगठन की मजबूती को चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण आधार बताया और कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा तथा संगठन के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का कमल निशान उसकी पहचान है और प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन के प्रति पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखने, संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया।

न्यूज ब्रीफ

500 मीटर बाइपास का होगा कायाकल्प 60 लाख रुपए से शुरू हुआ निर्माण

एजेंसी ,नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में वर्षों से जर्जर पड़े बाइपास मार्ग के निर्माण का काम रविवार से शुरू हो गया। खेड़ा देवत से सिकंदराबाद और झाझर रोड की ओर जाने वाले करीब 500 मीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क की हालत खराब होने के कारण क्षेत्रवासियों और राहगीरों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग उठाई थी। अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभाग के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। नई सड़क बनने के बाद दनकौर कस्बे में आवागमन सुगम होगा और सिकंदराबाद व झाझर रोड की ओर जाने वाले वाहन चालकों को बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा। क्षेत्रवासियों ने निर्माण शुरू होने पर खुशी जताते हुए काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने की उम्मीद व्यक्त की है।

मेरठ में 16,726 अवैध इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सील करने के निर्देश

एजेंसी, नई दिल्ली। मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) द्वारा जोन ए में चिन्हित 16,726 अवैध व्यावसायिक इमारतों को सील करने का निर्देश दिया। इन इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई है। अदालत ने जोन ए के अलावा जोन बी, सी और डी में भी ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विश्वनाथन की पीठ ने की। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को निर्धारित की गई है। हालांकि, सोमवार की सुनवाई का विस्तृत आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। आदेश उपलब्ध होने के बाद कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस फैसले से क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

प्रयागराज में वन भूमि गायब होने का मामला शासन तक पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र स्थित कोरांव के बेलहट में वन भूमि के रिकॉर्ड से गायब होने का मामला अब उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंच गया है। प्रकरण में करीब 472 बीघा वन भूमि के रिकॉर्ड से गायब होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की फाइल तहसील स्तर के अधिकारियों के पास लंबे समय से लंबित थी। अब राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने प्रयागराज के जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। मामले के शासन स्तर तक पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन में भी सक्रियता बढ़ गई है। अधिकारियों को रिकॉर्ड की जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। वन भूमि के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद संबंधित विभाग मामले की स्थिति स्पष्ट करने और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, दोपहर 12 बजे पुलिस को मिली सूचना

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी जेल में आर्म्स एक्ट के एक मामले में बंद विचाराधीन कैदी की कथित तौर पर तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन और दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना दोपहर करीब 12 बजे मिली। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में था। जेल परिसर में उस पर तेजधार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। हमले के बाद उसकी मौत हो गई। घटना किन परिस्थितियों में हुई और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा घटनास्थल और संबंधित साक्ष्यों की जांच की जा रही है। साथ ही, जेल में मौजूद कैदियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। हत्या के कारण और हमलावरों की पहचान समेत अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

फरीदाबाद में फल-सब्जियों के बढ़े दाम कम स्टॉक ने बढ़ाई चिंता

एजेंसी, नई दिल्ली। फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दामों में एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में कई फल और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, कुछ उत्पादों के दाम में मामूली गिरावट भी आई है। कारोबारियों के अनुसार, मंडी में स्टॉक कम होने के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है। डबुआ मंडी में सब्जियों और फलों की आवक तथा मांग के आधार पर रोजाना कीमतों में बदलाव हो रहा है। कुछ सब्जियों की उपलब्धता कम होने से उनके दाम बढ़ गए हैं, जबकि पर्याप्त स्टॉक वाले उत्पादों की कीमतों में मामूली कमी देखी गई है। मंडी से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि यदि आवक में सुधार नहीं हुआ और स्टॉक की कमी बनी रही तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को महंगे फल और सब्जियां खरीदनी पड़ सकती हैं। कीमतों में लगातार बदलाव का सीधा असर आम लोगों की रसोई के बजट पर पड़ रहा है।

ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचे भरत पराशर, जानिए उनका न्यायिक सफर

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट में सात नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बाद न्यायिक जगत में कई चर्चित नाम सामने आए हैं। इनमें न्यायमूर्ति भरत पराशर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह ट्रायल कोर्ट से पदोन्नत होकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। न्यायमूर्ति पराशर ने कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोयला ब्लॉक मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसी दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले में समन जारी किया था।

यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था। न्यायमूर्ति भरत पराशर ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट में संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहे। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर काम करने के कारण उन्हें हाई कोर्ट प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। बाद में उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी विशेष कार्य के रूप में भी सेवाएं दीं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले तक वह दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भरत पराशर के न्यायिक करियर में कोयला ब्लॉक मामलों की सुनवाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही है।

विशेष न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका उस समय सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य संबंधित पक्षों को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए सात नए न्यायमूर्तियों में अलग-अलग न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी शामिल हैं।

गुरुग्राम की हाईप्रोफाइल सोसायटी में मारपीट पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

एजेंसी, नई दिल्ली

जज के पति से मारपीट, तीन हिरासत

गुरुग्राम के सेक्टर-50 थाना क्षेत्र स्थित एक नामी सोसायटी में दिल्ली में कार्यरत एक महिला न्यायाधीश के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, आरोप है कि सोसायटी में किसी बात को लेकर एक युवक का न्यायाधीश के पति के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की।

घटना के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-50 थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि की जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। इसके साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना को लेकर सोसायटी के निवासियों के बीच भी चर्चा है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले घटना के कारण और आरोपों के संबंध में किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है।

नोएडा में अनोखा फैसला: सोसायटी ग्रुप में बदसलूकी करने पर 8 माह का मुचलका और 10 हजार जुर्माना

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा के सेक्टर-77 स्थित अंतरिक्ष केनबाल श्री जी सोसायटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना एक अन्य निवासी को महंगा पड़ गया। न्यायालय ने मानहानि के इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को आठ महीने तक सभ्य व्यवहार में रहने की अनूठी सजा सुनाने के साथ-साथ 25 हजार रुपये का बांड भरवाया और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जब अंतरिक्ष केनबाल सोसायटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। उस दौरान सोसायटी निवासी वीरेंद्र सिंह चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। इसी बीच सोसायटी के ही एक अन्य निवासी राजेश बजाज ने वाट्सएप समूह पर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक, अभद्र और अपमानजनक मैसेज पोस्ट कर दिए। अपनी सामाजिक छवि धूमिल होते देख पीड़ित वीरेंद्र सिंह ने सबसे पहले पुलिस प्रशासन से शिकायत की।

हालांकि, जब पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़ित ने अपने अधिवक्ता प्रिंस टाइगर के माध्यम से न्यायालय का रुख किया और आरोपी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया गया। अदालत ने जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तो आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म (सोशल मीडिया) पर छवि खराब करने और मानहानि करने का दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी राजेश बजाज को 8 महीने तक सभ्य व्यवहार बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, आरोपी से 25,000 रुपये का मुचलका (बांड) भरवाया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संयमित भाषा के इस्तेमाल को लेकर यह फैसला एक मिसाल बन गया है।

आगरा में बड़ा हादसा: नाला निर्माण के दौरान मिट्टी धंसी, दो मजदूरों की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा के सिकंदरा सब्जी मंडी के पास सोमवार को नाला निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के बगल में चल रही खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मलबे में दबे मजदूरों की पहचान 30 वर्षीय अनुज निवासी मुजफ्फरनगर, 22 वर्षीय विकास और सुशील के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने बचाव अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अनुज और विकास को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुशील की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एनटीपीसी भर्ती के 5810 पदों पर बड़ा अपडेट, लॉगिन विंडो हुई सक्रिय

एजेंसी, नई दिल्ली

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी के स्नातक स्तरीय पदों के लिए कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल सक्रिय कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5,810 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। लंबे समय से परीक्षा कार्यक्रम और चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। कैंडिडेट लॉगिन विंडो सक्रिय होने के बाद उम्मीदवार अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी देख सकते हैं।

पोर्टल पर उम्मीदवारों को परीक्षा की स्थिति, परीक्षा शहर की जानकारी यानी एग्जाम सिटी स्लिप और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने पंजीकरण से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज कर लॉगिन करना होगा। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के तहत स्नातक स्तर के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

परीक्षा से पहले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी पहले से मिल जाती है और यात्रा की तैयारी करने में सुविधा होती है। हालांकि, एग्जाम सिटी स्लिप को परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं माना जाना चाहिए।

मतदाता सूची सत्यापन में चुनाव आयुक्त संधू को भी नोटिस

नाम में विसंगति का मामला: दिल्ली वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयुक्त संधू को नोटिस जारी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली वोटर लिस्ट सुधार में चुनाव आयुक्त को नोटिस

राजधानी दिल्ली में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) और गणना प्रपत्र में नाम की विसंगतियों या लिपकीय त्रुटियों के कारण न केवल कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, बल्कि इस सूची में स्वयं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का नाम भी दर्ज किया गया है।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा साझा की गई विस्तृत जानकारी के अनुसार, दिल्ली में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत मतदाताओं द्वारा दिए गए वर्तमान डेटा और पुरानी मतदाता सूची के रिकॉर्ड्स का केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से गहन मिलान किया जा रहा है। इस डिजीटल सत्यापन की प्रक्रिया में यदि किसी मतदाता के नाम, स्पेलिंग, पिता के नाम या पते की जानकारी में कोई भी अंतर पाया जाता है, तो कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने हेतु चिन्हित कर लिया जाता है। इसी पारदर्शी व्यवस्था के कारण चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू का नाम भी इस नोटिस प्रक्रिया में शामिल हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के न्यू मोती बाग निवासी डॉ. संधू दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं।

उन्होंने अपने गणना फॉर्म में अपना नाम 'डॉ. एस. एस. संधू' भरा था, जबकि पुरानी मतदाता सूची में उनका नाम 'सुखबीर सिंह संधू' दर्ज है। नाम और अक्षरों में आए इसी सूक्ष्म अंतर को सॉफ्टवेयर ने चिन्हित कर लिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक पूरी तरह से स्वचालित, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है।

इसमें किसी राजनेता या आम नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नियमों के अनुसार, नाम में पाई गई विसंगति को सुधारने के लिए संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे। संधू द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद उनका विवरण दुरुस्त कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अभियान के तहत 97 लाख से अधिक मतदाताओं की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद लगभग 33.13 लाख से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती: शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान यूपी के बुलंदशहर निवासी सौरभ कुमार की जान गई

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में सोमवार को उस समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़ लगाते समय 23 वर्षीय एक परीक्षार्थी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की अनूपशहर तहसील अंतर्गत गांव सलामतपुर, नेतानगर निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर में दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण का आयोजन किया जा रहा था। सौरभ कुमार भी इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए अकादमी पहुंचे थे।

परीक्षण के दौरान जब वह मैदान में दौड़ लगा रहे थे, तभी अचानक ट्रैक पर ही गश्त खाकर गिर पड़े। मैदान पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और उन्हें प्राथमिक चिकित्सीय सहायता दी गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस पीसीआर वाहन के माध्यम से उन्हें अविलंब पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के उपरांत सौरभ को मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह लगभग 11:11 बजे थाना सोनिया विहार को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से आपातकालीन विभाग में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाए जाने की आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई।

सोनिया विहार थाना पुलिस की टीम सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है। मौत के वास्तविक और सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को आगे के पोस्टमार्टम प्रक्रिया हेतु गुरु तेग बहादुर अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। इस दुखद हादसे से मृतक अभ्यर्थी के परिवार में मातम छा गया है, वहीं पुलिस अकादमी परिसर में भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

न्यूज ब्रीफ

मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 18 पद अधिसूचित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश ने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-2 (जॉब ट्रेनी) के बैच आधार पर 18 पद अधिसूचित किए हैं। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इनमें सामान्य वर्ग के नौ, ईडब्ल्यूएस का एक, डब्ल्यूएफएफ का एक, अनुसूचित जाति के पांच और अनुसूचित जनजाति के दो पद शामिल हैं। निर्धारित बैच के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए दिसंबर 2012, ईडब्ल्यूएस के लिए दिसंबर 2015, डब्ल्यूएफएफ के लिए दिसंबर 2025, अनुसूचित जाति के लिए दिसंबर 2021 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए दिसंबर 2022 तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थी 12 अक्तूबर 2026 तक अपने संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाएं। पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी भी रोजगार कार्यालय से अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01978-222450 पर संपर्क किया जा सकता है।

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पढ़ाई के साथ शोध पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। नई शिक्षा नीति के तहत सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ शोध का अवसर मिलेगा। तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, जबकि चौथे वर्ष में बैचलर डिग्री ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का विकल्प दिया गया है। चौथे वर्ष के आठवें सेमेस्टर में विद्यार्थियों को शोध परियोजना या शोध प्रबंध पूरा करना होगा। चार वर्षीय कार्यक्रम में कुल 168 क्रेडिट निर्धारित हैं, जिनमें शोध परियोजना के लिए 12 क्रेडिट रखे गए हैं। शोध कार्य के लिए पीएचडी उपाधिधारक शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। बेहतर शोध को शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने, सम्मेलनों में प्रस्तुत करने और पेटेंट के लिए आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। चार वर्षीय ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री के बाद विद्यार्थियों के लिए सीधे पीएचडी में प्रवेश का रास्ता आसान होगा। करसोग कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. गुलशन महाजन ने इसे शोधपरक और नवाचार आधारित शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

एस्टोनिया की तार्तु यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए चयनित भारती सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से भौतिकी में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रा भारती का एस्टोनिया की तार्तु यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भारती को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। भारती ने वर्ष 2019 से 2022 तक राजकीय महाविद्यालय बासा से भौतिकी विषय में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वर्ष 2022 से 2024 तक राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से भौतिकी में एमएससी की शिक्षा हासिल की। अपनी मेहनत और शैक्षणिक प्रतिभा के दम पर उन्होंने विदेश में पीएचडी के लिए चयन प्राप्त किया है। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भारती की उपलब्धि जिले और प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारती शोध के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

सोलन में 24 सितंबर को सजेगी 'रहमते-ए-साईं' भजन संध्या, पुनीत खुराना देंगे प्रस्तुति

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। सोलन में पंजाबी महासभा की ओर से 24 सितंबर को ठोडो मैदान में विशाल 'रहमते-ए-साईं' साईं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम छह बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। सभा के प्रधान जतिन साहनी ने बताया कि प्रसिद्ध भजन गायक पुनीत खुराना मधुर भजनों से साईं बाबा का गुणगान करेंगे। नंगली आश्रम सरहिंद से कथावाचक एवं भजन गायक विशाल ठाकुर भी श्रद्धालुओं को धार्मिक संदेश देंगे। आयोजकों के अनुसार भजन संध्या के बाद रात नौ बजे से साईं इच्छा तक बिलासपुरी धाम के भंडारे का आयोजन होगा। पंजाबी महासभा ने शहरवासियों और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से जोड़ना है। प्रेसवार्ता में चेयरमैन मनोज साहनी, अमन सेठी और शोभित बहल मौजूद रहे।

दिव्यांग बेटी की शादी के लिए हरिजन कल्याण संस्था ने बढ़ाया मदद का हाथ

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। हरिजन कल्याण संस्था शाखा अर्की की टीम ने ग्राम पंचायत सरयांज पहुंचकर जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। पंचायत प्रधान मीरा देवी ने संस्था के पदाधिकारियों को परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवार बेहद गरीब है और शादी करने जा रही बेटी सुनने व बोलने में असमर्थ है। परिवार की स्थिति को देखते हुए संस्था और हरिजन सेवक संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आपसी सहयोग से धनराशि एकत्रित कर परिवार को सहायता देने का निर्णय लिया। संस्था सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर एकत्रित राशि बेटी के परिजनों को सौंपी और नवविवाहिता को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। इस दौरान हरिजन कल्याण संस्था अर्की के अध्यक्ष कैलाश चंद भाटिया, हरिजन सेवक संघ जिला सोलन के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग, महासचिव प्रेमचंद धीमान सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

विधवाओं के बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मिलेंगे 1,000 रुपए प्रतिमाह: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री ने की महिला व बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिला व बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग को निर्देश दिए कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और पात्र लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले 19 से 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिमाह 1,000 रुपए पॉकेट मनी प्रदान करने के निर्देश दिए। वर्तमान में इस योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को 1,000 रुपए मासिक पॉकेट मनी दी जा रही है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत प्रदेश सरकार वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर रही है तथा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 40.29 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध करवा रही है। सुक्खू ने विभाग को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के 50-50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और समृद्धि का लाभ समाज के वंचित वर्गों को भी मिलना चाहिए तथा उन्हें उनका हक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लुथान आश्रय ग्राम का काम मई 2027 तक होगा पूरा

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में नौ बाल देखभाल केंद्र/संस्थान के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय ग्राम परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधान सचिव एम सुधा देवी, सचिव सीपी वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित, ईसोमसा के निदेशक सुमित खिमटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ: निशु मोंगरा

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। 'आपका सेवक आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत एपीएमसी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेंद्र निशु मोंगरा हलेड़ खुर्द पंचायत पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया। निशु मोंगरा ने कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान किया, जबकि अन्य के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 'आपका सेवक आपके द्वार' कार्यक्रम को लोगों का सहयोग मिल रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निशु मोंगरा ने हलेड़ खुर्द में पंचायत भवन, हैंडपंप और महिला मंडल भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश और कांगड़ा जिले में कई विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांगड़ा के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिले की मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुन रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मोंगरा ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के दोबारा बनने का दावा भी किया।

सम्मान समारोह बना जनविश्वास का महाकुंभ जनता का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी: राणा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। सुजानपुर के जियाणा में आयोजित भाजपा पंचायतीराज प्रतिनिधि सम्मान समारोह की ऐतिहासिक सफलता पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन सुजानपुर मंडल और बमसन (टौणीदेवी) मंडल के अध्यक्षों सहित सभी पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रमुखों, बूथ अध्यक्षों, पन्ना प्रमुखों और दिन-रात जुटे रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक पंडाल में डटी रहीं हजारों की संख्या में देवतुल्य जनता, माताओं-बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए वे आजीवन ऋणी रहेंगे। यह कार्यक्रम उनका नहीं, बल्कि सुजानपुर-बमसन की जनता और एक-एक कार्यकर्ता का था। राजेंद्र राणा ने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही यह आयोजन जनविश्वास के महाकुंभ में बदल सका, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपनी उपस्थिति से समारोह का उद्देश्य पूरा किया। राजनीति में पद आते-जाते रहते हैं, लेकिन जनता से जो अपनेपन का रिश्ता मैंने कमाया है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वर्तमान सरकार ने सुजानपुर के सभी विकास कार्य ठप कर दिए हैं। जनता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुजानपुर के हक की लड़ाई जारी रहेगी। उटपुर में लटके आईटीआई भवन के निर्माण, क्षेत्र की बदहाल सड़कों और बंद किए गए 40 के करीब बस रूटों सहित अन्य जनसमस्याओं को लेकर 26 सितंबर को टौणीदेवी अस्पताल से तहसील तक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

चंबा कॉलेज में गूंजा शांति का संदेश

भारतेन्दु संवाददात, चंबा। राजकीय महाविद्यालय चंबा के शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की उप-प्रधानाचार्य प्रो. सपना बक्शी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. परनीता कुमारी गुरूदल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस विश्वभर में शांति, अहिंसा, सह-अस्तित्व, आपसी सम्मान और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शांति को केवल युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति तक सीमित न रखते हुए समानता, संवाद, सहिष्णुता, सहयोग और एक-दूसरे के अधिकारों के सम्मान से जोड़ने पर जोर दिया गया।

भारतेन्दु शिखर में समाचार छपते ही हरकत में आई घुड़करी पंचायत

घुड़करी पंचायत ने शुरू करवाई गांव की सफाई

खबर का असर

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। भारतेंदु समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद घुड़करी पंचायत हरकत में आई है। हाल ही में प्रकाशित खबर में पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराने के साथ-साथ पिछले कुछ माह से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मामला उठाया गया था। खबर प्रकाशित होते ही पंचायत ने गांव का दौरा कर सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सफाई अभियान शुरू करवा दिया।

घुड़करी के वार्ड नंबर नौ में सफाई व्यवस्था शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने भारतेन्दु शिखर समाचार का आभार जताया। गांव की वीणा कुमारी, रश्मि देवी, काम्या देवी और अंकित कुमार सहित अन्य लोगों ने कहा कि वे काफी समय से इन समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि समाचार प्रकाशित होने के बाद पंचायत ने तुरंत कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी गांव में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था जारी रहेगी। घुड़करी पंचायत की नवनियुक्त प्रधान राम दीक्षित ने कहा कि अब सफाई अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के प्रत्येक परिवार, चाहे वह मकान मालिक हो या किरायेदार से सफाई व्यवस्था के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे। सफाई कर्मचारी रोजाना घरों से कूड़ा एकत्र करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो वहीं, पिछले काफी समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के संबंध में प्रधान ने कहा कि इन्हें ठीक करवाने की जिम्मेदारी संबंधित लोगों की है। इस दौरान पंचायत उपप्रधान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच पर प्रशासन का जोर

सफाई कर्मियों की सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सौजन्य से जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने की। इसमें सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर आवश्यक सावधानियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने सभी संबंधित विभागों और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स, गमबूट सहित अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्य की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। राहुल कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के नियमित और सही इस्तेमाल के लिए लगातार जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सफाई कर्मचारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो सके। उन्होंने नगर परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। यदि सफाई कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जा रहा है, तो ठेकेदारों को भी कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। डीसी ने कहा कि सफाई कर्मचारी बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के कार्य न करें, क्योंकि सफाई के दौरान संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम रहता है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण मास्क, ग्लव्स, गमबूट और अन्य सुरक्षा किट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी स्थानीय निकाय को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने में वित्तीय कठिनाई हो तो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए। कर्मचारियों की सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

डीए एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी महासंघ ने तेज की कवायद

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। डीए एरियर सहित कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 32 विभागों के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रदेश महासचिव हीरा लाल वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की। डीए एरियर के भुगतान के मुद्दे पर विशेष रूप से विचार-विमर्श करते हुए आगामी रणनीति को लेकर प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से उचित मंच पर उठाने के लिए विभागों और कर्मचारी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय एवं एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने अपने-अपने विभागों से जुड़े मुद्दे भी बैठक में रखे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर उचित मंच पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर आपसी संवाद और सहमति से आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए व्यापक सहभागिता और निरंतर समन्वय जरूरी है। डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि डीए और एरियर कर्मचारियों के हितों से सीधे जुड़े विषय हैं, जिन्हें उचित एवं सकारात्मक तरीके से संबंधित स्तर पर उठाने में एकजुटता महत्वपूर्ण है। महासंघ ने कहा कि कर्मचारी हितों के मुद्दे संवाद, संगठनात्मक एकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे भी उठाए जाएंगे।

चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, भराड़ी। थाना भराड़ी पुलिस ने घर से पीतल की बल्टोही चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नसवाल स्थित एक कबाड़ की दुकान से चोरी की गई पीतल की बल्टोही भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर को थाना भराड़ी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत एफआईआर संख्या 115/2026 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने घर से पीतल की बल्टोही चोरी होने की सूचना दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा पुत्र हेम राज शर्मा, निवासी गांव पडयालग, डाकघर दधोल, तहसील घुमारवीं को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर चोरी का सामान बरामद किया गया। कबाड़ दुकान संचालक को भी जांच में शामिल कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश करने पर दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

बैंकिंग सुधार व सौर परियोजनाओं की पारदर्शिता पर अनुराग ने किया मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को जयपुर में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्ययन दौरे में भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदर्शन और पारदर्शिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

दौरे के पहले सत्र में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों पर चर्चा हुई। इसमें बैंकिंग व्यवस्था की कार्यक्षमता, जवाबदेही और सुधारों के प्रभाव से जुड़े पहलुओं को रखा गया। अपराह्न सत्र में अनुराग ठाकुर ने समिति के सदस्यों और अधिकारियों के साथ सौर पार्कों तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 13 के निष्पादन लेखा-परीक्षण पर अनौपचारिक चर्चा में भाग लिया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यक्षमता और पारदर्शिता से जुड़े विषयों की जानकारी दी।

शिमला पुलिस ने जब्त की चिट्टा तस्करों की 4.13 करोड़ की संपत्ति

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आर्थिक स्तर तक ले जाते हुए शिमला पुलिस ने एक एनडीपीएस मामले में करीब 4 करोड़ 13 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियां जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार वित्तीय जांच के दौरान सामने आया कि इन संपत्तियों के संबंध में आरोपियों और उनके सहयोगियों की कोई पर्याप्त ज्ञात एवं वैध आय का स्रोत सामने नहीं आया। उपलब्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी तथ्यों के आधार पर इन्हें नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से जुड़ी संपत्तियां माना गया और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। वर्ष 2026 में इस मामले में वित्तीय जांच अमल में लाई गई। जांच के दौरान कुल 9 आरोपियों तथा 10 एसोसिएट्स/सहयोगियों, यानी कुल 19 व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों को चिन्हित किया गया। पुलिस के अनुसार इनसे जुड़ी कुल 20 संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 4.13 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक वित्तीय जांच के दौरान इन संपत्तियों को खरीदने अथवा अर्जित करने के लिए आरोपियों व उनके सहयोगियों की पर्याप्त वैध आय का स्रोत सामने नहीं आया। वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी तथ्यों के परीक्षण के बाद पुलिस ने इन्हें Drug Proceeds से संबंधित संपत्तियां मानते हुए NDPS Act के तहत जब्ती की कार्रवाई की। शिमला पुलिस के अनुसार नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई अब केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस ने तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसका उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक आधार और वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना है।

नौतोड़ के लिए तय हो पैमाना, जरूरतमंदों को ही मिले जमीन: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से नौतोड़ भूमि के इंतजार में बैठे लोगों के लिए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उम्मीद की बात कही है। उन्होंने कहा कि नौतोड़ भूमि आवंटन के लिए स्पष्ट, समान और व्यावहारिक पैमाना होना चाहिए। जमीन उन्हीं पात्र और जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

किन्नौर में नौतोड़ को लेकर चल रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। पूरे मामले को वह गुण-दोष के आधार पर देख रहे हैं और कानूनी प्रविधानों की भी जांच की जाएगी। सोमवार को लोक भवन शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि नौतोड़ के मामले में पहले भी निरीक्षण और प्रक्रिया चली है। अब वह स्वयं भी यह देख रहे हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या व्यवस्था संभव हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं को समझने के बाद ही आगे कदम उठाया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी उनसे मुलाकात कर इस विषय को उनके समक्ष रख चुके हैं। राज्यपाल ने हिमाचल में पर्यटन की संभावनाओं को और विस्तार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है। ऐसे पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाना चाहिए, जहां अभी पर्यटकों की पहुंच कम है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर के कटरा में विकसित हुए धार्मिक पर्यटन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के अवसर पैदा हुए हैं।

नशे के बड़े तस्करों तक पहुंचना जरूरी

प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि नशे की आपूर्ति रोकने के लिए सीमा और प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ानी होगी। बाहर से हिमाचल में नशा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में अक्सर नशे का सेवन करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन आपूर्ति की पूरी श्रृंखला चलाने वाले बड़े तस्करों तक पहुंचना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती उन करीब 80 प्रतिशत युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाने की है, जो अभी इससे दूर हैं। इसके लिए कार्रवाई के साथ रोकथाम, जागरूकता और सामाजिक भागीदारी पर भी जोर देना होगा।

राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा ने चुनी हुई सरकार को गिराने का किया प्रयास: सुमन

- **दोनों को हमीरपुर का विकास रास नहीं आ रहा, बौखलाहट में लगा रहे आरोप**

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और विधायक आशीष शर्मा पर तीखा हमला बोला है।

हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि राजेंद्र राणा और उनके शिष्य आशीष शर्मा दो ऐसे लोग हैं, जिन्हें कभी भी हमीरपुर का विकास रास नहीं आया। सुमन ने कहा कि जब भी हमीरपुर को कोई बड़ा पद मिला है, ये दोनों उस व्यक्ति के विरोध में उतर आए हैं, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल हों या वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। हमीरपुर की जनता को खज्जल करने का सबसे बड़ा काम इन दोनों ने किया है। इन्होंने एक चुनी हुई सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, उसे गिराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक थे, उन्हें त्यागपत्र देने की क्या जरूरत थी? पहली बार विधायक बने और पहली बार ही सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल हो गए। क्या जनता ने उन्हें विकास के लिए भेजा था या सरकारें गिराने के लिए? भारती ने कहा कि आशीष शर्मा पैसे के घमंड में चकनाचूर हो गए हैं और हमीरपुर के व्यक्ति को छोड़कर जयराम ठाकुर के पीछे चल रहे हैं। यह वही जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हमीरपुर में एक रुपये का भी विकास नहीं करवाया और पांच साल तक जिले का रुख तक नहीं किया।

उन्होंने कहा कि पार्टी से दगा करने वाले इंद्रदत्त लखनपाल भी इनके षड्यंत्र का शिकार होकर पार्टी छोड़ गए, लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये लोग विकास विरोधी हैं और हमेशा विभीषण की भूमिका में रहते हैं। आज जब जिले के हर कोने में विकास हो रहा है तो यह आशीष शर्मा से देखा नहीं जा रहा, उन्हें सिर्फ अपनी ठेकेदारी के ठेकों की चिंता है। ठेके नहीं मिलने से बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। भारती ने कहा कि जयराम ठाकुर का पांच साल का कार्यकाल हमीरपुर के इतिहास में काला अध्याय था, जब एक-एक रुपये के फंड के लिए जिला तरसता था। जो लोग अपना घर फूंककर तमाशा देखते हैं, ये वही लोग हैं।

न्यूज ब्रीफ

चमयावल में सीएम का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। सायर उत्सव के अवसर पर अर्की पहुंचने से पूर्व ग्राम पंचायत चमयावल के लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के काफिले को रोककर उनका फूलमालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के बाद उन्हें पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना व मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायत की विभिन्न विकासात्मक जरूरतों को रखा और इनके जल्द समाधान की मांग की। इस अवसर पर अधिवक्ता भीम सिंह ठाकुर, पंचायत प्रधान भावना रघुवंशी, उपप्रधान परमिंदर ठाकुर, वार्ड सदस्य सुभद्रा कंवर, रतन सिंह कंवर, हरिराम ठाकुर, पूर्व प्रधान धर्मपाल, पूर्व पंचायत सदस्य निजानंद, प्रेम सिंह ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर, विशाल, गिरीश तथा महिला मंडल प्रधान कमला देवी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे भी रखे।

एनसीसी कैडेट्स ने की बावड़ी की सफाई

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर की एनसीसी (आर्मी विंग) के कैडेट्स ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता अभियान के तहत स्थानीय ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई की। अभियान में करीब 25 एनसीसी कैडेट्स ने श्रमदान कर बावड़ी परिसर में फैले कचरे को हटाया और स्वच्छता व जल संरक्षण का संदेश दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने कैडेट्स के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों से युवाओं में सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। एनसीसी के एएनओ कैप्टन डॉ. जय चंद ने कैडेट्स को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने प्राकृतिक जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने पर जोर दिया। अभियान के दौरान कैडेट्स ने स्थानीय लोगों से जलस्रोतों को स्वच्छ रखने तथा खुले में कचरा न फेंकने की अपील की।

नालागढ़ मत्स्य बीज फार्म में उन्नत रोहू और अमृत कतला शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने राजकीय मत्स्य बीज फार्म नालागढ़ में आनुवंशिक रूप से उन्नत सीआईएफए अमृत जयंती रोहू और अमृत कतला के प्रजनक बीज शामिल किए हैं। ये बीज आईसीएआर-केंद्रीय मीठाजल जलीय कृषि संस्थान (सीआईएफए), भुवनेश्वर से प्राप्त किए गए हैं। मत्स्य निदेशक ओम कांत ठाकुर ने बताया कि खेप में कुल 7,000 फ्राई शामिल हैं, जिनमें 4,000 अमृत जयंती रोहू और 3,000 अमृत कतला हैं। इनका आकार करीब 30 से 40 मिलीमीटर है। उन्होंने बताया कि दोनों प्रजातियों में बेहतर वृद्धि और उत्पादन क्षमता है। इन मछलियों का नालागढ़ फार्म में वैज्ञानिक परिस्थितियों में पालन-पोषण किया जाएगा। जल गुणवत्ता, आहार और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के बाद इन्हें प्रजनन योग्य ब्रूडस्टॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में इनसे गुणवत्तापूर्ण स्पॉन और फ्राई तैयार कर प्रदेश के मत्स्य किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभाग के अनुसार इससे गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता बढ़ेगी और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।

एसएससीईटी के दो छात्रों को मिला सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार

भारतेन्दु संवादाता, पठानकोट। श्री साई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एसएससीईटी) के दो छात्रों दिशा शर्मा (बीटेक सीएसई) और गर्व चौधरी (बीटेक ईसीई) ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया। दोनों छात्रों को यह सम्मान 19 सितंबर 2026 को मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमआईईटी), जम्मू में आयोजित आईएसटीई छात्र सम्मेलन-2026 में प्रदान किया गया। ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी मेहनत, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और कक्षा से बाहर की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सफलता संस्थान के लिए गर्व का विषय है और यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति एसएससीईटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर पर एमडी तृप्ता पुंज, सीएमडी कंवर तुषार पुंज, श्रीमती रिया पुंज, निदेशक रणजीत सिंह, प्राचार्य डॉ. विपिन गुप्ता, विभागाध्यक्ष, स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। संस्थान प्रबंधन ने दोनों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विद्यार्थियों की कमजोरियों व प्रतिभाओं पर चर्चा की

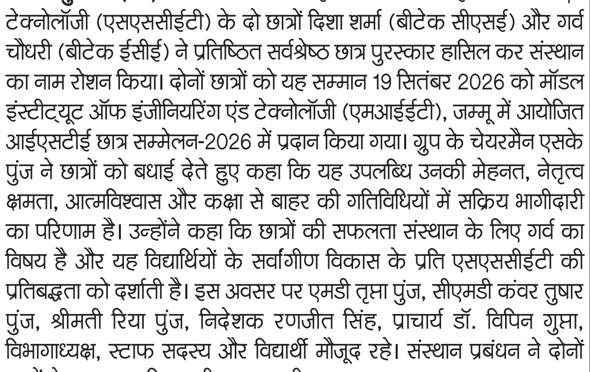

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। हिमाचल अकेडमिक स्कूल में अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अभिभावकों व शिक्षकों ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन तथा सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की। शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और उनके प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी। बैठक के दौरान विद्यार्थियों की कमजोरियों और उनकी प्रतिभाओं पर भी चर्चा की गई। शिक्षकों ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालय और परिवार के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय आवश्यक है। अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर घर में भी ध्यान देने तथा विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग करने का आग्रह किया गया। विद्यालय प्रबंधक रूप राम शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सहयोग से विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत विकास को और बेहतर बनाया जा सकता है।

नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों को करें जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बचत भवन में नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में चल रहे नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में चिट्टा सहित नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर विद्यार्थियों को नियमित जागरूक किया जाए। उन्होंने संवेदनशील और रेड जोन क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों, युवा क्लबों, महिला समूहों और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशामुक्ति केंद्रों से उपचार के बाद युवाओं के पुनर्वास पर भी जोर दिया। युवाओं को कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता बताई। अभियान के तहत अब तक जिले में 2,30,321 लोगों तक जागरूकता पहुंचाई गई है। 279 शैक्षणिक संस्थानों में गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

इंदौरा में विकास योजनाओं की समीक्षा, विभागीय समन्वय बढ़ाने पर दिया जोर

लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता से जल्द पूरा करें अधिकारी : मलेंद्र राजन

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपमंडल स्तरीय योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक ने अधिकारियों से उनके विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से लंबित कार्यों, उन्हें पूरा करने में आ रही समस्याओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मलेंद्र राजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृत योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश भी दिए। भूमि, बजट, तकनीकी स्वीकृति, विभागीय अनुमति या अन्य किसी स्तर पर समस्या आने पर संबंधित विभाग से समन्वय कर उसका शीघ्र समाधान करने को कहा। विधायक ने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी का सीधा असर लोगों पर पड़ता है। इसलिए अधिकारियों को जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को अपने कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी समिति के समक्ष रखी।

सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर लोगों तक पहुंचे

मलेंद्र राजन ने कहा कि समीक्षा बैठक का उद्देश्य केवल आंकड़ों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर लोगों तक पहुंचे। उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा। बैठक में एसडीएम इंदौरा सुरिंदर ठाकुर, डीएसपी संजीव यादव, बीडीओ सुदर्शन सिंह, डीएफओ संदीप कोहली, तहसीलदार अपूर्व शर्मा, अधिशासी अभियंता जल शक्ति देविंदर सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विनय मेहरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।

इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लाखों की चोरी का पर्दाफाश, सात गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। शाहपुरकंडी पुलिस ने सिऊंटी गांव स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में हुई लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार चोरी का मास्टरमाइंड कारोबारी का पूर्व कर्मचारी अभिषेक उर्फ गबरू निकला, जिसने नशे की लत और महंगे शौक पूरे करने के लिए साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में तीन आरोपी अभी फरार हैं। डीएसपी धारकलां राजेश कक्कड़ ने बताया कि करीब 10 दिन पहले गोदाम से लगभग 85 एसी, 42 गीजर, फ्रिज, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चोरी किया गया था। गोदाम मालिक राजेश कुमार की शिकायत पर 11 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि पूर्व कर्मचारी अभिषेक को गोदाम के रास्तों और सामान की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पांच दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान उसके साथियों के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक संदीप सिंह उर्फ माऊ, फकीर चंद उर्फ फकीरा, अमित उर्फ मीता, अभिनव उर्फ अभी, राबल शर्मा और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अभिषेक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के दो मामले भी दर्ज हैं। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। पुलिस ने 25 एसी के इनलेट-आउटलेट सेट, 10 वाशिंग मशीन, 10 फ्रिज, चार कूलर और एक गीजर बरामद किया है। वारदात में इस्तेमाल थ्री-व्हीलर ऑटो भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है। फरार तीन आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर चोरी के शेष सामान की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

विजयपुर में कैंसर जांच शिविर, 352 लोगों ने करवाया स्वास्थ्य परीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। विजयपुर स्थित चेतना संस्था में सोमवार को निशुल्क कैंसर जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 352 लोगों ने पहुंचकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीत राम कटवाल ने बतौर मुख्यातिथि शिविर में भाग लिया। शिविर का आयोजन चेतना संस्था, कृष्णा उत्कर्ष संस्थान और वर्ल्ड कैंसर केयर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा ने शिविर के आयोजन और व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में शुगर और रक्तचाप की जांच के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए टेस्ट, महिलाओं एवं पुरुषों में मुंह और रक्त कैंसर की जांच की। महिलाओं के लिए मैमोग्राफी के माध्यम से स्तन कैंसर की जांच तथा आंखों की जांच भी की गई। इसके अलावा अस्थि रोग, स्त्री रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग और सामान्य रोगों के विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। विधायक जीत राम कटवाल ने कहा कि गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को कम किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निशुल्क शिविरों को उपयोगी बताते हुए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। हरीश नड्डा ने कहा कि चेतना संस्था का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता पहुंचाना है। उन्होंने चिकित्सकों, सहयोगी संस्थाओं और शिविर में पहुंचे लोगों का आभार जताया।

अग्निवीर भर्ती रैली 26 सितंबर से हमीरपुर में

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 26 सितंबर से 6 अक्तूबर 2026 तक हमीरपुर के अणु खेल मैदान एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। भर्ती रैली में हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। निदेशक आर्मी भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने बताया कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया गया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का उच्च गुणवत्ता वाला रंगीन प्रिंट साथ लाएं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो सहित सभी आवश्यक मूल दस्तावेज व स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी।

हमले का वीडियो बनाने पर युवती से दुष्कर्म

चंडीगढ़ से पठानकोट लौटते वक्त रास्ते से उठाया; पीटा, कपड़े फाड़े, मोबाइल तोड़ा

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के थाना सदर क्षेत्र में परिवार के साथ मरपीट की एफआईआर करने की रंजिश में रविवार को 4 युवकों ने गांव की युवती के साथ गैंगरेप कर डाला। चंडीगढ़ से लौट रही युवती को आरोपियों ने रास्ते में घेरा और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया।

वारदात के दौरान आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। वे बंधक बनाकर पीड़ित युवती से कह रहे थे- तुझे बहुत सुबूत जुटाने और वीडियो बनाने का शौक है। अब वीडियो बना। वहां से बचकर युवती परिजन के साथ थाने पहुंची। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सदर पुलिस ने गांव के ही चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मनप्रीत सिंह ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपियों के साथ

दुकान के निर्माण को लेकर विवाद है। करीब 1 महीने पहले आरोपियों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया था। दुकान के निर्माण को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी 20-25 गुंडों को लेकर आए थे और उनकी पुरानी दुकानें तोड़ दी थीं। महिला ने बताया- उस दौरान आरोपियों ने मुझे, मेरे पति, बेटे और भाई के सिर पर गंभीर वार किए थे, जिससे वे लहूलुहान हो गए थे। उस खूनी झड़प के दौरान बेटी ने अपने फोन से आरोपियों की गुंडागर्दी का वीडियो बना लिया था। आरोपी इसी बात को लेकर रंजिश रख रहे थे और बेटी को निशाना बनाने की ताक में थे। पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि इस मामले में हमने पुलिस को शिकायत की थी, जिस पर आरोपियों पर एफआईआर हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की।

पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने गांव के ही रहने वाले चार युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 70(1) के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान विशाल, गगन, रंजीत और दक्ष के तौर पर हुई है। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया।

जांच महिला इंस्पेक्टर को सौंपी

एसएसपी मनप्रीत सिंह ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रुपिंदरजीत कौर को सौंपी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमों को मौके से सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया है।

हटवाड़ स्कूल को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में किया जा रहा विकसित : राजेश धर्माणी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हटवाड़ को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में करीब 8.50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि विद्यालय परिसर के समग्र विकास पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने जिला स्तरीय अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलने से उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हटवाड़ स्कूल के लिए करीब साढ़े 12 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई गई है तथा परिसर में बाउंड्री

वॉल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। पुराने भवन को गिराने के बजाय उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले के पांच जोन से 237 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। धर्माणी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता, टीम भावना और निरंतर प्रयास की भावना विकसित करते हैं। मंत्री ने प्रतिभा चयन में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण समाज और देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। खेलों के साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर छात्राओं ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया और विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंबेल सिंह, प्रधानाचार्य सुभाष चंद, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सर्व समाज के समर्थन से विधायक बने काजल सभी वर्गों को साथ लेकर चलें : मनकोटिया

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। राजपूत युवा शक्ति संघ कांगड़ा के सदस्य नरिंदर सिंह मनकोटिया ने कांगड़ा के विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल पर जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काजल तीन बार विधायक सर्व समाज के समर्थन से बने हैं, इसलिए उन्हें सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए।

मनकोटिया ने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, खत्री-बनिया, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी समाजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष जाति या वर्ग को प्राथमिकता देने की राजनीति से सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग में जाट, सैनी समेत कई समुदाय शामिल हैं और किसी एक समुदाय को पूरे ओबीसी समाज का प्रतिनिधि मानना उचित

◆ कांगड़ा की राजनीति को जातीय आधार पर बांटने से बचें

नहीं है। मनकोटिया ने सवाल उठाया कि चुनाव में सभी वर्गों के मतदाताओं का समर्थन जरूरी होता है, ऐसे में राजनीति को किसी एक जातीय समीकरण तक सीमित करना उचित नहीं है। मनकोटिया ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व से कांगड़ा में पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक नीति स्पष्ट करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों ने ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन परिणामों से स्पष्ट है कि चुनावी जीत में सभी वर्गों के मतदाताओं की भूमिका रहती है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सभी समाजों के प्रति समान नीति और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही पवन काजल से भी सर्व समाज को साथ लेकर चलने की अपील की।

राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में नीतिका ने हासिल किया तीसरा स्थान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय घुमारवीं की एमए अंग्रेजी तृतीय सत्र की छात्रा नीतिका ने राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। तीन दिवसीय 'ग्रुप-1 क्रिएटिविटी प्रतियोगिता' राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, शिमला में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेशभर के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नीतिका ने प्रभावशाली वक्तव्य, दमदार आवाज और उत्कृष्ट प्रस्तुति के दम पर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सोमवार को महाविद्यालय पहुंचने पर नीतिका का स्वागत किया गया। प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल और ग्रुप-1 क्रिएटिविटी समिति के सदस्यों ने उन्हें सम्मानित कर बधाई दी। प्राचार्य ने कहा कि पाठ्येतर गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मंजूरी एडीसी ने जिला स्तरीय बैठक में की महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा

सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 3-3 लाख

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बेसहारा बच्चों व युवाओं के लिए आरंभ की गई प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना-मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिला हमीरपुर के 41 बेसहारा युवाओं को मकान निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

9 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लगभग 7.44 लाख रुपए, 25 युवाओं की शादी के लिए 2-2 लाख और एक युवा को स्वरोजगार के लिए 1.40 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। जिला में कुल 211 बच्चों एवं युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। बेसहारा महिलाओं के 1962 बच्चों एवं युवाओं को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 92.30 लाख रुपए दिए गए हैं। सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

एडीसी अभिषेक गर्ग ने यह जानकारी दी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिला में कोई भी पात्र बेसहारा बच्चा, युवा, एकल नारी और बेसहारा बुजुर्ग इस योजना से छूटना नहीं चाहिए। एडीसी ने कहा कि जिला में कुल 1351 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह माह से 6 वर्ष तक के 14,542 बच्चों और 4081 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को विशेष पोषाहार दिया जा रहा है। इनके अलावा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 8045 बच्चे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील प्रदान किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों की सुविधा के लिए जिला में 2 क्रैच भी संचालित किए जा रहे हैं। जिला में 20,980 बच्चों की जांच के दौरान 80 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। इन बच्चों की विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए एडीसी ने कहा कि इनके पोषण के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि भोरंज ब्लॉक में पायलट आधार पर आरंभ किए गए रागी पाउडर के वितरण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। एडीसी ने आंगनबाड़ी भवनों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने डिनोटिफाई किए गए स्कूलों के भवनों को आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंपने के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल आश्रम सुजानपुर, वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण हब, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और अन्य सेवाओं की विस्तृत रिपोर्ट भी ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की लाभार्थियों को 89 लाख रुपए दिए गए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विभिन्न जागरुकता गतिविधियों पर 2.77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, विधवा पुनर्विवाह और अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर कार्यकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जिला स्तरीय समिति के अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।

समय पर आंखों की जांच से बचाई जा सकती है डायबिटीज के मरीजों की रोशनी : डॉ. संदीप महाजन

भारतेन्दु संवाददात, कांगड़ा। डायबिटीज से होने वाली आंखों की बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी की समय पर पहचान कर मरीज की दृष्टि को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

इसी उद्देश्य से एसएम आई हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में डायबिटिक रेटिनोपैथी पर सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्यातिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा पद्मश्री डॉ. उमेश भारती ने कहा कि डायबिटीज शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है और इसकी जटिलताओं की रोकथाम के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। सीएमई में एसएम आई हॉस्पिटल की रेटिना एवं विट्रियस विशेषज्ञ डॉ. अदिति पराशर व डॉ. कुमारी मुग्धा तथा टांडा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनु शर्मा ने शोध पत्र और चिकित्सकीय अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग, आधुनिक उपचार, जटिल मामलों के प्रबंधन और रेटिना सर्जरी की भूमिका पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने बताया कि बीमारी के शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, इसलिए मधुमेह मरीजों को नियमित रेटिना जांच करवानी चाहिए। समय पर पहचान होने पर इंजेक्शन, लेजर और सर्जरी जैसी उपचार विधियों से दृष्टि बचाने की संभावना बढ़ जाती है। एसएम आई हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं संस्थापक डॉ. संदीप महाजन ने कहा कि प्रत्येक डायबिटीज मरीज को आंखों की नियमित जांच को उपचार का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अन्निमारी का स्टाइल सबसे अलग

अन्निमारी कोर्ते फिनलैंड की प्रमुख 100 मीटर बाधा दौड़ एथलीट हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी तेज गति, तकनीक और बाधाओं को पार करने की क्षमता उन्हें एक प्रतिभाशाली धाविका बनाती है।

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया

यशबर्धन के शतक की बदौलत बनाए 341 रन, ऑस्ट्रेलिया 238 रन पर ढेर

एजेंसी, नई दिल्ली

यशबर्धन चौहान के शानदार शतक के दम पर इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को हरा दिया है। टीम इंडिया ने चौहान की शतकीय पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 341 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस विशाल स्कोर को हासिल नहीं कर सकी और उन्हें लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में भी भारत ने सात रनों से जीत हासिल की थी और अब दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है।

तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी। 342 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उन्होंने सात रनों के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया, जबकि 29 रन पर दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद 72 रनों के स्कोर पर उन्होंने तीसरा विकेट गंवाया। हालांकि, फिर कप्तान जैक जोसनेक और ब्लेक कैटल ने मोर्चा संभाला। जैक ने 63 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली, जबकि ब्लेक 44 रन बनाकर आउट हो गए और अर्धशतक लगाने से चूक गए। टीम इंडिया के लिए चिगुरुपति वेंकट सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने तीन विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.1 ओवरों में 238 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ टीम इंडिया ने मैच को 103 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

वीके विनीत ने खेली 87 रन की अहम पारी

भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद आर्यवीर सहवाग और वीके विनीत ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी हुई लेकिन सहवाग 47 रन बनाकर रन आउट हो गए। विनीत ने 87 रनों की की अहम पारी खेली।

चेस ओलंपियाड में भारत की नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत

एजेंसी, समरकंद

समरकंद में चल रहे 46वें चेस ओलंपियाड के 5वें राउंड में भारतीय मेंस टीम ने नीदरलैंड्स को 3-1 से हरा दिया। बोर्ड-1 पर आर प्रज्ञानानंद ने नीदरलैंड्स के नंबर-1 खिलाड़ी अनीश गिरी को हराया, जबकि वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने भी जीत दर्ज की। अर्जुन एरिगैसी और निहाल सरीन के मुकाबले ड्रॉ रहे। इस जीत के साथ भारत 10 मैच पॉइंट के साथ उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर है।

बोर्ड-4 पर डी गुकेश ने नीदरलैंड्स के एरविन लामी को हराया। गुकेश की यह टूर्नामेंट में पांच मैचों में चौथी जीत है और उनके 4.5 अंक हो गए हैं।

प्रज्ञानानंद ने गिरी की जीत का सिलसिला रोका

प्रज्ञानानंद और अनीश गिरी का मुकाबला करीब 5 घंटे चला। गिरी इससे पहले अपने चारों मुकाबले जीत चुके थे। प्रज्ञानानंद को गिरी ने ड्रॉ का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और मुकाबला जारी रखा। आखिरकार प्रज्ञानानंद ने जीत दर्ज कर गिरी की विजयी लय रोक दी।

महिला टीम पोलैंड से 1-5, 2-5 से हारी

विमेंस में डिफेंडिंग चैंपियन भारत को पोलैंड से 1-5,2-5 से हार मिली। आर वैशाली को अलेक्जेंड्रा माल्त्सेवस्काया ने हराया। कोनेरू हंपी और दिव्या देशमुख के मुकाबले ड्रॉ रहे। वंतिका अग्रवाल ने भी अपना मैच ड्रॉ खेला। पोलैंड के खिलाफ भारत की यह लगातार तीसरी ओलंपियाड हार है।

स्पोर्ट्स विंडो

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 1 विकेट से हराया जोश इंग्लिस का शतक

एजेंसी, हरारे। ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी वनडे 1 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से स्वीप कर लिया है। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर 272 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो जोश इंग्लिस और नाथन एलिस रहे। इंग्लिस ने 102 गेंदों पर 103 रन बनाए। एलिस 36 रन बनाकर नाबाद रहे और गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने गेंद वेस्ली मदहेवेरे को दी। एलिस ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया। अब 5 गेंद पर 3 रन चाहिए थे। एलिस ने दो सिंगल लेकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी विकेट के लिए एलिस और स्पेंसर जॉनसन ने 27 रन जोड़े। इससे पहले एडम जम्पा 9वें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। जिम्बाब्वे के पास मैच जीतने का मौका था, लेकिन मदहेवेरे ने एलिस का कैच छोड़ दिया। एलिस और जॉनसन ने आखिरी विकेट पर 27 रन जोड़कर मैच जिम्बाब्वे से छीन लिया।

रोहित शर्मा ने पत्नी रितिका के साथ गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद

एजेंसी, मुंबई। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा रविवार को मुंबई में लालबागचा राजा गणपति पंडाल पहुंचे। उन्होंने पत्नी रितिका सजदेह के साथ गणपति बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। रोहित गणेशोत्सव के दौरान पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। रोहित को इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा। रोहित शर्मा ने अपना पिछला मैच जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेला था। सीरीज के तीसरे वनडे में उन्होंने लॉर्ड्स पर 110 गेंदों में 138 रन की पारी खेली थी। रोहित की जगह को लेकर इंग्लैंड दौरे के दौरान चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उन्हें टीम में बनाए रखा है।

करण इंडियन सुपर लीग के सीईओ

एजेंसी, मुंबई। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) ने सोमवार को जेएसडब्ल्यू स्पोटर्स के मुख्य व्यावसायिक अधिकारी करण यादव को सीईओ नियुक्त किया जो क्लबों की अगुवाई वाले नये मॉडल में लीग का नेतृत्व करेंगे। सीईओ के तौर पर यादव लीग ऑफिस और आईएसएल की रणनीतिक, व्यावसायिक और संगठनात्मक दिशा का नेतृत्व करेंगे और इसके क्लबों और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ मिलकर काम करेंगे। यादव ने आईएसएल द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा ,'आईएसएल नये अहम अध्याय की ओर बढ रहा है और मुझे खुशी है कि भविष्य को दिशा देने का मौका मिला है । क्लब की अगुवाई वाले मॉडल में हमें क्लबों और आईएसएल की प्रबंधन समिति के साथ मिलकर लीग और भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने का मौका मिलेगा।'

टेबल टेनिस में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से दी मात

एजेंसी, नागोया

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दमदार शुरुआत करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की। सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने अपने-अपने मुकाबले सीधे गेम में जीतकर भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। पहले मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी का सामना पाकिस्तान की अलीना खान से हुआ। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और अलीना को दबाव में रखा। सुतीर्था ने पहला गेम 11-3 से अपने नाम किया।

दूसरे मैच में सिंड्रेला ने बढ़ाई भारत की बढ़त: दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने पाकिस्तान की कुलसूम खान का सामना किया। भारतीय युवा खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुलसूम पर दबाव बनाए रखा। सिंड्रेला ने पहला गेम 11-6 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने 11-7 से बाजी मारी। तीसरे गेम में भी सिंड्रेला ने अपना दबदबा कायम रखा और 11-5 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली।

अकुला ने दिलाई जीत

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का तीसरा मैच श्रीजा अकुला और फातिमा खान के बीच हुआ। श्रीजा ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और पाकिस्तान की खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिए। श्रीजा ने पहला गेम 11-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी उन्होंने 11-4 से बाजी मारी। तीसरे गेम में श्रीजा ने 11-5 से जीत दर्ज कर भारत को 3-0 से शानदार जीत दिला दी।

एशियन गेम्स: हॉकी में भारत की लगातार दूसरी जीत

महिला टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, दीपिका-रुतुजा ने 3-3 गोल किए

एजेंसी, काकामिगाहारा

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में इंडोनेशिया को 17-1 से हराया। काकामिगाहारा में पूल-बी के मुकाबले में दीपिका सेहरावत, रुतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने 3-3 गोल किए। भारत की यह लगातार दूसरी जीत है। दीपिका ने 8वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत का खाता खोला। इसके बाद सुनेलिता टोप्पो, लालरेमसियामी और रुतुजा ने गोल किए। दूसरे क्वार्टर में लालरेमसियामी, रुतुजा, साक्षी राणा, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए। हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। इंडोनेशिया के लिए इनेस अदियाता ने 32वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इसके बाद सलीमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका, रुतुजा और दीपिका ने गोल कर तीसरे क्वार्टर तक भारत की बढ़त 14-1 कर दी। आखिरी क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में गोल किए। साक्षी राणा ने भी 57वें मिनट में गोल कर भारत की जीत 17-1 कर दी।

दीपिका का लगातार दूसरा शानदार प्रदर्शन

उज्बेकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 8 गोल करने वाली दीपिका ने इंडोनेशिया के खिलाफ 3 गोल किए। वह अब दो मैचों में 11 गोल कर चुकी हैं। भारत का अगला मुकाबला बुधवार को थाईलैंड से होगा। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली टीम को 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन मिलेगा।

सविता पूनिया 321 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी

भारतीय हॉकी की दीवार कही जाने वाली गोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत के लिये सबसे ज्यादा 321 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड तोड़ा। सविता ने यह उपलब्धि एशियाई खेलों में पूल बी में इंडोनेशिया के खिलाफ दूसरे मैच में हासिल की जिसमें भारत 17 . 1 से विजयी रहा। हॉकी इंडिया ने इस उपलब्धि पर उनके लिये दस लाख रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। पूर्व कप्तान और तीन बार एफआईएच की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (2020, 2021, 2023) चुनी जा चुकी सविता ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया था और अब तक तीन ओलंपिक , तीन विश्व कप और दो एशियाई खेलों में भाग ले चुकी हैं ।

न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से होगा लागू

एजेंसी, नई दिल्ली

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को घोषणा की कि न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 20 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। मंत्रालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड दोनों के हित में है। दोनों देशों ने इस समझौते पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे, जबकि न्यूजीलैंड की संसद ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दे दी। गोयल के अनुसार समझौते को लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग और कारोबारी जगत से समझौते के प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

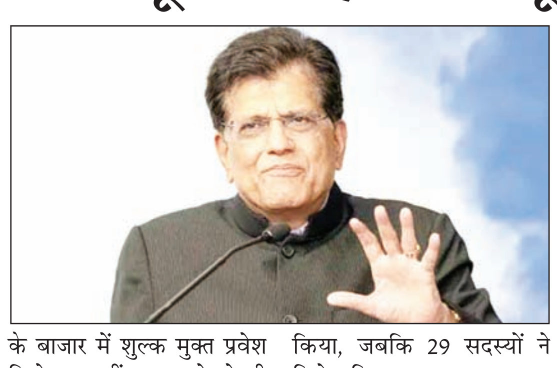

समझौते के तहत भारत के शत प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। वहीं भारत ने डेयरी सहित घरेलू किसानों से जुड़े कई संवेदनशील कृषि उत्पादों पर न्यूजीलैंड को शुल्क संबंधी रियायत नहीं दी है। इनमें मक्का, प्याज, चना, फलियां, चीनी और शहद जैसे उत्पाद शामिल हैं। गोयल ने कहा कि समझौते को दोनों देशों में व्यापक समर्थन मिला है। न्यूजीलैंड की संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के 93 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 29 सदस्यों ने विरोध किया।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि समझौते से न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पादों को उन देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, जिनका न्यूजीलैंड के साथ पहले से व्यापार समझौता है। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड ने समझौते के तहत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

हैदराबाद में लिफ्ट और दीवार के बीच फंसा शख्स

एजेंसी, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद के मूसेपेट में एक शख्स लिफ्ट से बाहर निकलते समय हादसे का शिकार हो गया। लिफ्ट अचानक ऊपर चली गई, जिससे उसका पैर ग्रिल में फंस गया और वह सेकेंड और थर्ड फ्लोर के बीच लटक गया। रेस्क्यू टीम ने करीब 90 मिनट की मशक्कत के बाद शख्स को बाहर निकाला। उसे बचाने के लिए लिफ्ट की दीवार का हिस्सा तोड़ना पड़ा और हाइड्रोलिक कटर की मदद ली गई। हादसे में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। पिछले 5 महीनों में हैदराबाद में लिफ्ट हादसे का यह तीसरा मामला बै। इससे पहले जून में उप्पल स्काईवॉक की लिफ्ट में एक युवक करीब 2 घंटे फंसा रहा था। वहीं मई में गच्चीबौली इलाके में 5 साल की बच्ची की ग्रिल वाली लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई थी।

प्याज 3 महीने में 82 प्रतिशत महंगा

महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्याज की सप्लाई में आई कमी

एजेंसी, नई दिल्ली

देश में प्याज की कीमतें तेजी से उछलीं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून को प्याज का औसत खुदरा भाव 29.50 रुपए प्रति किलो था।

17 सितंबर को यह बढ़कर 53.78 रुपए प्रति किलो हो गया। यानी करीब साढ़े तीन महीने में ही प्याज की कीमतों में 82.3% की भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई। थोक बाजारों में तेजी और भी ज्यादा रही। 1 जून को थोक बाजार में प्याज का औसत भाव 22.60 रुपए किलो था।

10 सितंबर को यह 46.20 रु. हो गया, फिर 17 सितंबर को 45.68 रु. दर्ज किया गया। जून के मुकाबले प्याज के थोक भाव करीब दोगुने हो गए हैं। महाराष्ट्र में गर्मियों की फसल खराब होने और आवक घटने से कीमतें बढ़ी हैं। कर्नाटक से भी सप्लाई कम हुई है। नई खरीफ फसल की आवक में देरी से भी बाजार में प्याज की कमी बनी हुई है। हालांकि, जल्द ही कीमतें कम होने की उम्मीद है।

दाम घटाने के सरकार उठा रही कदम

बफर स्टॉक से राहतः सरकार सस्ते में खरीदा प्याज जमा रखती है और दाम बढ़ते ही इसे 35 रुपए किलो जैसी सस्ती दरों पर बाजार में उतार देती है, ताकि आम जनता को राहत मिले।

एक्सपोर्ट पर रोकः देश में किल्लत होने पर सरकार प्याज के निर्यात पर टैक्स या रोक लगाती है, जिससे देश के अंदर प्याज की कमी न हो।

हैदराबाद बना माइक्रोसॉफ्ट का एआई हब

एआई वर्कलोड के लिए तैयार हुआ माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद डेटा सेंटर

एजेंसी, नई दिल्ली

अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने डेटा सेंटर रीजन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के लिए तैयार करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को आयोजित माइक्रोसॉफ्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में बताया कि हैदराबाद स्थित नया इंडिया साउथ सेंट्रल डेटा सेंटर रीजन एशिया और ग्लोबल साउथ के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार भारत में उसके डेटा सेंटर रीजन अब एआई-सक्षम हार्डवेयर, उच्च दक्षता वाली शीतलन व्यवस्था और उन्नत एआई कार्यभार को संचालित करने के लिए आवश्यक मंच से लैस हैं।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने बताया कि हैदराबाद में शुरू किया गया नया डेटा सेंटर तीन जोन वाली मजबूत संरचना पर आधारित है और भविष्य में इसकी क्षमता का विस्तार किया जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से इस क्षेत्र में अतिरिक्त एज्योर और एआई सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना भी है।

इन सेवाओं के उपलब्ध होने के बाद पात्र संगठन सुरक्षा, अनुपालन और सरकारी नियमों के अनुरूप संवेदनशील कार्यभार संचालित कर सकेंगे। कंपनी ने भारत में 20.5 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। नया डेटा सेंटर इसी निवेश योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अडानी समूह, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और पीबी पे समेत कई प्रमुख कंपनियों तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के संगठनों ने इस नए क्षेत्र के लिए समझौते किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत की महत्वाकांक्षा एआई के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनने की है।

एआई क्षमता बढ़ाने में नया क्लाउड क्षेत्र अहम

चंडोक ने बताया कि इंडिया साउथ सेंट्रल भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड रीजन है, जिसे उन्नत एआई कार्यभार के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल कंप्यूटिंग क्षमता किसी देश को एआई के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और सरकारी नियमों के अनुरूप बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार नए क्षेत्र में शीतलन के लिए पानी के इस्तेमाल को प्रभावी रूप से शून्य रखने वाली व्यवस्था भी महत्वपूर्ण विशेषता है।

शेयर मार्केट निफ्टी में 68 अंक की बढ़त, 23,414 पर बंद

सेंसेक्स 564 अंक उछलकर 74,859 पर बंद

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में 21 सितंबर को बढ़त रही। सेंसेक्स 564.03 अंक बढ़कर 74,858.99 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 67.90 अंक की वृद्धि के साथ 23,414.30 के स्तर पर पहुंच गया। हालिया नुकसान के बाद खरीदारी बढ़ने से बाजार को सहारा मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और प्राथमिक बाजार की बढ़ी हुई गतिविधियां लाभ को सीमित कर रही थीं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रीय सूचकांकों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी आईटी क्षेत्र में मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी फार्मा सबसे अधिक लाभ में रहा, जिसके बाद एफएमसीजी क्षेत्र का स्थान था। आईटीसी और सन फार्मा के शेयरों में 2 फीसदी की वृद्धि हुई। मध्य पूर्व और रूस-यूक्रेन युद्ध में संघर्ष बढ़ने के बावजूद ब्रेंट कच्चा तेल 102 डॉलर से नीचे आ गया। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से तेल के बढ़ते प्रवाह के कारण हुआ।

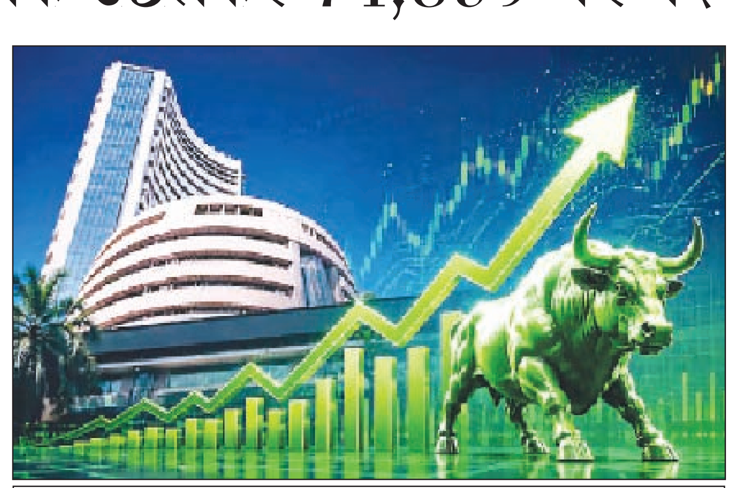

वैश्विक बाजारों में भी रहा मजबूती का रुख

वैश्विक बाजारों में भी मजबूती का रुख देखा गया। लंदन समय अनुसार सुबह 9:47 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.9 फीसदी की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 वायदा 0.7 फीसदी ऊपर चढ़ा। नैस्डैक 100 वायदा में 1.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा भी 0.7 फीसदी बढ़ा।

सोना 671 और चांदी 2,346 रुपए सस्ती

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने-चांदी के दाम में 21 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 671 रुपए घटकर 1.53 लाख रुपए पर आ गया है। एक किलो चांदी की कीमत 2,346 रुपए कम होकर 2.35 लाख रुपए पर आ गई है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 20 हजार रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.35 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था। कोटक सिक्युरिटीज के सीनियर वीपी एंड कमोडिटी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी कहते हैं कि सोने को आम निवेशकों के साथ ही दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों जैसे आरबीआई का भी सपोर्ट हासिल है, जो लगातार सोना खरीद रहे हैं। आगे मुश्किल हालात में भी सोने में तेजी बनी रहेगी।